EDU TERIA

E - D.N.A

Daily Newspaper Analysis

Prelims | Mains | Essay

By- Nikhil Ranjan

Useful For Prelims

Date: 14 December 2025

सन् 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध से पहले सगत सिंह ने दिसंबर 1962 में गति और अप्रत्याशितता का इस्तेमाल कर गोवा भी फतह किया था। वह भारतीय इतिहास में अनूठे जनरल हैं, जो तीन अलग-अलग विदेशी फौजों से लड़े और हर बार जीत हासिल की। इसके बावजूद उन्हें वह ख्याति नहीं मिली और सम्मान नहीं दिया गया, जिसके वह हकदार थे।

आजकल स्तंभ के तहत प्रकाशित आलेखों के लिए

महाविजय के गुमनाम नायक

शशि शेखर

आजकल

महज दो दिन बाद हम 54वां विजय दिवस मनाएंगे। बताने की जरूरत नहीं कि 16 दिसंबर को ढाका में हजारों पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष हथियार डाल दिए थे। इसी दिन बांग्लादेश का उदय हुआ और पाकिस्तान का सदा-सर्वदा के लिए विखंडन।

यह सिर्फ दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का उदय भर नहीं था, बल्कि जिन्ना के द्वि-राष्ट्रवाद की भी धज्जियां सिर्फ 24 वर्षों के अदना अंतराल में उड़ गई थीं। इसी के साथ तय हो गया था कि धर्म किसी देश के विभाजन का आधार तो बन सकता है, परंतु उसके स्थायित्व की गारंटी नहीं।

इस महान सैन्य उपलब्धि के लिए आप किसे याद करना चाहेंगे? जनरल सैम मानेकशॉ, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, लेफ्टिनेंट जनरल जेएफआर जैकब या तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को? उस समय देश के रक्षा मंत्री कौन थे? भारतीय थल सेना का वह जनरल कौन था, जिसने सैन्य मुख्यालय के हुक्म को नजरअंदाज कर पाक कमांडर जनरल एएके नियाजी को इतनी जल्दी हथियार डालने पर विवश कर दिया था? गुमनाम गाथाओं और उन्हें गढ़ने वाली शख्सियतों की यह शृंखला इतिहास की अबूझ त्रासदी को उजागर करती है।

पुरानी कहावत है, काल-गाथाएं वही दर्ज करती हैं, जो उनको दिखाया जाता है।

इतिहास की इस रतौंधी के चलते तमाम गौरव-गाथाएं काल की तहों में दबती चली जाती हैं। यहां मैं आदरपूर्वक लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह को याद करना चाहूंगा। सगत सिंह न होते, तो यकीनन यह युद्ध लंबा खिंच जाता, लेकिन अफसोस, बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। वजह? उन्होंने नाम के बजाय हमेशा काम को तरजीह दी।

जानने वाले जानते हैं कि भारतीय सैन्य नेतृत्व ने तब पूर्वी पाकिस्तान के मोर्चे पर जूझ रही भारतीय सेना को चार कोर सेक्टर में बांटा था। जनरल सगत सिंह चौथी कोर के कमांडर थे। उन्हें पूर्वी पाकिस्तान में भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों से लगी सीमा से प्रवेश करने का काम सौंपा गया था। इस जिम्मेदारी का निर्वाह बेहद मुश्किल था। रास्ते में दर्जनों नदियां, जंगल, दलदल और ऊबड़-खाबड़ इलाके थे। अखौरा, भवानीपुर और मेमन सिंह जैसे शहरों से सेना को गुजरना था। वहां जनरल नियाजी ने जबरदस्त किलेबंदी कर रखी थी, ताकि हिन्दुस्तानी फौज को लंबे समय तक वहीं उलझाया जा सके। नियाजी ने प्राकृतिक अवरोधों को अपनी ताकत मानते हुए वहां यथास्थिति को तरजीह दी थी। यह उनकी बड़ी भूल साबित हुई। वह भूल गए थे कि जनरल सगत सिंह बेहद तेज गति और अप्रत्याशित अचरजों के लिए जाने जाते हैं।

सगत सिंह ने पाकिस्तानी लामबंदी को बाईपास करने की रणनीति अपनाई। उनका आदेश स्पष्ट था, 'किलेबंदी को नजरअंदाज करो, उन्हें मुस्तैदी से घेरो और तेजी से ढाका की ओर बढ़ो।'

इस रणनीति के तहत उनके दस्ते मुख्य शहरों के बजाय नदी-नालों को लांघते हुए दुर्गम पगडंडियों के सहारे शत्रु क्षेत्र में घुसते चले गए। जब तक पाकिस्तानी फौज का नेतृत्व इस तथ्य को समझ पाता, तब तक देर हो चुकी थी। भारतीय सैनिक चारों ओर से अंदर धंसते चले आ रहे थे और देखते-देखते वे मेघना नदी के किनारे जा पहुंचे। यह नदी अपनी गहराई और विशालता के लिए मशहूर है। जनरल सिंह को आदेश था कि वह मेघना न पार करें, लेकिन युद्धक्षेत्र में उन्हें रोक पाना इंसानी बूते से बाहर की बात थी।

'ऑपरेशन मेघना' में भाग लेने वाले स्क्वाड्रन लीडर पुष्प वेद और मेजर चंद्रकांत सिंह ने अपनी किताबों- *एमआई-4एस एट वार* और *मेघना* में इसका विस्तार से वर्णन किया है। सगत सिंह ने अपने साथियों से कहा कि अगर हम मेघना पर पुल बनाएंगे, तो इसमें हफ्तों लग सकते हैं। क्यों न हम

हेलीकॉप्टरों से अपने फौजी दुश्मन के पीछे उतार दें। यह काम आसान न था। इसके लिए न तो आलाकमान की मंजूरी थी और फिर खतरे भी बहुत थे। हेलीकॉप्टरों में भारी साजो-सामान और सैनिक लादकर ले जाना जोखिम भरा था। वे नीचे मुस्तैद दुश्मन के निशाने पर भी आ सकते थे।

उनकी वीरता, शौर्य और हर हाल में युद्ध जीतने की ललक का यह अद्भुत उदाहरण है।

इसके लिए उनके साथियों ने क्या-क्या जतन किए? हेलीकॉप्टरों की सीटें निकाल दी गई थीं, ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान लादे जा सकें। उसी सैन्य सामग्री के ऊपर हमारे जवान यह चिंता किए बिना कि सीट बेल्ट और खिड़कियों के अभाव में वे नीचे गिर सकते हैं, बैठ जाते। कई बार पाकिस्तानी फौजों की गोलियां हेलीकॉप्टरों से टकरातीं। एक हेलीकॉप्टर में तो 38 गोलियां लगीं, इसके बावजूद वे उड़ान भरते रहे। एक आता, तो दूसरा उड़ लेता। इस बीच इंजीनियर उसे दुरुस्त करने में जुट पड़ते और पायलट को नहाने, खाने और सुस्ताने का मौका मिल जाता।

देखते-देखते छह हजार सैनिकों का बड़ा जत्था मेघना पार कर ढाका की ओर बढ़ चला था। वे ढाका पहुंचने ही वाले थे कि सगत सिंह को आदेश मिला, लौट आइए। सगत सिंह का जवाब था- ऐसा सिर्फ मेरी मृत देह पर संभव है। यह जवाब सैन्य नियमों की अवहेलना भले हो, पर एक सैनिक की मर्यादा का चरमोत्कर्ष था।

उधर पाकिस्तानी खेमे में हलचल मच चुकी थी। भारतीय दस्ते की विशालता और मारक क्षमता को लेकर अतिरंजित जानकारियां फिजां में थीं। नियाजी को जैसे ही लगा कि हम दोनों ओर से घिर गए हैं, उन्होंने हथियार डाल दिए। सगत सिंह के बिना यह संभव न था। इससे भारतीय सेना और भारतीयों का मनोबल आसमान पर जा पहुंचा था। हालांकि, सगत सिंह का यह पहला कारनामा न था। वह इससे पहले नाथू ला में चीनियों का मानमर्दन कर चुके थे।

हमें मालूम है कि 1962 में चीन से शर्मनाक हार के बाद भारतीय सेना हताशा का शिकार हो गई थी। उसी दौर में सगत सिंह वहां कमांडर बनकर पहुंचे थे। उन्हें जानकारी मिली कि चीनी सैनिक कभी भी सीमाएं लांघ सकते हैं और उन्होंने पर्याप्त मात्रा में सैनिकों की तैनाती वहां कर दी। झड़प के आसार बनते ही तोपखाने को भी आगे बढ़ने का हुक्म दिया गया। उन दिनों तोपखाने की रवानगी से पहले सर्वोच्च स्तर से आज्ञा लेनी पड़ती थी, पर उन्होंने इसका इंतजार नहीं किया।

यही वजह है कि जब झड़प हुई, तो भारतीयों के मुकाबले तीन से चार गुना चीनी सैनिक मारे गए। यह वह लम्हा था, जिसने सेना और सरकार, दोनों को आत्मविश्वास प्रदान किया कि हम मजबूत से मजबूत सेना को हरा सकते हैं। इससे पहले सगत सिंह ने दिसंबर 1962 में गति और अप्रत्याशितता का इस्तेमाल कर गोवा भी फतह किया था। वह भारतीय इतिहास में अनूठे जनरल हैं, जो तीन अलग-अलग विदेशी फौजों से लड़े और हर बार जीत हासिल की।

इसके बावजूद उन्हें वह ख्याति नहीं मिली और सम्मान नहीं दिया गया, जिसके वह हकदार थे। देशहित में की गई जिद उन पर भारी साबित हुई, लेकिन जगजीवन राम का क्या दोष था? वह उस दौरान देश के रक्षा मंत्री थे। उनके हिस्से में भी गुमनामी आई। क्यों?

@shekharkahin

@shashishekhar.journalist

Hindustan Page No-10

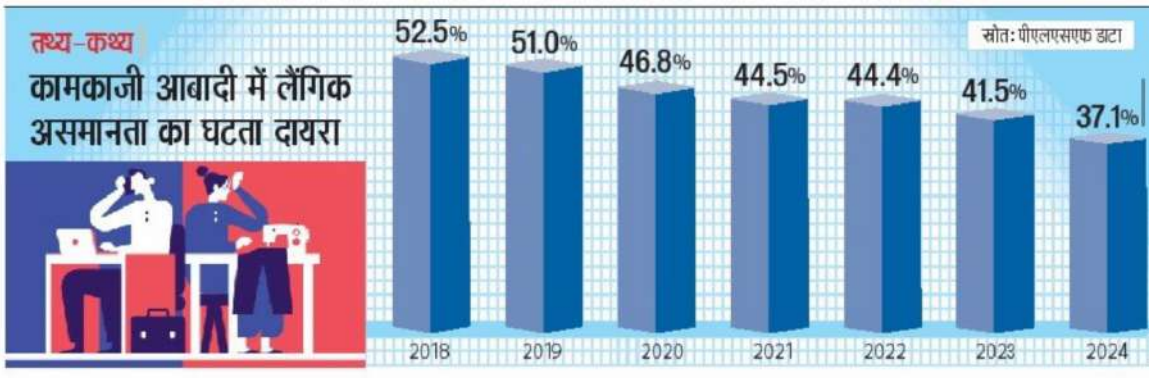

Dainik Jagaran Page No-8

प्रतिनिधि सभा के तीन सदस्यों ने प्रस्ताव पेश कर इसे बताया अवैध

भारत पर 50% टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी सांसद

समर्थन

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में कांग्रेस (संसद) के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में तीन सदस्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ को खत्म करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। इसमें टैरिफ को अवैध बताया गया है।

अमेरिकी सांसदों ने शुक्रवार को प्रस्ताव को पेश किया। प्रस्ताव में इन शुल्क को अवैध बताया गया है। सदस्यों ने प्रस्ताव में कहा कि इससे अमेरिकी श्रमिकों और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका-भारत संबंधों में भी तनाव पैदा होगा। उत्तर कैरोलिना की प्रतिनिधि डेबोरा रॉस, टेक्सास के प्रतिनिधि मार्क वेसी और इलिनोइस के प्रतिनिधि राजा कृष्णमूर्ति ने प्रतिनिधि सभा में यह प्रस्ताव पेश किया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस कदम का मकसद 27 अगस्त को भारतीय सामानों पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क को रद्द कराना है। यह प्रस्ताव डेमोक्रेट्स द्वारा ट्रंप के एकतरफा व्यापारिक कार्यों को चुनौती देने और भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों को फिर से ठीक करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

अक्तूबर की शुरुआत में रॉस, वेसी और कृष्णमूर्ति ने कांग्रेसी रो खन्ना और 19 अन्य सांसदों के साथ मिलकर राष्ट्रपति से टैरिफ नीति को पलटने और द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने का आग्रह किया था। इससे पहले सीनेट में ब्राजील पर लगाए गए इसी तरह के टैरिफ को वापस लेने और राष्ट्रपति के अधिकार को सीमित करने के लिए दोनों पार्टियों ने मिलकर प्रयास किया था। बता दें कि अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम के तहत कई भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर 50% तक कर दिया है।

एकतरफा शुल्क वृद्धि पर मेक्सिको से बातचीत

नई दिल्ली। भारत मेक्सिको द्वारा कई उत्पादों पर एकतरफा टैरिफ बढ़ाने के फैसले को लेकर उससे बातचीत कर रहा है, ताकि दोनों देशों के लिए लाभकारी समाधान निकाले जा सके। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि भारत अपने निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ये शुल्क उन देशों के खिलाफ लगाए गए हैं, जिनका मेक्सिको के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) नहीं है। इनमें भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया शामिल हैं।

अमेरिकियों पर टैक्स थोपने जैसा है शुल्क

डेबोरा रॉस ने कहा, उत्तर कैरोलिना की अर्थव्यवस्था व्यापार, निवेश व भारतीय अमेरिकी समुदाय के जरिये भारत से जुड़ी हुई है। भारतीय कंपनियों ने राज्य में 100 करोड़ डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है, जिससे हजारों नौकरियां पैदा हुईं।

कृष्णमूर्ति ने टैरिफ को नुकसानदायक बताया

भारतीय-अमेरिकी कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने टैरिफ को नुकसानदायक बताते हुए कहा कि वे आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करते हैं, अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान पहुंचाते हैं। शुल्क खत्म करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग मजबूत होगा।

ब्राजील पर लगे 40% शुल्क को रद्द करें ट्रंप : सिल्वा

साओ पाउलो। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ब्राजीलियाई उत्पादों पर लगाए गए अतिरिक्त 40% आयात शुल्क को रद्द करने का आग्रह किया है।

Hindustan Page No-15

अखिल भारतीय सिविल सेवा अथलेटिक्स चैम्पियनशिप का आगाज

पटना। अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025-26 का शुभारंभ आज पाटलिपुत्र खेल परिसर, पटना में भव्य और उत्साहपूर्ण वातावरण में किया गया। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर से 31 राज्य एवं केंद्रीय सचिवालय की टीमें भाग ले रही हैं।

चैम्पियनशिप का उद्घाटन बिहार के मख्य सचिव श्री और खेल खिलाड़ियों के प्रति आत्मीय आतिथ्य के लिए जाना जाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह चैम्पियनशिप न केवल खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि देशभर के सिविल सेवकों के बीच आपसी सौहार्द और सहयोग को भी मजबूत करेगी। उद्घाटन समारोह के दौरान 31 टीमों द्वारा अनुशासित मार्च पास्ट किया गया, जो खेल भावना और एकता का प्रतीक रहा। इसके उपरांत बिहार सचिवालय खेल फाउंडेशन एवं अखिल भारतीय सिविल सेवा के ध्वज का ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री दीपक सिंह, डॉ. बी. राजेंद्र, श्री महेंद्र कुमार एवं श्री शिरशात कपिल अशोक सहित बिहार सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

किलकारी पटना को राधा सिन्हा स्मृति बॉल बैडमिंटन का खिताब

पटना। चित्रांश खेल एवं सांस्कृतिक मंच के तत्वावधान में मुजफ्फरपुर जिला बॉल बैडमिंटन संघ एवं किलकारी मुजफ्फरपुर द्वारा किलकारी बिहार बाल भवन मुजफ्फरपुर में आयोजित राधा सिन्हा स्मृति एकदिवसीय जूनियर बालिका बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में किलकारी पटना ने पूर्वी चम्पारण को 35-16,35-18 से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया। इससे पूर्व खेले गये महत्वपूर्ण लीग मुकाबले में पूर्वी चम्पारण ने मुजफ्फरपुर को आसानी से 35-11,35-8 से एवं किलकारी पटना ने मुजफ्फरपुर को 35-18,35-22 से पराजित किया। प्रातियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किलकारी पटना की मुस्कान कुमारी को दिया गया।

Aaj Patna Page No-12

देश में आईएसओ सर्टिफिकेट्स प्राप्त करने वाला बिहार बना पहला बोर्ड

अध्यक्ष आनन्द किशोर ने प्राप्त किया तीन आईएसओ प्रमाणपत्र

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। देश में आईएसओ सर्टिफिकेट्स प्राप्त करने वाला बिहार बोर्ड (बिहार विद्यालय परीक्षा समिति) पहला बोर्ड बन गया है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली एवं उत्कृष्ट रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली के लिए बिहार बोर्ड आईएसओ सर्टिफिकेट्स मिले हैं। यह बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि है।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इसके अध्यक्ष आनन्द किशोर ने आईएसओ सर्टिफिकेट्स प्राप्त किया। इसके पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा प्रणाली में किये गये सुधारों एवं नवाचारों के लिए अध्यक्ष आनन्द किशोर को 'प्राइम मिनिस्टर एवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' मिल चुका है। आपको याद दिला दूं कि विगत वर्षों में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सभी कार्यों में आईटी, सॉफ्टवेयर एवं टेक्नोलॉजी का व्यापक इस्तेमाल करते हुए पूरी परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी एवं छात्र-हितकारी बनाया गया है।

समिति की सम्पूर्ण परीक्षा व्यवस्था एवं कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीक के माध्यम से किये गये सुधारों का ही परिणाम है कि बिहार बोर्ड ने वर्ष 2019 से वर्ष 2025 तक लगातार सात वर्ष देश में सबसे पहले मैट्रिक एवं

(शेष पृष्ठ ९ पर)

Aaj Patna Page No-3

बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम

पटना (आससे)। बिहार में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से शुरू की गई 'उद्योग वार्ता' निवेशकों के बीच जबरदस्त हिट साबित हो रही है. इस पहल के तहत बिहार में

32 निवेशकों ने दिये उद्योग लगाने के प्रस्ताव

निवेश के इच्छुक इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमेन सीधे राज्य के मुख्य सचिव से मुलाकात करके अपनी बात उनके सामने रखते हैं. उद्योग वार्ता की दूसरी बैठक में रिकॉर्ड 32 उद्योग प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव से सीधे मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की गहरी रुचि दिखाई.

बिहार सरकार की यह पहल राज्य को देश के नए औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. अधिकतर निवेशक बिहार के मूल निवासी या बिहारी उद्यमी हैं, जिनका सपना अपने गृह राज्य में उद्योग लगाकर रोजगार पैदा करना और युवाओं के पलायन को रोकना है. उनका कहना है कि बिहार में प्रतिभा और संभावनाओं की कोई कमी नहीं, बस सही अवसर

(शेष पृष्ठ ९ पर)

Aaj Patna Page No-3

'भूमि सुधार जनकल्याण संवाद' प्रशंसनीय पहल

उपमुख्यमंत्री से मिला चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल

पटना (आससे)। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री-सह-राज्य एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात की।

चैम्बर के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने बताया कि राज्य के भूमि सुधार से संबंधित कई मुद्दों पर विस्तृत वार्ता हुई। प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री-सह-राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री द्वारा प्रारंभ किये गये 'भूमि सुधार जनकल्याण संवाद' की सराहना करते हुए कहा कि यह काफी प्रशंसनीय पहल है, जिसका बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हार्दिक स्वागत करता है। इस पहल से भूमि विवाद के काफी लंबित मामलों का समाधान सहज रूप से हो सकेगा।

श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में होनेवाले संवाद कार्यक्रम में मंत्री के स्वयं रहने से सभी वर्ग के लोग उनको अपनी बातों को निर्भीक होकर बता सकेंगे।

उन्होंने विभाग द्वारा प्रदत्त दाखिल-खारिज, भू-लगान भुगतान, डिजिटल हस्ताक्षरित भू-अभिलेख, ई-मापी परिमार्जन प्लस जैसी ऑनलाइन सेवाओं से काफी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इससे लोगों को सहज रूप से पेपर उपलबध होता है, जिससे उन्हें सुविधा हो रही है।

प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष एनके ठाकुर एवं विशाल टेकरीवाल, कोषाध्यक्ष राजेश जैन, महामंत्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व अध्यक्ष सुभाष पटवारी, पूर्व उपाध्यक्ष आशीष शंकर, पूर्व महामंत्री एकेपी सिन्हा एवं कार्यकारिणी सदस्य श्रवण गोयनका, अजय गुप्ता, पवन भगत एवं आदित्य राज थे।

Aaj Patna Page No-2

राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार देना व पलायन रोकना है: उद्योग मंत्री

पटना (आससे)। बिहार के उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने उद्योग निदेशक मुकुल कुमार गुप्ता तथा निवेश प्रोत्साहन (आईपी) टीम के साथ विभागीय कार्यालय कक्ष में एक विस्तृत बैठक की। आयोजित बैठक में बिहार में निवेश की अपार संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर उद्योग निदेशक द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन दी गई, जिसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों, औद्योगिक विकास की दिशा और भविष्य की रणनीतियों को साझा किया गया। प्रस्तुति के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि किस प्रकार बिहार सरकार उद्योगों को आकर्षित करने के लिए मजबूत नीतिगत समर्थन, आधुनिक आधारभूत संरचना, भूमि उपलब्धता और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। साथ ही यह भी बताया गया कि कैसे स्टार्टअप्स से लेकर बड़ी औद्योगिक इकाइयों तक को बिहार में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना तथा पलायन को रोकना है। बैठक में यह विचार किया गया कि कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, हरित ऊर्जा और आधुनिक तकनीक जैसे क्षेत्रों में निवेश को और अधिक प्रोत्साहित कर राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं।

बिहार बनेगा पुष्प उत्पादन का नया केन्द्र : रामकृपाल

पटना (आससे)। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित किसान विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कृषि विविधीकरण और बागवानी आधारित

कृषि को बढ़ावा देने के विजन के अनुरूप बिहार सरकार फूलों की खेती को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित कर रही है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष२०२५-२६ के अंतर्गत रबी मौसम में 'फूल (गेंदा) विकास योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ८ करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य रबी मौसम में गेंदा फूल की खेती का विस्तारकर राज्य में व्यावसायिक बागवानी को नयी दिशा देना है। गेंदा फूला की बाजार में मांग को देखते हुए यह फसल किसानों के लिए कम लागत में अधिक आमदनी का सशक्त माध्यम बन सकती है। इससे किसानों की आय में स्थायी वृद्धि के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत किसानों को गेंदा फूल की खेती के लिए पौधा अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जाएगी। गेंदा उत्पादन हेतु प्रति हेक्टेयर ८० हजार रुपये की इकाई लागत निर्धारित की गयी है, जिसपर किसानों को ५० प्रतिशत अनुदान अर्थात् ४० हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी। यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू होगी, जिससे अधिक से अधिक किसान इस लाभकारी खेती से जुड़ सकेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छक किसानों को डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लाभुकों का चयन 'पहले जाओ, पहले पाओ' के आधारपर किया जाएगा। अनुदान की राशि पुष्पण के उपरांत संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की अनुशंसा एवं जिला उद्यान पदाधिकारी की स्वीकृति के बाद किसानों के खाते में एकमुश्त भुगतान की जाएगी। उन्होंने बताया कि लाभुकों के चयन में सामाजिक समावेशन का विशेष ध्यान रखते हुए ३० प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे महिला सशक्तीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

देश में पहली बार किसी परीक्षा बोर्ड को ऐसी उपलब्धि हासिल हुई

परचम: बिहार बोर्ड को आईएसओ प्रमाणपत्र

पटना, कार्यालय संवाददाता। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) को कार्यप्रणाली में उत्कृष्टता और पारदर्शिता के लिए तीन श्रेणियों में आईएसओ (अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन) प्रमाणपत्र मिले हैं। ये प्रमाणपत्र गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली के लिए दिये गये हैं।

इस उपलब्धि के साथ ही बिहार बोर्ड देश का पहला परीक्षा बोर्ड बना है, जिसे एक साथ तीनों प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। सीबीएसई को अब तक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ प्रमाणपत्र मिले हैं।

आनंद किशोर के मुताबिक, मैट्रिक-इंटर और अन्य परीक्षाओं के साथ-साथ विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था और प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाया गया है। आईटी, सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग से परीक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और छात्र-हितकारी बनाई गई है। इन्हीं कार्यों में उत्कृष्टता के कारण बोर्ड को यह उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने बताया कि बिहार बोर्ड लगातार सात वर्षों से (2019 से 2025) देशभर में सबसे पहले मैट्रिक व इंटर का रिजल्ट जारी करने में सफल रहा है। समिति ने रिकॉर्ड प्रबंधन, सूचना सुरक्षा और गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कई प्रमुख पहल की है।

गुणवत्ता, सूचना सुरक्षा और रिकॉर्ड प्रबंधन में सर्टिफिकेट

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को मिले तीन आईएसओ (अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन) प्रमाणपत्र को प्रदर्शित करते बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर और अन्य।

03
क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम के लिए मिला प्रमाणपत्र

> आईएसओ प्रमाणपत्र मिलना बड़ी उपलब्धि है। इससे बोर्ड की विश्वसनीयता कायम रहेगी। बिहार बोर्ड को 2022 में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट लोक प्रशासन पुरस्कार भी मिल चुका है। इससे समिति की दक्षता और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत होगी।-आनंद किशोर, अध्यक्ष, बिहार बोर्ड

इन श्रेणियों में कामयाबी

1. गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली
(आईएसओ 9001:2015) : मैट्रिक-इंटर स्तर के विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया विश्वसनीय बनी। रिजल्ट लंबित नहीं।

2. सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली
(आईएसओ/आईईसी 27001:2022- परिणाम घोषित करने में अक्वल, ऑनलाइन फैसिलिटेशन फॉर स्टूडेंट्स (ओएफएस) के जरिये 11वीं में नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन

3. रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली
(आईएसओ 15489-1:2016) - 1983 से 2025 तक के डेटा को ऑनलाइन किया गया।

यह होगा फायदा

- बिहार बोर्ड की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा देशभर में बढ़ेगी
- छात्रों को भरोसा होगा कि दाखिला, परीक्षा-रिजल्ट में गुणवत्ता रहेगी
- कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, कार्य में दक्षता हासिल होगी
- गुणवत्ता, पारदर्शिता और सुरक्षा के मानकों के पालन की गारंटी होगी

Hindustan Page No-3

वरिष्ठ कथाकार मैत्रेयी पुष्पा को मिलेगा इफको साहित्य सम्मान

जागरण टीम, नई दिल्ली

भारतीय ग्रामीण जीवन व कृषि संस्कृति पर लिखने वाले रचनाकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको) ने वर्ष 2025 के साहित्य सम्मानों की घोषणा की है। इस बार प्रतिष्ठित इफको साहित्य सम्मान 2025 वरिष्ठ कथाकार मैत्रेयी पुष्पा को प्रदान किया जाएगा, जबकि इफको युवा साहित्य सम्मान 2025 के लिए अंकिता जैन को 'ओह रे! किसान' पुस्तक के लिए दिया जाएगा। दोनों रचनाकारों को 30 दिसंबर को दिल्ली स्थित इफको सदन में आयोजित विशेष समारोह में सम्मानित किया जाएगा। मुख्य साहित्य सम्मान के तहत 11 लाख रुपये, प्रतीक चिह्न व प्रशस्ति पत्र तथा युवा साहित्य सम्मान के अंतर्गत 2.5 लाख रुपये, प्रतीक चिह्न व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

दोनों रचनाकारों का चयन वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रकांता की अध्यक्षता वाली समिति ने किया, जिसमें नासिरा शर्मा, अनंत विजय, यतीन्द्र मिश्र, उत्कर्ष शुक्ल और डा. नलिन विकास शामिल थे। इफको की यह पहल ग्रामीण समाज और कृषि आधारित कहानियों, उपन्यासों और साहित्यिक अभिव्यक्तियों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2011 में शुरू की गई थी।

- इफको ने की सम्मान 2025 की घोषणा की, 30 को होगा पुरस्कार वितरण
- युवा साहित्य सम्मान से अंकिता जैन को किया जाएगा सम्मानित

मैत्रेयी पुष्पा। जागरण आर्काइव

मैत्रेयी पुष्पा की प्रमुख कहानियां

मैत्रेयी पुष्पा की प्रमुख कृतियों में कहानी-संग्रह 'चिन्हार', 'गोमा हंसती है', 'ललमनियां', 'समग्र कहानियां' और उपन्यास 'इदन्नमम', 'अगनपाखी', 'अल्मा कबूतरी', 'बेतवा बहती रही', 'चाक', 'फरिश्ते निकले' शामिल है। 'फैसला' कहानी पर बनी टेलीफिल्म 'वसुमती की चिट्ठी' और 'इदन्नमम' पर आधारित धारावाहिक ने भी उनका साहित्य लोगों तक पहुंचाया। वह सार्क लिटरेरी अवार्ड, सरोजिनी नायडू पुरस्कार, प्रेमचंद सम्मान और शाश्वती सम्मान सहित कई महत्वपूर्ण सम्मानों से अलंकृत हो चुकी है।

'ओह रे! किसान' को पहले भी मिल चुका पुरस्कार

नईदुनिया प्रतिनिधि के अनुसार, अंकिता जैन ने बताया कि शोध पर आधारित अपनी किताब में उन्होंने कम जमीन वाले छोटे किसानों की व्यथा और पारंपरिक खेती को उभारा है। इस पुस्तक के लिए उन्हें पूर्व में पर्यावरण जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से तृतीय पुरस्कार भी मिला है। मूल रूप से मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की निवासी अंकिता अब तक आधा दर्जन से अधिक किताबें लिख चुकी है। इनमें जागरण-नीलसन बेस्ट सेलर पहली किताब "ऐसी वैसी औरत", "मैं से मां तक", "बहेलिए", उपन्यास 'मुहल्ला सलीमबाग' एवं बाल उपन्यास "आतंकी मोर" को भी सराहा जा रहा है। जल्द ही उनकी अगली किताब 'इम्परफेक्ट मां' आने वाली है।

अंकिताजैन। स्वयं

संस्थान का कहना है कि गांव की मिट्टी, किसानों के संघर्ष, महिला जीवन और सामाजिक बदलावों को रचनात्मक रूप से स्वर देने वाले लेखक इस सम्मान से देशभर में साहित्यिक जगत के केंद्र में आते हैं।

मैत्रेयी पुष्पा का समृद्ध साहित्यिक सफर : वर्ष 2025 का मुख्य साहित्य सम्मान पाने वालीं मैत्रेयी पुष्पा हिंदी साहित्य की उन धारदार और महत्वपूर्ण आवाजों में से हैं, जिन्होंने ग्रामीण स्त्री जीवन की विडंबनाओं और संघर्षों को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उनका जन्म 30 नवंबर 1944 को अलीगढ़ जिले के सिकुर्रा गांव में हुआ और जीवन का बड़ा समय बुंदेलखंड में बीता। झांसी से एमए (हिंदी साहित्य) करने के बाद उन्होंने साहित्य की दुनिया में अलग पहचान बनाई।

गांव की महिलाओं की कहानियों ने किया प्रेरित : साहित्यकार बनने और गांव की कहानियों पर लिखने की प्रेरणा के बारे में पूछने पर मैत्रेयी पुष्पा ने कहा कि मैंने गांव को करीब से देखा है। वहां के लोगों का संघर्ष देखकर मुझे लगा कि गांव पर कोई खास लिखता नहीं, यहीं सोचकर लिखना शुरू किया। जिंदगी सिर्फ रोमानियत में नहीं गुजरती। संघर्ष भी होता है। गांव की महिलाओं को देखा कि कैसे वह बिना सहायता के लड़ रही हैं। जब महिलाओं को सहयोग नहीं मिलता है तो वह ज्यादा साहसी हो जाती हैं। बस, यहीं से मैंने ठान लिया कि स्त्री विमर्श को उठाऊंगी। मेरे पात्र बोलने से ज्यादा, करते भी हैं। इसी से बदलाव आता है। इसके बाद से स्त्री विमर्श को उठाया।

Dainik Jagaran Page No-6

'जीरो टालरेंस' की नीति से माओवादी विद्रोह की वैचारिक, क्षेत्रीय रीढ़ टूटी

नई दिल्ली, प्रेट्र : विगत 11 वर्षों में केंद्र सरकार की 'जीरो टालरेंस' की नीति और सख्त कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप माओवादी हिंसा में 70 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। नागरिक और सुरक्षा बलों की हताहतों की संख्या में भी भारी गिरावट आई है। शीर्ष माओवादी नेतृत्व को व्यवस्थित रूप से निष्क्रिय कर दिया गया है और हजारों माओवादियों ने सशस्त्र संघर्ष के बजाय मुख्यधारा के जीवन को चुना है। हालांकि, प्रतिरोध के कुछ क्षेत्र अभी भी मौजूद हैं और इनके पूर्ण उन्मूलन के लिए 31 मार्च, 2026 की घोषित समय सीमा तक निरंतर सतर्कता की आवश्यकता है। स्थिति स्पष्ट है - माओवादी विद्रोह की वैचारिक और क्षेत्रीय रीढ़ टूट चुकी है जिससे इन क्षेत्रों में स्थायी शांति एवं विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया है जो लंबे समय से इन दोनों से वंचित रहे हैं।

केंद्र सरकार ने कई एजेंसियों की समन्वित कार्रवाई के माध्यम से 92 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करके माओवादियों की वित्तीय सहायता को काफी हद तक सीमित कर दिया है और उनके सूचना नेटवर्क पर नियंत्रण कड़ा करके 'शहरी माओवादियों' को गंभीर नैतिक और मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचाई है। देश को मार्च 2026 तक पूरी तरह से माओवाद मुक्त बनाने के दृढ़ लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) में एक समर्पित विभाग बनाया है, जिसने 40 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। राज्य अधिकारियों ने अतिरिक्त 40 करोड़ रुपये जब्त किए हैं, जबकि ईडी ने 12 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

- माओवाद विरोधी कार्रवाई में 92 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त, शहरी माओवादियों को गंभीर क्षति
- उन क्षेत्रों में स्थायी शांति-विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ जो लंबे समय से इन दोनों से वंचित रहे हैं

माओवादियों के खिलाफ सख्ती। फाइल

हकीकत को बयां करते आंकड़े...

- 2025 में माओवाद से "सर्वाधिक प्रभावित" सिर्फ तीन जिले ही बचे हैं, जबकि 2014 में यह संख्या 36 थी
- 2025 में 317 माओवादियों को ढेर किया गया, 862 को गिरफ्तार किया एवं 1,973 ने आत्मसमर्पण किया
- आपरेशन ब्लैक फारेस्ट में 27 कट्टर माओवादी ढेर; छग में 197 और महाराष्ट्र में 61 ने आत्मसमर्पण किया
- किलेबंद थानों की संख्या 2014 तक केवल 66 ही थी, यह संख्या पिछले 10 वर्षों में बढ़कर 586 हो गई

प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में बहुआयामी और निर्णायक सुधार

- छह वर्षों में 361 नए सुरक्षा शिविर स्थापित, परिचालन पहुंच मजबूत करने को 68 रात्रिकालीन हेलीपैड
- मई 2014 व अगस्त 2025 के बीच प्रभावित क्षेत्रों में 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया
- दुर्गम क्षेत्रों में हर मौसम में 20,815 करोड़ की लागत वाली 17,589 किमी की परियोजनाओं को मंजूरी
- मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए पहले चरण में 4,080 करोड़ रुपये की लागत से 2,343 (2जी) टावर लगे
- दूसरे चरण में 2,210 करोड़ के निवेश से 2,542 टावरों को मंजूरी, इनमें 1,154 पहले ही लगाए जा चुके
- आकांक्षी जिलों व 4जी संतृप्ति योजनाओं के तहत 8,527 (4जी) टावरों को मंजूरी, 5,357 टावर चालू हैं
- प्रभावित क्षेत्रों में 1,804 बैंक शाखा, 1,321 एटीएम की स्थापना, 37,850 बैंकिंग संवाददाताओं की तैनाती
- केंद्र सरकार ने 90 जिलों में 5,899 डाकघर भी खोले हैं, जिनकी कवरेज प्रत्येक पांच किलोमीटर पर है

एजेंसियों की समन्वित सख्त कार्रवाई से शहरी माओवादियों को नैतिक व मनोवैज्ञानिक क्षति : सरकार ने शनिवार को एक बयान में कहा, "एक साथ की गई कार्रवाई ने शहरी माओवादियों को गंभीर नैतिक और मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचाई है और उनके सूचना युद्ध नेटवर्क पर नियंत्रण को और मजबूत किया है।" माओवादी चरमपंथियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण देते हुए सरकार ने कहा कि 2025 में माओवाद से "सबसे अधिक प्रभावित" केवल तीन जिले ही बचे हैं, जबकि 2014 में यह संख्या 36 थी।

2025 में अब तक 317 माओवादियों को निष्क्रिय किया जा चुका है, 862 को गिरफ्तार किया गया है और 1,973 ने आत्मसमर्पण किया है। बयान में कहा गया है, "कुल 28 शीर्ष माओवादी नेताओं को निष्क्रिय किया जा चुका है। इनमें 2024 में निष्क्रिय किया गया केंद्रीय समिति का एक सदस्य और 2025 में ढेर किए गए पांच सदस्य शामिल हैं।"

सुरक्षा बलों की प्रमुख सफलताओं को सूचीबद्ध करते हुए सरकार ने कहा कि आपरेशन ब्लैक फारेस्ट में 27 कट्टर माओवादी मारे गए। 23 मई, 2025 को बीजापुर में 24 ने आत्मसमर्पण किया। अक्टूबर 2025 में कुल 258 (छत्तीसगढ़ में 197 और महाराष्ट्र में 61) ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 10 वरिष्ठ माओवादी शामिल थे।

माओवाद प्रभावित जिलों की कुल संख्या 2014 में 126 से घटकर 2025 में मात्र 11 रह गई है। किलेबंद थानों की संख्या 2014 तक केवल 66 थी, जो पिछले 10 वर्षों में बढ़कर 586 हो गई है।

Dainik Jagaran Page No-3

शोर के बीच

बाखबर

सुधीश पचौरी

> एक ओर 'इंडिगो' के एकाधिकार का 'मनमानापन' और दूसरी ओर मंत्रालय तथा डीजीसीए के बीच एक चुप्पी। हजारों उड़ानें रद्द। हवाईअड्डों पर लावारिस छोड़ दिए गए तमाम यात्रियों की तकलीफें। गनीमत कि चैनलों के रिपोर्टरों और आलोचना ने अधिकारियों पर कुछ असर डाला।

एक सौ पचासवीं वर्षगांठ मनाता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम्! बंगाल का वंदे मातरम्... अखिल भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम्! वर्षगांठ मनाने को लेकर संसद में प्रधानमंत्री का संबोधन... कि जिस गीत ने देश के आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी, प्रेरणा दी, उस वंदे मातरम् का गायन करना सदन का सौभाग्य। राष्ट्रगीत की सुदीर्घ यात्रा का बखान... इतिहास में किस-किस ने गाया वंदे मातरम्... इसने गाया, उसने गाया, देशभर ने गाया, दुनिया के देशों ने भी गाया, गांधी ने गाया, नेताजी सुभाष बोस ने गाया, नेहरू ने गाया, पटेल ने गाया, टैगोर ने गाया वंदे मातरम्..! स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश को एकजुट करने वाला वंदे मातरम्... अंग्रेजों को डराने वाला वंदे मातरम्... 'जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी' से जुड़ता वंदे मातरम्!

किसने गाया, किसने खारिज किया वंदे मातरम्! जिन्ना ने खारिज किया! तुष्टीकरण के लिए संशोधित किया गया वंदे मातरम्। इस तरह दो 'बंदों' का हुआ वंदेमातरम्..! इस पर संसद में शोर और उस शोर में भी 'वंदे मातरम्-वंदे मातरम्'। यहां कोई पक्ष या प्रतिपक्ष नहीं। 2047 में विकसित भारत बनाने का अवसर। हजारों वर्षों का भारत बोलता है वंदे मातरम् में। वीर का अभिमान हैं ये शब्द! पहले रहा 'सप्त कोटि' वाले बंगाल का वंदे मातरम्, फिर हुआ तीस कोटि का वंदे मातरम्, अब है 140 कोटि का वंदे मातरम्..! कुछ कहें कि सभी गाते वंदे मातरम्। एक कहे कि राष्ट्रगीत सबका गीत। ग्यारह घंटे तक वंदे मातरम् होता रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष का 'वंदे मातरम्'। गृहमंत्री का वंदे मातरम् कि 'राष्ट्रगान' और 'राष्ट्रगीत' भारत माता की दो आंखें हैं।

एक चर्चक बोले कि ये हिंदू गीत कैसे है... ये तो भारत का 'राष्ट्रगीत' है जो राष्ट्र को नमन करता, कराता है। इससे किसी को क्या एतराज हो सकता है? पहले भी कई मुसलिम नेताओं ने गाया है, तब हम क्यों न गाएं? ऐसी ही एक बहस में सुनाई पड़ी एक एंकर की मजेदार तुकबंदी कि- 'हम राष्ट्रभक्तों के लिए वंदे मातरम् 'एनर्जी' है, जबकि कुछ के लिए 'एलर्जी' है! बहुतों ने मांग की कि हम जिस वंदे मातरम् को गाते हैं, यह अधूरा है। उसे उसके पूरे मूल रूप में बहाल किया जाना चाहिए और संविधान में जरूरी संशोधन किए जाने चाहिए। एक चर्चक ने फरमाया कि बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय का 'आनंदमठ' एक 'हिंदू लेखन' है जो 'संन्यासी विद्रोह' पर आधारित है... जो अपने मूल में मुसलिम शासकों की ज्यादतियों के खिलाफ था। बाद में यह अंग्रेजों के शासन की ज्यादतियों के खिलाफ सारे देश को एकजुट करने वाला बन गया। कइयों ने कहा कि यह गीत तो राष्ट्रगान से बेहतर नजर आता है। कुछ वक्ताओं ने वंदे मातरम् को भी चुनावी राजनीति में लपेट दिया कि सत्तापक्ष वंदे मातरम् की डेढ़ सौवीं वर्षगांठ इसलिए मना रहा कि अगले वर्ष बंगाल का चुनाव है और बंगाली का वोट लेना है।

वंदे मातरम् पर अच्छे संबोधन प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षामंत्री के रहे। इसी क्रम में एक बेहतरीन वक्तव्य भाजपा के रविशंकर का रहा और विपक्ष में बेहतरीन बोलने वालों में पहला नंबर प्रियंका गांधी का रहा, जबकि दूसरा गौरव गोगोई का रहा। इसके बाद की सबसे चर्चित कहानी 'एसआइआर' यानी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर 'सिरफुटौव्वल' की रही। विपक्ष के नेता ने एक बार फिर संसद में 'वोट चोरी' का मुद्दा उठाया और चुनाव आयोग को लेकर धमकी दोहराई कि हम आए तो ऐसा कानून लाएंगे जो तुम्हारा हिसाब करेगा... हम छोड़ने वाले नहीं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में हो रही एसआइआर की इस खबर ने कइयों को झटका दिया कि उत्तर प्रदेश में दो करोड़ से अधिक इससे संबंधित फार्म लौट कर नहीं आए हैं। तब क्या उत्तर प्रदेश में दो करोड़ से अधिक मतदाता 'अनुपस्थित', फर्जी, मृत या प्रवासित हैं? वंदे मातरम् और एसआइआर को लेकर एक चैनल में सत्ता प्रवक्ता और एक विपक्षी प्रवक्ता के बीच ऐसी भिड़ंत हुई, जो देखते-देखते गाली-गलौज तक आ गई।

एक ओर 'इंडिगो' के एकाधिकार का 'मनमानापन' और दूसरी ओर मंत्रालय और डीजीसीए के बीच एक अजानी चुप्पी। हजारों उड़ानें रद्द। हवाई अड्डों पर लावारिस छोड़ दिए गए तमाम यात्रियों की तकलीफें। गनीमत कि चैनलों के रिपोर्टरों और आलोचना ने अधिकारियों पर कुछ असर डाला। आखिर मंत्री और डीजीसीए सबको सक्रिय होना पड़ा। फिर भी 'एअरलाइन' वालों ने अपने किराए कई-कई गुना बढ़ा दिए... और कहीं कोई विरोध नहीं।

चलते-चलते अब तमिलनाडु में भी एक 'बाबरी' बनता दिखता है। मदुरई में दो पहाड़ी। एक पहाड़ी पर दीप जले... दूसरी पर मजार। दूसरी पहाड़ी पर 'दीपम उत्सव' के लिए मजार वालों को कोई 'आपत्ति नहीं', लेकिन सरकार को एतराज। फिर अदालत और उसका फैसला कि दीप जले तो जले, लेकिन सत्ता को फिर एतराज। फिर अदालत, सत्ता, अदालत और 'दीपम' के पक्ष में फैसला देने वाले जज के खिलाफ एक सौ सात सांसदों का महाभियोग का प्रस्ताव!

Jansatta Page No-17

इतिहास से छेड़छाड़, भविष्य का तिरस्कार

दूसरी नजर

पी चिदंबरम

> राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत के लिए कुछ छंदों का चयन कोई असामान्य बात नहीं है। जन गण मन, जो कि राष्ट्रगान है, रवींद्रनाथ टैगोर की पूर्ण कविता का संक्षिप्त रूप है। कई देशों के राष्ट्रगान लंबे गीतों के संक्षिप्त रूप हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तथ्य को जानबूझकर नजरअंदाज किया कि आरएसएस और भाजपा के पूर्ववर्ती संगठन की भारत के स्वतंत्रता संग्राम में या वंदे मातरम् गाने या उसे लोकप्रिय बनाने में कोई भूमिका नहीं थी।

इतिहास एक सार्वजनिक संपत्ति की तरह है। कोई भी इसमें प्रवेश कर सकता है और इतिहास लिख सकता है या उसका पुनर्लेखन कर सकता है- जब तक कि बाद का कोई शोध और अध्ययन उन तथ्यों को गलत साबित न कर दे। यूरोपीय सिद्धांतकारों और कुछ नकलची भारतीय इतिहासकारों ने आर्यों को एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में चित्रित किया, जिन्होंने भारत और अन्य देशों पर आक्रमण करके उन्हें 'सभ्य' बनाया। यह एक मिथक था। भारत के कई हिस्सों में आर्यों के आने से बहुत पहले प्राचीन उन्नत सभ्यताएं मौजूद थीं: उदाहरण के लिए, तमिलनाडु के कीझाडी और अन्य स्थानों में पुरातात्विक खोजों से 3500 ईसा पूर्व की एक समृद्ध सभ्यता का पता चलता है।

क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की 'खोज' इतिहास का एक प्रारंभिक पाठ था, जो हम सबने स्कूल में पढ़ा था। यह कई मायनों में गलत था; कोलंबस के इस महाद्वीप पर पहुंचने से कई शताब्दी पहले से ही वहां लोगों की आबादी मौजूद थी, जिसे अब अमेरिका कहा जाता है। शोध ने साबित किया है कि उत्तरी वाइकिंग्स, कोलंबस से लगभग 500 साल पहले उत्तरी अमेरिका पहुंच चुके थे।

तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने वाले

राजनेता इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने में माहिर होते हैं। भाजपा (और सरकार) ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम् को विकृत करने का आरोप लगाया और शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदनों में एक दिन की बहस पर जोर दिया। पार्टी के वक्ताओं ने अपने-अपने तरीके से 'इतिहास' का वर्णन किया; यह विरूपित इतिहास था- एक तरह का दुष्प्रचार। इसमें सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उनके शब्दों में:

'वंदे मातरम् की रचना उस समय हुई थी, जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश साम्राज्य अस्थिर था तथा उसने भारत पर तरह-तरह के दबाव डाले और अन्याय किए। तब बंकिम-दा ने चुनौती दी, और ताकत के साथ जवाब दिया, उसी ललकार से वंदे मातरम् का जन्म हुआ...

'...मोहम्मद अली जिन्ना ने 15 अक्तूबर, 1937 को लखनऊ से वंदे मातरम् के खिलाफ नारा लगाया। मुसलिम लीग के निराधार बयानों का दृढ़ता से खंडन करने और उनकी निंदा करने के बजाय तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम् के प्रति अपनी और कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता की पुष्टि नहीं की और स्वयं वंदे मातरम् पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। जिन्ना के विरोध के ठीक पांच दिन बाद 20 अक्तूबर, 1937 को नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक पत्र लिखकर जिन्ना की भावना से सहमति व्यक्त की..

'...(नेहरू ने कहा) 'मैंने वंदे मातरम् गीत की पृष्ठभूमि पढ़ी है। मुझे लगता है कि यह पृष्ठभूमि मुसलमानों को भड़का सकती है।'

'...दुर्भाग्यवश, 26 अक्तूबर, 1937 को कांग्रेस ने वंदे मातरम् पर समझौता कर लिया और इसे टुकड़ों में बांट दिया... इतिहास गवाह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुसलिम लीग के आगे घुटने टेक दिए और उसके दबाव में आकर तुष्टीकरण की राजनीति अपना ली... कांग्रेस अब एमएमसी (मुसलिम लीग-माओवादी कांग्रेस) बन चुकी है।'

अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रगीत को बांटने से तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा मिला, जिसके कारण विभाजन हुआ। यह कल्पना की ऐसी उड़ान है कि इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करने वाले भी असहज महसूस करेंगे।

संक्षिप्त इतिहास

यहां राष्ट्रगीत का घटनाक्रम दिया गया है (देखें बाक्स)।

राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत के लिए कुछ छंदों का चयन कोई असामान्य बात नहीं है। जन गण मन, जो कि राष्ट्रगान है, रवींद्रनाथ टैगोर की पूर्ण कविता का संक्षिप्त रूप है। कई देशों के राष्ट्रगान लंबे गीतों के संक्षिप्त रूप हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तथ्य को जानबूझकर नजरअंदाज किया कि आरएसएस और भाजपा के पूर्ववर्ती संगठन की भारत के स्वतंत्रता संग्राम में या वंदे मातरम् गाने या उसे लोकप्रिय बनाने में कोई भूमिका नहीं थी। वास्तव में, आरएसएस ने अपने राष्ट्रीय मुख्यालय में 52 वर्षों तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया था।

गलत प्राथमिकताएं

सन 1937 से अब तक दो छंदों वाले राष्ट्रगीत पर किसी ने विवाद नहीं उठाया। अब क्यों? संसद और सरकार को वर्तमान में जनता की गंभीर समस्याओं और भविष्य के लिए देश के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए।

चीन के संवैधानिक निकाय रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, अंतरिक्ष एवं महासागरों की चुनौतियों और डेटा पर चर्चा करते हैं, जो इस तरह पर मानव जीवन में बड़े बदलाव लाएंगे। भारत की संसद को वर्तमान में गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं सभी के लिए उनकी उपलब्धता, वित्तीय स्थिरता, व्यापार घाटा, जलवायु परिवर्तन और अन्य ज्ञात समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। भविष्य में बढ़ती असमानता, जनसंख्या, आंतरिक प्रवासन, धर्मनिरपेक्षता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अन्य अज्ञात मसले भारत के सामने एक चुनौती के रूप में होंगे।

इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करना बहुत बुरी बात है, लेकिन भविष्य का तिरस्कार अक्षम्य है।

1870 का दशक- बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक स्तुति गीत की कुछ पंक्तियां लिखीं, जो अप्रकाशित रहीं।

1881- इस कविता का विस्तारित संस्करण आनंदमठ उपन्यास में शामिल किया गया।

1905- रवींद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवादी प्रदर्शनों का नेतृत्व करते हुए वंदे मातरम् गाया; यह एक राजनीतिक नारा बन गया।

1908- तमिल कवि सुब्रमण्य भारती ने अपनी कविता 'एन्दैयुम थायुम...' में वंदे मातरम् को अमर कर दिया।

बंकिम चटर्जी का यह गीत हर स्वतंत्रता सेनानी की जुबान पर था।

1930 का दशक- सांप्रदायिक राजनीति चरम पर थी, और यह गीत विवादास्पद हो गया।

28-09-1937- राजेंद्र प्रसाद ने सरदार पटेल को पत्र लिखकर गीत के व्यापक विरोध पर चिंता व्यक्त की और सुझाव दिया कि इस पर कांग्रेस की नीति स्पष्ट कर दी जानी चाहिए।

कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की पूर्व संध्या पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने टैगोर से सलाह ली।

17-10-1937- नेताजी बोस ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर कांग्रेस कार्य समिति में गीत पर चर्चा करने का अनुरोध किया।

20-10-1937- नेहरू ने बोस को पत्र लिखकर कहा कि यह विवाद सांप्रदायिक तत्वों द्वारा गढ़ा गया है और वे इस मामले पर टैगोर तथा अन्य लोगों से चर्चा करेंगे।

26-10-1937- टैगोर ने नेहरू को पत्र लिखकर कहा कि गीत का पहला भाग अपने आप में पूर्ण है और इसमें प्रेरणादायक संदेश है, जो किसी भी धार्मिक समुदाय के लिए आपत्तिजनक नहीं है।

28-10-1937- कांग्रेस कार्य समिति ने कविता के दो छंदों को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया।

जनवरी 1939- कांग्रेस कार्य समिति ने महात्मा गांधी की उपस्थिति में वर्धा में हुई एक बैठक में इस प्रस्ताव को दोहराया।

Jansatta Page No-17

केंद्र सरकार के मुताबिक 15 भगोड़े आर्थिक अपराधी हैं इन पर सरकारी बैंकों के 58000 करोड़ रुपए बकाए हैं

किसी देश का कानून वहीं खत्म हो जाता है, जहां से उसकी भौगोलिक सरहद खत्म होती है। इसी के साथ शुरू होता है अन्य देशों से कानूनी सहभागिता का रिश्ता। कई अपराधी देश छोड़ कर भागने में कामयाब हो जाते हैं। इनमें बड़ी संख्या होती है आर्थिक अपराधियों की। कई मामलों में आर्थिक अपराधी देश छोड़ने के बाद विदेश में शानदार जीवन जीते नजर आते हैं। हाल में गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के बाद इसके सह-मालिक गौरव और सौरभ लूथरा रातोंरात थाईलैंड भाग गए। हालांकि इंटरपोल के नोटिस के बाद दोनों हिरासत में ले लिए गए और उन्हें शीघ्र ही भारत लाया जा सकता है। कुछ दिन पहले अमेरिका से एक अपराधी अनमोल बिश्नोई को प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया। लगभग साल भर पहले मुंबई बम धमाके के आरोपियों में से एक डेविड कोलमैन हेडली को लंबे कानूनी संघर्ष के बाद भारत लाने में कामयाबी मिली। ऐसे कई आरोपी हैं, जो अभी भी देश के हाथों में नहीं आए हैं। इनमें मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग भी शामिल हैं। हाल में बेल्जियम के उच्चतम न्यायालय ने भगोड़े मेहुल चौकसी के भारत प्रत्यर्पण को रोकने की याचिका खारिज कर दी। पिछले लंबे समय से भारत सरकार ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। गोवा अग्निकांड के अपराधियों की भारत वापसी की कवायद इसकी मिसाल है। मसले पर सरोकार की पड़ताल।

भागते रहो

बारह अरब डालर की संपत्ति जब्त करने का सरकार का दावा

केंद्र सरकार ने धनशोधन कानून को सख्त कर दिया है। पिछले चार वर्षों में दो अरब डालर बरामद किए हैं। धनशोधन कानून को सख्त करने के कारण भारत सरकार 2014-23 के बीच कई भगोड़ों की 12 अरब डालर की संपत्ति जब्त करने में सक्षम हुई। सीबीआइ ने साल 2024 में फरार आरोपियों के खिलाफ कम से कम 52 रेड नोटिस और 44 ब्लू नोटिस जारी किए। साल 2025 के पहले नौ महीनों में 189 नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें 89 लाल नोटिस और 110 नीले नोटिस शामिल हैं। इंटरपोल ने भारतीय भगोड़ों के खिलाफ 957 रेड नोटिस जारी किए हैं, जिनमें से 231 मामले सीबीआइ से, 130 एनआइए से, 21 ईडी से, 12 एनसीबी से जुड़े हैं और बाकी राज्य पुलिस बलों से संबंधित हैं। इंटरपोल को जारी किए गए कुल नोटिस में से 189 रेड नोटिस आर्थिक अपराध से संबंधित हैं, उसके बाद 254 आतंकवाद से संबंधित, 21 नोटिस जबरन वसूली से संबंधित, 55 मादक पदार्थों से संबंधित और बाकी बलात्कार, जबरन वसूली आदि जैसे अन्य अपराधों से जुड़े हैं।

इस साल अब तक कुल 35 भगोड़ों को भारत प्रत्यर्पित किया जा चुका है और साथ ही कहा, अन्य देशों के पास कुल 338 प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित हैं। साल 2024 में 30 अपराधियों का प्रत्यर्पण किया गया और साल 2023 में 29 अपराधियों का प्रत्यर्पण किया गया था।

वैसे इन मामलों में देरी की आशंका बनी हुई है, और भगोड़े अक्सर इन देशों से अपने प्रत्यर्पण के प्रयासों में बाधा डालने के लिए विभिन्न तरीकों का सहारा लेते हैं। ऐसे उदाहरण भी हैं जहां संगठित आपराधिक गिरोहों से जुड़े कई अपराधी भारत से भाग गए हैं और विदेशों में रहकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं।

किसका कितना है बाकी

सरकार के अनुसार, विजय माल्या और उनकी कंपनियों, जिनमें किंगफिशर एअरलाइंस लिमिटेड और अन्य संस्थाएं शामिल हैं, से संबंधित विभिन्न बैंकों में कुल वित्तीय नुकसान का मूल्य लगभग 27,073.41 करोड़ रुपए है।

31 अक्तूबर तक माल्या और उससे संबंधित संस्थाओं से कुल मिलाकर लगभग 15,094.93 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। इनमें से अकेले स्टेट बैंक आफ इंडिया के माध्यम से 10,814.54 करोड़ रुपए की वसूली हुई है।

नीरव मोदी और उनकी कंपनियों, जिनमें फायरस्टार ग्रुप, फायरस्टार इंटरनेशनल लिमिटेड, फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल लिमिटेड शामिल हैं, को विभिन्न बैंकों में कुल मिलाकर लगभग 9,664.50 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान हुआ है।

नीरव मोदी और उससे संबंधित संस्थाओं से 31 अक्तूबर तक कुल लगभग 671.63 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। गौरतलब है कि पंजाब नेशनल बैंक में दर्ज गैर-ऋण धोखाधड़ी के मामलों में 93.21 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। गैर-ऋण धोखाधड़ी के मामलों से तात्पर्य बैंक के आंतरिक संचालन से संबंधित किसी धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन या गतिविधि से है, न कि ऋण देने की प्रक्रिया से।

नीरव मोदी ब्रिटेन में गिरफ्तार किया जा चुका है और अपने प्रत्यर्पण का विरोध कर रहा है। जुलाई 2025 में, नीरव मोदी के भाई, नेहल को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था।

सुदर्शन वेंकटरमन, रामानुजम शेषरथिनम और उनकी चेन्नई स्थित प्रौद्योगिकी कंपनी आइलाम सिस्टम्स लिमिटेड के मामले में, विभिन्न बैंक लेनदेनों में कुल कथित वित्तीय हानि लगभग 2,145.93 करोड़ रुपए है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इन सभी लेनदेनों से कुल वसूली 4.45 करोड़ रुपए है।

पुष्पेश कुमार बैद, जिसे कोलकाता की एक विशेष अदालत ने कथित तौर पर बड़े पैमाने पर बैंक ऋण धोखाधड़ी का मुख्य साजिशकर्ता घोषित किया है, बैंकों के लगभग 381.71 करोड़ रुपए के नुकसान के लिए जिम्मेदार है। सरकार के अनुसार, इससे कुल 2.06 करोड़ रुपए की वसूली हुई है।

भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी 8,515 करोड़ रुपए के कुल बकाया के साथ वांछित है। उसने एंटीगा और बारबुडा की नागरिकता ले ली है और उसके प्रत्यर्पण के प्रयास जारी हैं।

नितिन जायसंदेसरा से जुड़े नतिन मेहता पर लगभग 6,800 करोड़ का बकाया है, जो ब्याज और जुर्माने को मिलाकर लगभग 7,000 करोड़ हो गया है। इस मामले में वसूली गई राशि सार्वजनिक नहीं की गई है। मेहता वर्तमान में सेंट किट्स और नेविस का नागरिक है। उसके खिलाफ जांच जारी है।

कितने तरह के नोटिस जारी करता है इंटरपोल

रेड नोटिस

अभियोजन के लिए वांछित या सजा काटने के लिए वांछित व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जारी किया गया नोटिस।

येलो नोटिस

लापता व्यक्तियों, अक्सर नाबालिगों, का पता लगाने में मदद करने के लिए, या उन व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करने के लिए जो स्वयं की पहचान करने में असमर्थ हैं।

ब्लू नोटिस

किसी आपराधिक जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिए।

ब्लैक नोटिस

अज्ञात शवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए।

ग्रीन नोटिस

किसी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी देने के लिए, जहां उस व्यक्ति को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा माना जाता है।

आरेंज नोटिस

किसी ऐसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या प्रक्रिया के बारे में चेतावनी देने के लिए जारी किया जाता है जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर और तत्काल खतरा पैदा करती है।

पर्पल नोटिस

अपराधियों द्वारा अपनाए गए तौर-तरीकों, वस्तुओं, उपकरणों और छिपाने के तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना या प्रदान करना।

सिल्वर नोटिस (पायलट चरण)

आपराधिक संपत्तियों की पहचान और पता लगाने के लिए।

जनसत्ता सरोकार

बीते पांच वर्षों में सीबीआइ 134 भगोड़ों को देश में वापस लाने में कामयाब रही है। यह संख्या साल 2010 से 2019 के बीच पूरे दशक के दौरान विदेश से लाए गए भगोड़ों की दोगुनी है। इनमें से 23 भगोड़ों को अकेले इसी वर्ष वापस लाया गया। इसके लिए सीबीआइ ने इंटरपोल के साथ-साथ राज्य और केंद्रीय प्रवर्तन एजंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाया। नतीजतन साल 2020 से इन 134 भगोड़ों का प्रत्यर्पण या निर्वासन सुनिश्चित करने में सफलता मिली। वहीं, 2010 से 2019 के बीच के दशक के दौरान यह संख्या केवल 74 थी।

केंद्र सरकार ने कुख्यात कारोबारियों विजय माल्या और नीरव मोदी सहित 15 व्यक्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। इन पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सामूहिक रूप से 58,000 करोड़ बकाया है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया गया कि केंद्र सरकार ने विजय माल्या और नीरव मोदी सहित 15 व्यक्तियों को 31 अक्तूबर, 2025 तक भगोड़े आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित किया है।

कुल मिलाकर, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (एफईओए) के अनुसार, इन भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर लगभग 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल 58,082 करोड़ बकाया है। इसमें गैर-निष्पादित अभियोग (एनपीए) की तिथि तक 26,645 करोड़ की मूल राशि और एनपीए की तिथि से 31 अक्तूबर 2025 तक अर्जित 31,437 करोड़ का ब्याज शामिल है। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि 31 अक्तूबर 2025 तक इन अपराधियों से 19,187 करोड़ वसूल किए जा चुके हैं। इन 15 अपराधियों में से दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ किए गए बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल हैं।

माल्या और नीरव के खिलाफ आरोप

विजय माल्या पर भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एक संघ से उनकी अब बंद हो चुकी किंगफिशर एअरलाइंस के लिए लिए गए 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण में धोखाधड़ी का आरोप है। नीरव मोदी पर अपने चाचा मेहुल चोकसी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के खिलाफ 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। यह भारत के इतिहास में सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक है।

एफईओए की सूची में कौन-कौन शामिल है?

एफईओए सूची में जिन लोगों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है, वे हैं : विजय माल्या, नीरव मोदी, नितिन जे संदेसरा, चेतन जे संदेसरा, स्टर्लिंग बायोटेक धोखाधड़ी मामले की दीप्ति सी संदेसरा, सुदर्शन वेंकटरमण, रामानुजम शेषरत्नम, आइलाम सिस्टम्स लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर पुष्पेश कुमार बैद और हितेश कुमार नरेंद्रभाई पटेल। नितिन और चेतन संदेसरा ने इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया और स्टेट बैंक आफ इंडिया के साथ कुछ बकाया राशि का निपटारा कर लिया है।

सुप्रीम कोर्ट से राहत

पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने स्टर्लिंग बायोटेक बैंक धोखाधड़ी मामले में संदेसरा भाइयों के खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का निर्देश दिया, बशर्ते वे ऋणदाता बैंकों को 5,100 करोड़ का पूर्ण और अंतिम भुगतान जमा कर दें। अदालत ने कहा, यदि याचिकाकर्ता (संदेसरा बंधुओं) एकमुश्त निपटान (ओटीएस) में तय की गई राशि जमा करने के लिए तैयार हैं और सार्वजनिक धन उधार देने वाले बैंकों को वापस मिल जाता है तो आपराधिक कार्यवाही जारी रखने का कोई फायदा नहीं होगा। इससे यह अंदेशा पैदा हुआ कि क्या सरकार भविष्य में ऐसे अपराधियों को देश छोड़ने से रोकने के लिए कानूनी प्रतिबंधों या निगरानी सूचियों के माध्यम से कोई नीति बना रही है, तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वर्तमान में ऐसी कोई नीति तैयार नहीं की जा रही है।

पांच साल में 134 भगोड़ों को वापस लाने में सीबीआइ को सफलता यूं ही नहीं मिल गई है। इसमें नई तकनीक और कूटनीतिक प्रयासों का भी खासा योगदान रहा है। सफलता दर में वृद्धि का श्रेय सरकार द्वारा बढ़ाए गए राजनयिक जुड़ाव, सीबीआइ की यात्राओं के माध्यम से भारत की पहुंच, द्विपक्षीय संबंधों, तकनीकी प्रगति और इंटरपोल के साथ बेहतर समन्वय को दिया जा सकता है। सीबीआइ ने अपने नए डिजिटल पोर्टल भारतपोल के माध्यम से इंटरपोल के साथ समन्वय बढ़ाया है। इससे भगोड़ों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तेज हुई है। एजंसी द्वारा आंतरिक रूप से विकसित यह मंच भारतीय पुलिस एजंसियों को सीबीआइ के माध्यम से इंटरपोल से जोड़ता है। इससे जांच और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में तेजी आई है और रेड नोटिस जारी होने में लगने वाला औसत समय छह महीने से घटकर तीन महीने रह गया है।

> **हाल** में सीबीआइ ने अमेरिका में नेहल मोदी को गिरफ्तार करवाया, जो नीरव मोदी का भाई है और पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी है। वहीं, सीबीआइ ने एक आर्थिक अपराधी मोनिका कपूर को भी अमेरिका से प्रत्यर्पित करवाया, जो 1999 में फरार हो गई थी।

हाल ही में सीबीआइ ने अमेरिका में नेहल मोदी को गिरफ्तार करवाया, जो नीरव मोदी का भाई है और पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी है। यहीं, सीबीआइ ने एक आर्थिक अपराधी मोनिका कपूर को भी अमेरिका से प्रत्यर्पित करवाया, जो 1999 में फरार हो गई थी। वहीं, सीबीआइ ने कई साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसके अलावा, सीबीआइ देश से भागे हुए अपराधियों को वापस लाने के लिए आपरेशन त्रिशूल चला रही है।

प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के तीन चरण होते हैं- इंटरपोल द्वारा रेड नोटिस जारी करना, भगोड़े की भौगोलिक स्थिति का पता लगाना, और तीसरा, कानूनी और कूटनीतिक प्रयासों के बाद प्रत्यर्पण। ये सभी प्रक्रियाएं समय लेने वाली हैं। इंटरपोल रेड नोटिस जारी करके किसी देश में वांछित भगोड़े के बारे में सभी 195 देशों को सचेत करता है। इधर सरकार और केंद्रीय एजंसियां कोशिश कर रही हैं कि भगोड़े अपराधियों को लाने के लिए समन्वय बढ़े और मजबूत किया जाए। पिछले दिनों एक बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फरार अपराधियों के लिए सभी राज्य सरकारों से राज्य की राजधानी में एक विशेष प्रकोष्ठ गठित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकोष्ठों की अनुपस्थिति हमेशा अपराधियों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में चुनौतियां पैदा करती है। जानकारों का कहना है कि सभी राज्यों की राजधानियों में भगोड़ों के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ होना चाहिए, जो अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करता हो। कई बार, अंतरराष्ट्रीय भगोड़ों के लिए ऐसे प्रकोष्ठ का अभाव विदेशी अदालतों में मुद्दा बन जाता है। राज्य सरकारों को ऐसा प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए ताकि कोई भी बहाना न बन सके।

विशेषज्ञों का कहना है कि कायदे से फरार आरोपियों का एक वैज्ञानिक डेटाबेस सभी राज्य पुलिस के साथ साझा किया जाना चाहिए और आइबी व सीबीआइ को इस दिशा में काम करना चाहिए। सीबीआइ और आइबी को राज्यों को ऐसे डेटाबेस बनाने में मार्गदर्शन करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। डेटाबेस में फरार लोगों के खिलाफ मामले, उनके फरार होने के स्थान, भारत में उनका नेटवर्क और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में आई रुकावट सहित सभी विवरण होने चाहिए।

जानकारों के मुताबिक नशीले पदार्थ, गिरोहबाजी, जबरन वसूली और वित्तीय अपराधों के साथ-साथ साइबर अपराधों की जांच के लिए एक केंद्रित समूह का गठन किया जाना चाहिए, जहां सूचना एवं प्रसार ब्यूरो (आइबी) और सीबीआइ एक बहु एजंसी केंद्र (एमएसी) की मदद से प्रक्रिया में मार्गदर्शन करें।

केंद्रीय एजंसियों, विदेश और गृह मंत्रालयों के कार्यक्रम में गृह मंत्री शाह ने कहा था कि किसी व्यक्ति के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी होने के बाद, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाना चाहिए, ताकि वह विदेश भाग सके। भगोड़े को भारत के कानूनों से डरना चाहिए। शाह ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के अनुच्छेद 355 और 356 (अनुपस्थिति में मुकदमे के मुद्दे से संबंधित हैं), का उपयोग राज्यों द्वारा भगोड़ों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, सीबीआइ की मदद से, सभी राज्यों को राज्य-विशिष्ट भगोड़ों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के लिए इकाइयां स्थापित करनी चाहिए।

नीरव मोदी और नितिन संदेसरा

मेहुल चौकसी, विजय माल्या, चेतन संदेसरा

संदेसरा बंधुओं को मिली छूट के संदेश पर चिंता

पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े संदेसरा भाइयों के खिलाफ मामले वापस लेने पर सहमति जताई थी। शर्त यह थी कि वे 5,100 करोड़ रुपए का पूर्ण और अंतिम भुगतान करें। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि इस आदेश को मिसाल के तौर पर नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े संदेसरा बंधुओं को 1.6 अरब अमेरिकी डालर के बैंक धोखाधड़ी मामले में 5,100 करोड़ रुपए का भुगतान करके समझौता करने की अनुमति दे दी और सभी कार्यवाही रद्द कर दी।

इससे यह बहस छिड़ गई कि क्या बड़े आर्थिक अपराधी छूट को खरीद सकते हैं। कानूनी विशेषज्ञ और ईडी को चिंता है कि इससे माल्या और मोदी जैसे अन्य भगोड़ों को भी ऐसे समझौते करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर को स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड के प्रमोटर संदेसरा बंधुओं और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ सभी दीवानी और आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की, बशर्ते वे 17 दिसंबर तक या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को 5,100 करोड़ रुपए जुर्माने और ब्याज सहित कुल कथित धोखाधड़ी राशि का लगभग एक तिहाई पूर्ण और अंतिम भुगतान के रूप में जमा कर दें।

साल 1985 में स्थापित स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड गुजरात स्थित संदेसरा समूह की कंपनी है। इसका स्वामित्व नितिन और चेतन जयंतीलाल संदेसरा भाइयों के पास है। दोनों भाइयों की एक और कंपनी है। इसका नाम स्टर्लिंग आयल एक्सप्लोरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन लिमिटेड है। इसकी स्थापना साल 2003 में हुई थी और इसका मुख्यालय नाइजीरिया में है। संदेसरा परिवार 2017 में अल्बानियाई पासपोर्ट पर भारत छोड़कर चला गया क्योंकि उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआइओ) और आयकर विभाग सहित कई एजंसियों द्वारा ऋण धोखाधड़ी के कई आरोपों का सामना करना पड़ रहा था। साल 2020 में, उन्हें साल 2018 के एक कानून के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। इसके तहत दीवानी मुकदमों में भाग लेने की उनकी क्षमता भी निलंबित कर दी गई और संपत्तियों की कुर्की अनिवार्य कर दी गई।

उनके खिलाफ मामले की बात करें तो, इसमें 5,383 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण शामिल हैं। सीबीआइ के अनुसार, इस पैसे को मुखौटा कंपनियों के जरिए संदेसरा बंधुओं के विदेशों में व्यापारिक संचालन और निजी जेट और महंगी अचल संपत्ति सहित निजी विलासिता वाली संपत्तियों को निधि देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। सीबीआइ ने साल 2017 में कथित धोखाधड़ी की राशि 5,383 करोड़ रुपए बताई थी। समय के साथ, जुर्माने और ब्याज के चक्रवृद्धि होने से बैंकों को देय कुल राशि में काफी वृद्धि हुई, और ईडी के अनुमान के अनुसार अब धोखाधड़ी की कुल राशि 16,000 करोड़ रुपए या लगभग 1.6 अरब अमेरिकी डालर से अधिक है।

न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई ने अपने आदेश में कहा कि कार्यवाही की सामान्य भावना सार्वजनिक धन की रक्षा करने और गबन की गई राशि को वापस पाने के इरादे को दर्शाती है और चूंकि सार्वजनिक धन उधारदाताओं को लौटाया जा रहा था, इसलिए भाइयों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय, जिसने संदेसरा परिवार से जुड़ी कंपनियों की 14,550 करोड़ रुपए की अचल और चल संपत्तियों को जब्त किया था, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में पक्षकार नहीं था। हालांकि, सीबीआइ ने 2017 में संदेसरा परिवार और उनकी कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। प्रवर्तन निदेशालय का मानना है कि संदेसरा को खुद को मुसीबत से बाहर निकालने की अनुमति देने वाले आदेश का संदर्भ अन्य भगोड़े आर्थिक अपराधियों द्वारा दिया जा सकता है।

समस्या देश में बाघों की मौत का सिलसिला नहीं थमा, दस वर्षों में देश में 1,256 बाघों की जान गई

इस वर्ष अब तक 157 बाघों की जान गई

सुशील राघव
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

देश में वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों के बावजूद बाघों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष 12 दिसंबर तक देश में 157 बाघों की मौत दर्ज की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में यह संख्या 31 अधिक है। वर्ष 2024 में कुल 126 बाघों की मौत हुई थी।

आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश एक बार फिर सबसे अधिक बाघों की मौत वाला राज्य रहा है। यहां 52 बाघों ने इस वर्ष अब तक दम तोड़ा है, जो कुल मौतों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है। इसके बाद महाराष्ट्र 37 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि कर्नाटक में 14, केरल में 13, असम में 12 और तमिलनाडु में 10 बाघों की मौत हुई है। एनटीसीए के अनुसार, मरने वाले बाघों में 30 शावक और 40 मादाएं शामिल हैं, जिससे यह चिंता और बढ़ गई है कि भविष्य में बाघों की आबादी पर इसका असर पड़ सकता है। देशभर में बाघों की सुरक्षा को लेकर कई अभयारण्य और टाइगर रिजर्व सक्रिय हैं, लेकिन मानव हस्तक्षेप, अवैध शिकार, क्षेत्रीय संघर्ष और बीमारियां अभी भी बाघों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। पिछले दस वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में कुल 1,256 बाघों की मौत दर्ज की गई है। इनमें वर्ष 2023 सबसे घातक रहा। वर्ष 2016 के बाद से हर वर्ष 100 से अधिक बाघों की मौत दर्ज की गई है। केवल 2019 ऐसा वर्ष रहा, जब बाघों की मौत का आंकड़ा 100 से नीचे (95) रहा।

पिछले एक दशक के आंकड़े बताते हैं कि 2016 में 121, 2017 में 117, 2018 में 101, 2019 में 95, 2020 में 106, 2021 में 129, 2022 में 122, 2023 में 182 और 2024 में 126 बाघों की मृत्यु हुई थी।

मध्य प्रदेश एक बार फिर सबसे अधिक बाघों की मौत वाला राज्य रहा है। यहां 52 बाघों ने इस वर्ष अब तक दम तोड़ा है, जो कुल मौतों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है। इसके बाद महाराष्ट्र 37 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि कर्नाटक में 14, केरल में 13, असम में 12 और तमिलनाडु में 10 बाघों की मौत हुई है।

वर्ष	बाघों की मौत	वर्ष	बाघों की मौत
2025	157	2018	101
2024	126	2017	117
2023	182	2016	121
2022	122	2015	82
2021	129	2014	78
2020	106	2013	68
2019	95	2012	88

Jansatta Page No-7

बांग्लादेश में चुनाव से पहले भड़की हिंसा, नकेल कसने को 'आपरेशन डेविल हंट-2'

ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश में मो. यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अगले वर्ष फरवरी में होने वाले चुनावों से पहले नए सिरे से भड़की हिंसा को रोकने की जरूरत का हवाला देते हुए देश भर में 'आपरेशन डेविल हंट' का दूसरा चरण शुरू करने का निर्णय लिया है। हाल ही में 'इंकलाब मंच' के नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या की कोशिश के बाद अवैध हथियारों के प्रयोग से होने वाली विध्वंसक गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से अंतरिम सरकार ने शनिवार को देशव्यापी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का आदेश दिया।

ढाका में पत्रकारों को संबोधित करते हुए अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर हुई कोर कमेटी की बैठक के बाद इस निर्णय की घोषणा की। यह बैठक हादी पर प्रचार के दौरान फायरिंग के एक दिन बाद आयोजित की गई थी। मीडिया रिपोर्टों के

- नेता को गोली मारे जाने की घटना के बाद युनुस सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का दिया आदेश
- पूर्व मंत्री पर हमले के विरोध के बाद फरवरी, 2025 में पहली बार 'आपरेशन डेविल हंट' शुरू किया था

प्रतीकात्मक

अनुसार, उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) जहांगीर आलम चौधरी ने एक प्रेस कान्फ्रेंस में बताया, "सरकार जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवैध हथियारों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए 'आपरेशन डेविल हंट' का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है।" अंतरिम सरकार ने राजधानी के उत्तरी उपनगर में एक पूर्व मंत्री के निजी घर पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शनों के बाद इस साल फरवरी में पहली बार 'आपरेशन डेविल हंट' शुरू किया था। इस अभियान में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अब प्रतिबंधित हो चुकी अवामी लीग के कथित समर्थकों को निशाना बनाया गया था।

जहांगीर आलम चौधरी ने हादी को गोली मारने वाले संदिग्ध की सूचना देने वाले को 50 लाख टका के इनाम की घोषणा की है। इस बीच, पुलिस ने संदिग्ध की तस्वीरें जारी कर उसकी पहचान फैसल करीम मसूद के रूप में की है। वह उन तीन मोटरसाइकिल सवार हमलावरों में से एक था, जिसने बिजोयनगर में हादी के सिर में करीब से गोली मारी थी। बिजोयनगर में युवा नेता हादी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं।

Dainik Jagaran Page No-11

इमरान की एकांत कारावास की सजा को शीघ्र समाप्त किया जाए : यूएन विशेषज्ञ

इस्लामाबाद, प्रेट्र : संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के एक विशेषज्ञ ने पाकिस्तान सरकार से अगस्त, 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में कई मामलों में बंद 73 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के संस्थापक इमरान खान की 'अमानवीय और अपमानजनक हिरासत स्थितियों' की रिपोर्टों पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक एलिस जिल एडवर्ड्स ने कहा कि लंबे समय तक या अनिश्चितकालीन एकांत कारावास अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत निषिद्ध है, और जब यह 15 दिनों से अधिक समय तक चलता है तो यह मनोवैज्ञानिक यातना का एक रूप है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकाय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, एडवर्ड्स ने कहा, 'मैं पाकिस्तानी अधिकारियों से आग्रह करती हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि इमरान की हिरासत की शर्तें अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और मानकों के पूरी तरह अनुरूप हों। इमरान की एकांत कारावास की सजा को बिना किसी देरी के समाप्त किया जाना चाहिए। यह न केवल गैरकानूनी उपाय है, बल्कि लंबे समय तक एकांतवास से उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं।' प्राप्त जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के संस्थापक इमरान को उस एकांत कोठरी से बाहर निकलने या अन्य बंदियों से मिलने की भी अनुमति नहीं है। वह अन्य लोगों के साथ नमाज अदा करने में भी शामिल नहीं हो सकते। आरोप यह भी है कि वकीलों, परिवार के सदस्यों और अदालतों द्वारा अधिकृत अन्य लोगों को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री मोहम्मद शोएब अफरीदी ने आरोप लगाया कि इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के साथ जेल में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उनकी यह टिप्पणी तब आई जब गुरुवार को अदियाला जेल प्रशासन ने उन्हें दसवीं बार इमरान से मिलने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया।

- पाकिस्तान सरकार से 'अमानवीय हिरासत स्थितियों' की रिपोर्टों पर तत्काल कार्रवाई करने का किया आह्वान
- कहा- लंबे समय तक, अनिश्चितकालीन एकांत कारावास अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत निषिद्ध

इमरान खान। फाइल

पीटीआइ ने किया 23 सदस्यीय नई राजनीतिक समिति का गठन

इस्लामाबाद, एएनआइ : पाकिस्तान के प्रमुख अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी ने 23 सदस्यीय पुनर्गठित राजनीतिक समिति की घोषणा की है और एक औपचारिक अधिसूचना जारी की है जिसमें विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर को इससे बाहर रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इमरान खान ने पार्टी महासचिव सलमान अकरम राजा को एक नई राजनीतिक समिति गठित करने का निर्देश दिया था।

Dainik Jagaran Page No-11

Useful For Mains

सूचनाओं का विस्फोट और शहरों का शोर दिलोदिमाग को बेचैन बना रहा है। शायद इसीलिए इन दिनों साइलेंट वॉक, साइलेंट रिट्रीट या हीलिंग ट्रैवल जैसी गतिविधियां ट्रेंड में हैं, क्योंकि 'मौन' के पल मिलना भी अब लग्जरी है। अतिशय शोर में लंबे समय तक रहना शरीर को भी तोड़ देता है। इन सबका नतीजा ये है कि खास शांति और सुकून देने वाले समाधानों का बाजार भी बन रहा है। क्या है मौन की मजबूती, कैसे इसे जीवन में उतारें, बता रही हैं किरण मिश्रा

मौन से मिलता मनोबल

110

डेसिबल से अधिक हो जाता है शोर, त्योहारों या विशेष आयोजनों के दौरान बड़े शहरों में। जबकि दिन और रात के लिए क्रमशः 55 व 45 डेसिबल मानक सीमा है।

40%

से ज्यादा घूमने जाने वाले, ऐसी छुट्टियां पसंद करते हैं, जो प्रकृति में डूबने और आत्मखोज का मौका दें, एक अध्ययन के अनुसार

चौबीसों घंटे चलने वाली खबरों की गूंज, हर कुछ मिनट में मिलने वाले फोन के नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की अंतहीन सूचनाएं और महानगरों की न थमने वाली हलचल..., हमारा हर दिन शोर से घिरा हुआ है। सुबह आंख खुलते ही न्यूज चैनल्स और एप्स हमें ब्रेकिंग अपडेट्स से भर देते हैं, सोशल मीडिया हमें लाइक्स-कमेंट्स की दौड़ में उलझा देता है। अगर हम इन डिजिटल शोर से बच भी जाएं, तो शहर का न थमने वाला शोर हमें घेर लेता है। युवा, खासकर जेन जी सूचनाओं के निरंतर ओवरलोड, नोटिफिकेशन व सोशल मीडिया के दबाव के माहौल में बड़े हुए हैं, उनके लिए अब सूचनाओं तक अति पहुंच उनको थकाने लगी है। इसलिए वे शोर के बीच सुकून की तलाश में लग गए हैं। मानो, मौन उनके लिए कोई लग्जरी की चीज हो। यहीं से शुरू होता है बाजार का खेल, जो भावनात्मक बोझ को भुनाने के लिए साइलेंट रिट्रीट, हीलिंग ट्रैवल के नाम पर महंगी थेरेपी वैकेशन्स ऑफर कर रहे हैं। मतलब, सुकून को अब बाजार ने एक प्रीमियम पैकेज डील में बदल दिया है।

सुकून में निवेश

- न पॉडकास्ट, न टीवी, न बेवजह की सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग। कमरे में बस एक सन्नाटा। अधिकतर शामों में कुछ ऐसा ही चाहिए होता है मुझे अपने कमरे में, जब मैं ऑफिस से लौटता हूं। पूरे दिन की थकान के बाद कुछ देर बिल्कुल चुप रहना मुझे सुकून देता है।' यह कहना है सेल्स से जुड़े 24 वर्षीय नवनीत का, जिन्होंने कुछ महीने पहले हैदराबाद में नौकरी शुरू की है।
- 'मैं दिल्ली के एक ऐसे इलाके में रहता हूं, जहां दिन भर गाड़ियों की आवाज कानों में आती रहती है। ऐसे में छुट्टी के दिन बस अपनी किताब के साथ कुछ पल चुपचाप बिताना चाहता हूं। इसलिए रविवार को अक्सर मैं लाइब्रेरी कैफे चला जाता हूं, जहां सिर्फ सन्नाटा, कॉफी की खुशबू और पन्नों की सरसराहट होती है।' यह कहना है 22 वर्षीय आदित्य भारद्वाज का, जो एक छोटे से शहर से दिल्ली पढ़ने आए हैं।
- 'जब भी मुझे ऑफिस में काम का बोझ

मौन से मन की सफाई

श्रीबालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट, साइकायट्री के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. प्रशांत गोयल कहते हैं, 'बाहरी शोर, भागदौड़, फोन के नोटिफिकेशन, काम का दबाव, ये सब दिमाग को आराम नहीं करने देते। जिससे भावनात्मक सेहत खराब हो रही है। नतीजा है गुस्सा, तनाव, अवसाद। ऐसे में मौन रहना यानी कुछ समय बिना बोले, बिना स्क्रीन, बिना मानसिक शोर के बिताना दिमाग को रीसेट करने में मदद करेगा। इससे हमारा दिमाग ओवरथिंकिंग से बाहर आता है, तनाव व गुस्सा कम होने लगता है। नींद बेहतर होती है, साथ ही ध्यान लगाने की क्षमता भी बढ़ती है। हालांकि, यह तभी लाभ देगा, जब इसे सही तरीके से किया जाए, जैसे दिन में 10-15 मिनट सिर्फ शांत बैठना, गहरी सांसें लेना और खुद को किसी भी तरह के रिएक्शन से रोकना। शुरुआत मुश्किल लगे तो फोन को साइलेंट रखें, आंखें बंद करें और बस अपनी सांसों पर फोकस करें। धीरे-धीरे आप 30 मिनट या हफ्ते में एक बार 2-3 घंटे तक भी ऐसा कर सकते हैं। यह कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं, मानसिक डिटॉक्स का तरीका है।

दिखाता है कि हमारा दिमाग शायद ही कभी आराम कर पाता है। जाहिर है युवा सोशल मीडिया की लगातार तुलना, छूट जाने का डर व भागदौड़ की संस्कृति से जूझ रहे हैं, जिससे उनमें भावनात्मक थकान बढ़ रही है। यहीं शादियां अब कानफोड़ू हो गई हैं। त्योहारों में स्पीकर्स, सड़कों पर तेज हॉर्न, रैलियां...सब शोर क्षेत्र बन गए हैं। इस तरह हर पांच में से एक इंसान सड़क का शोर झेलने को मजबूर है। महानगरों में उत्सवों के दौरान 100-115 डेसीबल तक शोर पहुंच जाता है। यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी और डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार, शोर केवल सुनने की समस्या नहीं, बल्कि यह नींद, ध्यान और महसूस होने लगी है, इसलिए वे अपनी दिनचर्या में सुकून के पल तलाशने लगे हैं। मौन हमें खुद से जोड़ता है, हमारी अति तेज रफ्तार को थोड़ा धीमा करता है और यह एहसास कराता है कि हर जवाब शब्दों में नहीं, कई बार शांति में भी मिलता है।

मौन या कहें सुकून, एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन गया है, तभी तो बाजार में शोर निवारक हेडफोन, व्हाइट नॉइज मशीन खूब बिक रहे हैं। बेंगलुरु और सैन फ्रांसिस्को की तकनीकी कंपनियां अब साइलेंट जोन डिजाइन कर रही हैं, जहां कर्मचारी बिना किसी बाधा के सोच सकें और काम कर सकें।

शांति के ठिकाने

निकिता सक्सेना कहती हैं, 'जब मेरा एक दोस्त दस दिन की मौन रिट्रीट से लौटा और अपने अनुभव साझा किए, तो मैंने भी इसे आजमाने का फैसला किया। मैंने घर पर ही अपना रिट्रीट किया। नतीजा, एक अद्भुत अनुभव। मुझे एहसास हुआ कि मेरी कई आदतें सिर्फ व्यस्त रहने की जरूरत से प्रेरित थीं। पांच दिन बिना फोन, बिना बातचीत के गुजरे। हालांकि, शुरुआत में डर लगा, पर लंबे मौन ने मुझे बाहरी आग्रहों और अपने काम के बीच दूरी बनाना सिखाया। मैंने छोटे-छोटे पलों की खूबसूरती को गहराई से महसूस किया, जैसे खिड़की से बाहर आकाश को निहारना, पक्षियों की चहचहाहट सुनना, भोजन के स्वाद का आनंद लेना। ये वे चीजें थीं, जिसे हम व्यस्त जीवन में अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह अनुभव मेरे लिए एक रीसेट बटन जैसा था।'

दरअसल, सुकून की इसी चाहत में युवा, खासकर जेन जी मौन यात्राओं की ओर बढ़ रहे हैं। क्लबिंग और सोशल मीडिया की भागदौड़ छोड़ ये विपश्यना केंद्रों, मठों और प्रकृति की गोद में मानसिक शांति खोज रहे हैं। इस तरह मौन एक स्टेटस सिंबल के रूप में सामने आ रहा है, जहां संपन्न शहरी अब दूर-दराज के इलाकों में हजारों रुपए देकर प्रति सप्ताह के लिए डिजिटल डिटॉक्स रिट्रीट बुक कर रहे हैं।

शांत रहें दो घंटे

शोध के अनुसार रोजाना दो घंटे का मौन मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस में नई कोशिकाओं के विकास को बढ़ाता है, जो सीखने और याददाश्त से जुड़ा है। यह कार्टिसोल स्तर घटाकर तनाव कम करता है, इसलिए हृदय रोग विशेषज्ञ उच्च रक्तचाप के मरीजों को प्रकृति में शांतिपूर्ण सैर की सलाह देते हैं। यानी मौन सिर्फ मन की नहीं, दिमाग की ताकत भी है। आपको हैरानी होगी कि पिछले साल 'शांत जीवन' देने वाली जगहों की खोज में 530% की वृद्धि हुई है। आप मौन को अपनी जिंदगी में ऐसे जगह दे सकते हैं-

- तकनीक के साथ सीमाएं निर्धारित करें। जागने के बाद कुछ देर तक बिना फोन उठाए बिताएं।
- रोजाना ध्यान करने की आदत बनाएं।
- ग्राउंडिंग का अभ्यास करें। जैसे चाय को सजगता से पीना या अपने आसपास के रंग, बनावट और सुगंध आदि को नोटिस करना।
- प्रकृति में बिना उपकरणों के रोजाना कुछ मिनट समय बिताएं। घास पर नंगे पांव चलें, बिना संगीत, बिना कॉल आदि के।
- खुद को सुकून देने वाले कामों से जोड़ें, जैसे डायरी लिखना, रचनात्मक खेल से जुड़ना आदि।

Hindustan Page No-19

जीना इसी का नाम है

श्वेता अग्रवाल
आर्किटेक्ट, सामाजिक कार्यकर्ता

हजारों सपनों को श्वेता ने अपनी सेवा से बचा लिया

आज श्वेता की बदौलत हाशिये पर जीने वाले समाज के 3,800 बच्चों को सुखद दिशा मिल चुकी है। इस बीच उन्होंने निजी जिंदगी में विलगाव का दुख भी झेला, लोगों से गरीब बच्चों के अंग बेचने जैसे आरोप भी झेले, पर वह अपने ईमान और साथियों के साथ लक्ष्य की राह पर चलती जा रही हैं।

बरसों पहले किसी शख्सीयत के बारे में एक जुमला पढ़ा था- वह गिरे, उठे, फिर गिरे और अब जो उठे, तो हजारों उनके संग उठ गए। श्वेता अग्रवाल के सफरनामे को पढ़ते हुए अनायास वह जुमला याद हो आया। श्वेता का "उन्मुक्त फाउंडेशन" भुवनेश्वर के हजारों गरीब बच्चों के लिए एक ऐसा प्रकाश-स्तंभ साबित हुआ है, जिसकी रोशनी से उनका पूरा जीवन आलोकित हो उठा है। श्वेता जैसी बेटियों पर पूरे समाज और देश को नाज होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के हापुड़ का एक अग्रवाल परिवार दशकों पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आ बसा था। उसी निम्न मध्यवर्गीय परिवार में आज से 41 साल पहले श्वेता पैदा हुईं। पिता स्थानीय जेसी मिल्स में काम करते थे और मां गृहिणी थीं। हर माता-पिता की तरह उन्होंने भी शहर के एक अच्छे स्कूल में अपने दोनों बच्चों (श्वेता व उनके बड़े भाई) का नाम लिखवाया था। श्वेता पढ़ने में काफी अच्छी थीं, मगर नन्हे बच्चों को कहां पता होता है कि माता-पिता कितनी मुश्किलों से उनकी जरूरतें जुटाते हैं! पिता जिस फैक्टरी में काम करते थे, वह अचानक बंद हो गई। अग्रवाल परिवार के लिए यह किसी मुसीबत से कम न था। आखिर उसी नौकरी की बदौलत पूरा परिवार चल रहा था। कुछ सोच-विचार के बाद पिता ने दिल्ली की ट्रेन पकड़ी, ताकि वहां छोटा-मोटा कारोबार करके परिवार चलाया जाए। दिल्ली पहुंचकर साझेदारी में उन्होंने ड्रॉइंग बॉक्स इंस्ट्रूमेंट्स बनाने की एक फैक्टरी डाली। काम चल निकला। जब मुनाफा आने लगा, तो वही हुआ, जो अक्सर साझेदारों के कारोबार में होता है। श्वेता के पिता दगाबाजी के शिकार हो गए।

जाहिर है, इन सबका असर परिवार और बच्चों पर पड़ना ही था। श्वेता और उनके भाई की स्कूल फीस में देरी होने लगी थी। श्वेता तब कक्षा सात में थीं। एक दिन फीस न चुकाने के कारण स्कूल की वाइस प्रिंसिपल ने सभी बच्चों के सामने श्वेता और उनके भाई को बहुत अपमानित किया। उस लंच टाइम को वह आज तक नहीं भूल सकीं। वाइस प्रिंसिपल ने न सिर्फ उनके पिता की आर्थिक स्थिति का उपहास उड़ाया, बल्कि लंच के बाद उन दोनों को कक्षा में बैठने तक की इजाजत नहीं दी थी। आहत श्वेता ने उसी दिन अपनी मां से कहा था- अगर मैं जिंदगी में इतनी सक्षम हुई कि मदद कर सकूं, तो कभी किसी बच्चे को इस तकलीफ से गुजरने नहीं दूंगी।

यह एक बेटी का अपनी मां के साथ-साथ खुद से किया गया वादा था। स्कूल बदल गया था, मगर कुछ बनने का जुनून बढ़ता चला गया। श्वेता अच्छे नंबरों से कक्षाएं पास करती गईं। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि अपने माता-पिता पर वह अपनी उच्च शिक्षा का बोझ नहीं पड़ने देंगी, इसलिए जब ग्वालियर के एमआईटीएस कॉलेज में आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम के लिए उनका चयन हुआ, तो उन्होंने एजुकेशन

लोन लेकर और पार्ट टाइम काम करके इसकी फीस अदा की।

उन दिनों अच्छे आर्किटेक्ट को कॉरपोरेट कंपनियां हाथोंहाथ लेती थीं। साल 2007 में दिल्ली की एक कॉरपोरेट कंपनी से श्वेता ने अपने करियर की शुरुआत की। कॉलेज के दिनों के साथी को जीवनसाथी बनाने का फैसला किया, तो माता-पिता भरपूर आशीर्वाद लिए साथ आ खड़े हुए। पति भी कॉरपोरेट दुनिया का ही हिस्सा थे। शादी के कुछ साल बाद दोनों कोलकाता चले आए थे, मगर कॉरपोरेट क्षेत्र की भागदौड़ भरी जिंदगी दोनों को रास नहीं आ रही थी। लिहाजा, श्वेता और उनके पति ने फैसला किया कि किसी छोटे शहर में चलकर बसा जाए। चूंकि श्वेता के पति ओडिशा के थे, इसलिए वे दोनों भुवनेश्वर चले आए। भुवनेश्वर पहुंचते ही श्वेता को एक अस्पताल में प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट का अहम ओहदा मिल गया था। उन दिनों देश में हॉस्पिटल डिजाइन की समझ रखने वाले आर्किटेक्ट बहुत कम थे। बहुत छोटी उम्र से काम करती आ रहीं श्वेता को अपनी नौकरी से बहुत संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी, लिहाजा एक दिन नौकरी से इस्तीफा देकर वह जिंदगी का मकसद समझने के लिए भारत भ्रमण पर निकल पड़ीं। इस दौरान उन्होंने लद्दाख से लेकर नेपाल तक की यात्रा की।

यात्रा से लौटकर उन्होंने नई नौकरी ज्वॉइन कर ली थी, क्योंकि सारे पैसे खर्च हो गए थे। साल 2015 की दीवाली की रात श्वेता अपने पति के साथ भुवनेश्वर की मुंडा साही बस्ती से गुजर रही थीं। वह बस्ती घुप्प अंधेरे में डूबी हुई थी। यह बात श्वेता को चुभ गई थी। 2016 में उन्होंने इस त्योहार के आने पर दीये व तेल के कई पैकेट बनाए और दीवाली की पहली रात चुपचाप उनके दरवाजे पर रखकर लौट रही थीं कि कुछ बच्चों ने उन्हें घेर लिया। श्वेता उड़िया नहीं जानती थीं। पहले कुछ डर लगा। मगर फिर बच्चों ने इतना अच्छा व्यवहार किया कि उन्हें लगा कि इनके साथ कुछ काम करना चाहिए।

जनवरी में श्वेता ने वहां एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की। विषय था- मेरा सपना, मेरी दुनिया। मानस नाम के एक बच्चे ने हवाईअड्डे का बेहद सुंदर चित्र बनाया, उसका सपना पायलट बनने का था। श्वेता जानती थीं कि इन बच्चों के सपने बेमौत मर जाएंगे, क्योंकि उनके अभिभावक उन्हें इसके लिए जरूरी शिक्षा नहीं दिला सकेंगे। श्वेता ने इन बच्चों को उड़ने के लिए पंख देने का फैसला किया। उन्हें खुद को व्यक्त करने के लिए एक रचनात्मक केंद्र के रूप में उन्होंने 'उन्मुक्त' की शुरुआत की, जिसे बाद में गैर-लाभकारी संस्था 'उन्मुक्त फाउंडेशन' का रूप दिया गया।

फीस न देने के कारण वाइस प्रिंसिपल ने सभी बच्चों के सामने श्वेता और उनके भाई को बहुत अपमानित किया। उस लंच टाइम को वह आज तक नहीं भूल सकी हैं। वाइस प्रिंसिपल ने न सिर्फ उनके पिता की आर्थिक स्थिति का उपहास उड़ाया, बल्कि लंच के बाद उन दोनों को कक्षा में बैठने तक की इजाजत नहीं दी थी।

आज श्वेता और उन्मुक्त फाउंडेशन की बदौलत हाशिये पर जीने वाले समाज के 3,800 बच्चों को जीने की सार्थक दिशा मिल चुकी है। इस बीच निजी जिंदगी में उन्होंने 14 वर्षों के सुखद दांपत्य जीवन के बाद विलगाव का अवसाद भी झेला, लोगों से गरीब बच्चों के अंग निकालकर बेचने जैसे हास्यास्पद आरोप भी झेले, मगर वह अपने ईमान और साथियों के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ती रहीं, बढ़ती जा रही हैं।

प्रस्तुति : चंद्रकांत सिंह

Hindustan Page No-10

अध्ययन | उत्तराखंड के तीन प्रमुख भू-वैज्ञानिकों के संयुक्त शोध से खुलासा, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में प्रकाशित शोध से चेताया

जलवायु परिवर्तन से ज्यादा मानव जनित हैं आपदाएं

■ शैलेन्द्र सेमवाल

देहरादून। उत्तराखंड के तीन प्रमुख भू-वैज्ञानिकों ने हिमालय क्षेत्र में आपदाओं को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में प्रकाशित इन भू-वैज्ञानिकों के संयुक्त शोध के अनुसार, हिंदुकुश क्षेत्र में आपदाओं की जिम्मेदार केवल जलवायु परिवर्तन और मौसम का बदलता पैटर्न नहीं है। इसके लिए मानवीय हस्तक्षेप, जैसे- अनियोजित निर्माण और बस्तियां, प्रमुख वजह हैं।

भू-वैज्ञानिकों ने चेताया कि यदि उत्तराखंड में फ्लड प्लेन जोनिंग ऐक्ट सख्ती से लागू नहीं किया गया तो धराली और केदारनाथ की आपदाओं जैसी घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ेगी। यह शोध दून विश्वविद्यालय के डॉ.नित्यानंद हिमालयन रिसर्च एंड स्टडी सेंटर के जियोलॉजी विभाग के डॉ. यशपाल सुंदरियाल, भरसार विश्वविद्यालय के डॉ. एसपी सती और भू-वैज्ञानिक डॉ. नवीन जुयाल द्वारा तैयार किया गया है।

हाल में जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, बेंगलुरु में प्रकाशित इस शोध के अनुसार, बढ़ती आबादी के कारण लोग नदियों के किनारे या अस्थिर ढलानों पर बसने को मजबूर हो रहे हैं। व्यावसायिक गतिविधियां और हाईवे निर्माण भी बाढ़ के मैदानों को प्रभावित कर रहे हैं।

2010 के बाद हिंदुकुश क्षेत्र में खतरा बढ़ा

हिंदुकुश क्षेत्र में आपदाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इस साल मानसून में पूरा हिंदुकुश खतरनाक बाढ़ की चपेट में रहा। नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में 2010 के बाद से प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं बढ़ी हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, हुंजा घाटी, खैबर पख्तुनख्वा में खतरनाक बाढ़ आई, जबकि वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न हिमालय पर बाढ़ और लैंडस्लाइड का असर पड़ा। शोध में चेतावनी दी गई है कि छोटे ग्लेशियरों का पिघलना, अस्थिर ग्लेशियर झीलों की संख्या में वृद्धि और बारिश के पैटर्न में बदलाव से हिमालय क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट (सीटीपी) के करीब पहुंच रहा है। विश्व का वैश्विक तापमान औद्योगिक क्रांति के बाद एक डिग्री सेल्सियस बढ़ा है।

हिमालय क्षेत्र में त्रासदी

2013: केदारनाथ आपदा
2014: लद्दाख की जांस्कर घाटी में ग्या झील का फटना
2021: चमोली के ऋषि गंगा में बाढ़
2023: सिक्किम में ल्होनक झील फटी
2023 और 2025: हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर आई बाढ़
2025: धराली में मलबे से आई बाढ़
2025: कश्मीर के किश्तवाड़ में बाढ़

Hindustan Page No-16

ऊर्जा संरक्षणके प्रति जागरूकता जरूरी

❐ योगेश कुमार गोयल

ऊर्जा मंत्रालयके अधीनस्थ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षणमें भारतकी उपलब्धियोंको प्रदर्शित करनेके लिए प्रतिवर्ष १४ दिसम्बरको राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवसका आयोजन किया जाता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा वर्ष २००१ में देशमें ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। दरअसल दुनियाभरमें पिछले कुछ दशकोंमें जनसंख्या तेजीसे बढ़ी है और उसीके अनुरूप ऊर्जाकी खपत भी निरन्तर बढ़ रही है लेकिन दूसरी ओर जिस तेजीसे ऊर्जाकी मांग बढ़ रही है, उससे भविष्यमें परम्परागत ऊर्जा संसाधनोंके नष्ट होनेकी आशंका बढ़ने लगी है। यदि ऐसा होता है तो मानव सभ्यताके अस्तित्वपर ही प्रश्नचिह्न लग जायगा। यही कारण है कि भविष्यमें उपयोग हेतु ऊर्जाके स्रोतोंको बचानेके लिए विश्वभरमें ऊर्जा संरक्षणकी ओर विशेष ध्यान देते हुए इसके प्रतिस्थापनके लिए अन्य संसाधनोंको विकसित करनेकी जिम्मेदारी बढ़ गयी है। ऊर्जाके अपव्ययको कम करने, ऊर्जा बचाने और इसके संरक्षणके महत्वके बारेमें लोगोंको जागरूक करनेके लिए ही देशमें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष एक खास विषयके साथ कुछ लक्ष्यों तथा उद्देश्योंको मद्देनजर रखते हुए लोगोंके बीच इन्हें अधिक प्रभावशाली बनानेके लिए मनाया जाता है। वास्तवमें इस दिवसके आयोजनका मुख्य उद्देश्य ऊर्जाके अनावश्यक उपयोगको न्यूनतम करते हुए लोगोंको मानवताके सुखद भविष्यके लिए ऊर्जाकी बचतके लिए प्रेरित करना ही है।

विद्युत मंत्रालय द्वारा देशमें ऊर्जा संरक्षणकी प्रक्रियाको सुविधाजनक बनानेके लिए शुरू किया गया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अभियान एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान है। देशमें ऊर्जा संरक्षण तथा कुशलताको बढ़ावा देनेके लिए वर्ष १९७७ में केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान असोसिएशनका गठन किया गया था। ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षणके महत्वके बारेमें आम जनतामें जागरूकता बढ़ानेके लिए वर्ष २००१ में एक अन्य संघटन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो स्थापित किया गया। ब्यूरोका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति छोटे-छोटे कदम उठाकर अपने घर अथवा कार्यालयमें लाईट, पंखे, हीटर, कूलर, एसी तथा बिजलीके अन्य किसी भी उपकरणके अनावश्यक उपयोगपर नियंत्रण करते हुए ऊर्जाकी बचत कर सकता है। हम छोटे-छोटे स्तरपर ऊर्जा संरक्षणके लिए कदम उठाकर भी प्रत्येक नागरिक देशके राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अभियानमें बहुत बड़ी मदद दे सकता है और इस प्रकार बड़ी मात्रामें ऊर्जा संरक्षण किया जा सकता है। यदि ऐसे ही कुछ छोटे उपायोंका उल्लेख किया जाए तो पुराने बल्बोंके स्थानपर सीएफएल या एलईडी बल्बोंका इस्तेमाल किया जाय। आईएसआई चिह्नित विद्युत उपकरणोंका ही उपयोग करें।

यथासंभव दिनके समय सूर्यकी रोशनीका अधिकतम उपयोग किया जाय और जरूरत न होनेपर लाइटें, पंखे, कूलर, एसी, हीटर, गीजर इत्यादि विद्युत उपकरण बंद रखें। खाना पकानेके लिए बिजलीके उपकरणोंके बजाय सोलर कुकर और पानी गर्म करनेके लिए बिजलीके गीजरके बजाय सोलर वाटर हीटरके उपयोगको बढ़ावा दिया जाय। भवन निर्माणके समय प्लाटके चारों ओर वृक्ष लगाये जायं तो प्रचण्ड गर्मीमें भी भवन गर्म होनेसे बचेंगे और कूलर, एसी इत्यादिकी जरूरत कम होगी। मकानों या कार्यालयोंमें दीवारोंपर हल्के रंगोंके प्रयोगसे कम रोशनी वाले बल्बोंसे भी कमरेमें पर्याप्त रोशनी हो सकती है। इससे न केवल ऊर्जा संरक्षण अभियानमें सहभागी बनकर हम भविष्यके लिए ऊर्जा बचानेमें मददगार बनेंगे, बल्कि अपना बिजली बिल भी सीमित रख सकेंगे।

सार्वजनिक स्थानोंपर सौर लाइटोंकी व्यवस्था होनी चाहिए। विशेषज्ञोंके अनुसार कार्यस्थलपर दिनके समय प्राकृतिक रोशनीमें कार्य करने वाले लोगोंकी कार्यकुशलतामें वृद्धि होती है और ऊर्जाकी खपतमें अपेक्षित कमी आती है, वहीं तेज कृत्रिम रोशनी वाले स्थानोंपर काम करनेसे कर्मियोंमें तनाव, सिरदर्द, रक्तचाप, थकान जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखी जाती हैं और उनकी कार्यकुशलतापर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऑफिसमें यदि पर्याप्त प्राकृतिक रोशनीका व्यवस्था हो तो इससे ऊर्जा संरक्षण होनेके साथ-साथ कर्मचारियोंकी कार्यक्षमता भी बढ़ती है। प्रतिवर्ष देशमें हजारों गैलन पानी बर्बाद होता है, इसलिए ऊर्जा संरक्षणकी बात करते समय जलकी बर्बादीको रोकनेपर पर्याप्त ध्यान दिया जाना भी बेहद जरूरी है। न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनियाके समक्ष बिजली जैसी ऊर्जाकी महत्वपूर्ण जरूरतें पूरी करनेके लिए सीमित प्राकृतिक संसाधन हैं, साथ ही पर्यावरण असंतुलन और विस्थापन जैसी गम्भीर चुनौतियां भी हैं।

ऐसी गम्भीर समस्याओं और चुनौतियोंसे निबटनेके लिए अक्षय ऊर्जा ऐसा बेहतरीन विकल्प है, जो पर्यावरणीय समस्याओंसे निबटनेके साथ-साथ ऊर्जाकी जरूरतोंको पूरा करनेमें भी कारगर साबित होगा लेकिन ऊर्जाके संसाधन गैर-अक्षय हों या अक्षय, हमें अपने जीवनमें ऊर्जाके महत्वको समझते हुए ऊर्जा संरक्षणके प्रति जागरूक होना ही होगा। देशके प्रत्येक नागरिकका दायित्व है कि ऊर्जा चाहे किसी भी रूपमें हो, वह उसे व्यर्थमें नष्ट न करे। अपने और आनेवाली पीढ़ियोंके सुखद भविष्यके लिए हमें अपने व्यवहारमें ऊर्जा संरक्षणकी आदतोंको शामिल करना ही होगा।

Aaj Patna Page No-6

जलवायु सुरक्षाकी जिम्मेदारी सभीपर

कुछ महीने पहले अमेरिकी पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी ईपीएने अपने खतरेके निष्कर्षोंकी औपचारिक समीक्षा करनेका फैसला किया, जिससे जलवायु परिवर्तनके वैज्ञानिक आधारपर भी सवाल उठने लगे। ईपीएके कदमका अमेरिकी सरकार द्वारा समर्थित अनुसंधान कार्यक्रमोंपर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

❐ राजीव खेर

अमेरिकाका पक्षकारोंके ३०वें सम्मेलन (कॉप ३०) से जदारद रहना पेरिस समझौतेसे उसके हटनेके बाद जलवायु परिवर्तनके उपायोंको कमजोर करने वाला अगला कदम माना जा सकता है। कुछ महीने पहले अमेरिकी पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी (ईपीए) ने अपने 'खतरेके निष्कर्षों' की औपचारिक समीक्षा करनेका फैसला किया जिससे जलवायु परिवर्तनके वैज्ञानिक आधारपर भी सवाल उठने लगे। ईपीएके कदमका अमेरिकी सरकार द्वारा समर्थित अनुसंधान कार्यक्रमोंपर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा और इसका संबंधित कार्य योजनाओंके विकासपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ग्रीनहाउस गैसोंका सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाले देशों एवं समूहोंमेंसे एक यूरोपीय संघ (ईयू) ने क्रमशः २०१९ और २०२१ में 'ग्रीन डील' और 'फिट फॉर ५५' पैकेज अपनाया था। इसने अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओंको पूरा करनेके लिए वर्ष २०३० तक उत्सर्जन ५५ फीसदीतक कम करने और अंततः २०५० तक विशुद्ध शून्य (नेट-जीरो) उत्सर्जनका लक्ष्य हासिल करनेकी योजना बनायी है। हालांकि ह्वाइट हाउसमें डोनल्ड ट्रम्पके दूसरे कार्यकालने ईयूकी योजनाओंकी राहमें मुश्किलें पैदा कर दी हैं। ईयूपर थोपे गये 'ग्रये समझौते' के अनुसार इस समूहको अपनी सुरक्षाका जिम्मा उठाना होगा, अंदरूनी नयी चुनौतियोंका सामना करते हुए बेहतर राजनीतिक एकीकरण सुनिश्चित करना होगा और अपनी स्थिरता सुनिश्चित करनेके लिए बाहरी दुनियासे मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध बनाने होंगे। सस्ते रूसी तेल एवं गैसकी आपूर्ति थमनेसे ईयू अधिक महंगी ऊर्जा संसाधनोंकी तलाश करनेके लिए विवश हो गया है। इसे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनोंके अधिक इस्तेमालकी तरफ कदम बढ़ानेको मजबूर होना पड़ा है।

अमेरिकाकी मांग है कि नाटो सदस्य अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का तीन फीसदी अपने रक्षा बजटपर खर्च करें जिससे ईयूके लिए अपने जलवायु लक्ष्योंको पूरा करनेका काम और भी मुश्किल हो जायगा। चीन (सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश) ने पेरिस समझौतेके तहत कोई पूर्ण कटौती प्रतिबद्धता नहीं दिखायी है। वर्ष २०३० के लिए चीनके अद्यतन देशवार निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्योंमें २००५ के स्तरसे जीडीपी प्रति यूनिट कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जनमें ६५ फीसदीकी कटौती करना, गैर-जीवाश्म-ईंधन ऊर्जाकी हिस्सेदारी बढ़ाकर लगभग २५ फीसदी करना, वनोंका क्षेत्र छह अरब घन मीटर मीटरतक बढ़ाना और पवन एवं सौर ऊर्जाकी स्थापित क्षमता १२०० गीगावॉटसे अधिक करना शामिल है।

इसने वर्ष २०३० के आसपास चरमतक पहुंचने और २०६० तक विशुद्ध शून्य उत्सर्जनका लक्ष्य हासिल करनेका वादा किया है। उत्सर्जनमें पूर्ण कटौतीका लक्ष्यका हासिल करनेसे जुड़ा कोई वादा नहीं कर चीन अपनी मात्रात्मक प्रतिबद्धता पूरा करते हुए कोयला आधारित बिजली संयंत्रोंको बढ़ाकर अब भी उत्सर्जन बढ़ा सकता है। औद्योगिक नीति द्वारा सक्षम हरित तकनीक (ग्रीन टेक्नोलजी) में चीनकी दमदार उपस्थिति दुनियाको कम लागतपर हरित अर्थव्यवस्थामें बदलनेमें मदद कर रही है।

यूरोपीय संघ, चीन और भारतको वैश्विक जलवायु लक्ष्योंको पूरा करनेके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। यूरोपीय संघको गरीब देशोंकी चिंताओंको दूर कर और वित्तीय और तकनीकी सहायता बढ़ाकर जलवायुके मुद्देपर अग्रणी समूह होनेके अपने रुतबेको फिरसे स्थापित करना होगा। चीनको सस्ती कीमतोंपर हरित तकनीकतक पहुंच प्रदान कर दुनियाके पिछड़े एवं विकासशील देशोंकी मदद करनी चाहिए और भारतको स्वयं अंदरूनी स्तरपर प्रयास और तेज कर इन अर्थव्यवस्थाओंमें हरित परियोजनाओंके विकासमें मदद करनी चाहिए।

परन्तु चीनकी अर्थव्यवस्था अत्यधिक आंतरिक तनावमें है और यदि ट्रम्पके शुल्क मुद्दोंपर पारस्परिक रूपसे स्वीकार्य समझौता जल्द नहीं हो पाता है तो इसपर बाहरी दबाव भी बढ़ेगा। इन घटनाक्रमोंका वैश्विक अर्थव्यवस्थापर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इससे मध्यम अवधिमें हरित ऊर्जाकी तरफ कदम बढ़ाना (ग्रीन ट्रांजिशन) भी धीमा हो जायगा, क्योंकि प्रमुख उत्सर्जकोंको वित्तीय बाधाओंका सामना करना पड़ेगा।

अमेरिकाके कदमोंसे चीन कोयला संयंत्रोंको बंद करनेके लिए भी अब अधिक दबाव महसूस नहीं करेगा। यह मानते हुए कि चीनकी अर्थव्यवस्था पांचसे छह फीसदीकी दरसे बढ़ती रहेगी (ऊर्जाकी मांगमें वृद्धिके साथ) यह जीवाश्म और गैर-जीवाश्म दोनों प्रकारके ईंधनपर निर्भर रह सकती है। इससे उत्सर्जनका स्तर बढ़ता रहेगा। भारत एक दुरूह तीसरा उत्सर्जक होनेके नाते अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओंको पूरा करनेमें अच्छी प्रगति कर रहा है। इसे वर्ष २०२५ में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांकमें दसवें स्थानपर रखा गया है (चीनके ५५वें स्थानके मुकाबले)। भारत अपनी सभी प्रतिबद्धताओंपर समयसे बहुत आगे है और ग्रिड-आधारित और ऑफ-ग्रिड दोनों नवीकरणीय परियोजनाओंको तेजीसे क्रियान्वित करनेमें तेजीसे प्रगति कर रहा है। हालांकि यह बिजली उत्पादनके लिए कोयलेपर बहुत अधिक निर्भर है।

इन हालातके बीच यूरोपीय संघ, चीन और भारतको वैश्विक लक्ष्योंको पूरा करनेके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। यूरोपीय संघको गरीब देशोंकी चिन्ताओंको दूर कर और वित्तीय और तकनीकी सहायता बढ़ाकर जलवायुके मुद्देपर अग्रणी समूह होनेके अपने रुतबेको फिरसे स्थापित करना होगा। चीनको सस्ती कीमतोंपर हरित तकनीकतक पहुंच प्रदान कर 'ग्लोबल साउथ' (दुनियाके पिछड़े एवं विकासशील देशों) की मदद करनी चाहिए और भारतको स्वयं अंदरूनी स्तरपर प्रयास और तेज कर इन अर्थव्यवस्थाओंमें हरित परियोजनाओंके विकासमें मदद करनी चाहिए। इससे अच्छे राजनयिक एवं कारोबारी संकेत भी बाहर जायंगे। अमेरिकाके रुखमें सकारात्मक बदलाव होनेतक वे कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन ऐंड स्टोरेज (सीसीयूएस) टेक्नोलजी सहित सभी जलवायु समाधानों पर साक्ष्य-आधारित जलवायु-संबंधी अनुसंधान कार्यक्रमोंको भी जारी रख सकते हैं और इन्हें बढ़ावा दे सकते हैं। हालांकि वे बढ़ती वैश्विक बाधाओंके बीच ऐसा कर पायेंगे या नहीं यह एक बड़ा सवाल है।

Aaj Patna Page No-6

जापानियों की ईमानदारी हमारे दिल को छू गई

राग सिद्ध कवयित्री के रूप में अलग पहचान बनाने वाली इंदु जैन ने अपने पहले काव्य-संग्रह 'चौंसठ कविताएं' से हिंदी साहित्य में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवाई। 'आंख से भी छोटी चिड़िया', 'हवा की मोहताज क्यों रहूं', 'कुछ न कुछ टकराएगा जरूर' प्रमुख कृतियां। 'चश्मेबद्दूर', 'स्पर्श', 'कथा' जैसी फिल्मों में यादगार गीत लिखने वाली तथा अनेक पुरस्कारों से सम्मानित प्रसिद्ध कवयित्री इंदु जैन के यात्रा-संस्मरण 'पत्तों की तरह चुप- जापान प्रवास' से संपादित अंश...

इलस्ट्रेशन: यशवंत नामदेव

अद्भुत यात्रा संस्मरण-39

इंदु जैन

जन्म: 05 अगस्त, 1935 निधन: 27 अप्रैल, 2008

यदि पूछा जाए कि जापानियों का कौन-सा सामाजिक गुण सर्वाधिक प्रभावित कर गया, तो मैं निस्संकोच कहूंगी, उनकी ईमानदारी। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह हो सकता है कि यह सीधे-सीधे मेरे नफे-नुकसान से जुड़ा है, लेकिन जितनी बार कीमती चीजें यहां-वहां भूल जाने के बाद मुझे जापान में वापिस मिली हैं, शायद दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में नहीं मिल सकतीं। अनेक पश्चिमी विदेशी मित्रों ने इसकी ताईद की है।

भारत में अपना सामान कभी ढोने की जरूरत नहीं पड़ी, सो तमाम मनोबल के बावजूद देह थक जाती थी। तिस पर जापान के स्टेशनों की बेइंतहा सीढ़ियां चढ़ने-उतरने की भूलभुलैया। बीच में जैसे-तैसे जुटाए निरामिष भोजन से पेट भरते रहने की समस्या और मुंह में जबान होते हुए अवाक रह जाने की मजबूरी। लेकिन फिर भी सहायता को उद्यत लोग हमारे यात्रा-सलाहकार की प्रबुद्ध योजना और रेल-परिवहन की सुचारु नियमितता से हम सारी मंजिलें पूरी करते चले गए और तरह-तरह के अनुभवों व दृश्यों की मीठी थकान से भरे अपने अंतिम सफर के लिए आरामदेह सीटों पर सामान टिकाकर प्लेटफार्म पर टहलने लगे। अभी गाड़ी छूटने में थोड़ा समय बाकी था। पहली बार ऐसी रेलगाड़ी में बैठ रहे थे, जो दुमंजिली थी।

नीचे की आधी मंजिल जमीन के नीचे रहती थी। सोचा इस अद्भुत रेलगाड़ी का चित्र खींच लिया जाए, लेकिन कैसे? कैमरा कहां है? बल्कि कैमरा, उसके दो लेंस, चल कैमरा का माइक्रोफोन, कई खींची हुई फिल्में, नई फिल्में सबका बैग-का-बैग ही कहां है? जल्दी-जल्दी सोचना शुरू किया और याद आया कि शिन ओसाका से नोबा की स्थानीय भूमिगत ट्रेन में बहुत भीड़ थी। लगभग बीस मिनट की यात्रा दरवाजे के पास खड़े-खड़े की थी। बड़े बैग हाथ से संभाले हुए थे और भीड़ जब ज्यादा बढ़ने लगी, तो कैमरा-बैग ऊपर सामान के रैक पर रख दिया था। नोबा आया- बाहर निकलती, भीतर आती भीड़ के बीच जल्दी से बड़े बैग लेकर बाहर चले आए और कैमरे का थैला ऊपर ही रखा छूट गया।

इस बात को अब लगभग सवा घंटा हो चुका था। उधर इस गाड़ी के छूटने में मुश्किल से पांच मिनट बाकी थे। किसी तरह गाड़ी के कंडक्टर को सारी बात समझाई। उसने फौरन सामान उतारने को कहा और फिर शुरू हुई कोशिशें...कोशिशें और कोशिशें। जापान रेलवे के उस वयोवृद्ध कर्मचारी को हम कभी नहीं भूलेंगे। अगली गाड़ी का टिकट बदलवाते हुए, मेरे हाथ का सामान खुद ढोते हुए वे हमें यहां से वहां संबंधित ऑफिसों में ले गए। अपनी ड्यूटी दूसरे साथी को सौंपी। अनेक फोन करवाने के बाद उन्होंने बताया कि बैग कहीं किसी स्टेशन के खोए सामान-ऑफिस में जमा नहीं कराया गया है। यह कहते हुए कि कैमरा मिलने की संभावना अब कम ही है- उनके चेहरे पर खेद और लज्जा के ऐसे भाव थे, जैसे गलती हमारी नहीं उनकी है, मानो वे अपने देशवासियों के व्यवहार के लिए क्षमा मांग रहे हैं। उन्होंने फिर भी तोबा में हमारे होटल का नाम और फोन नंबर ले लिया और आश्वासन दिया कि हमें अब और प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। कैमरा मिले या न मिले, वे रात को आठ बजे हमारे होटल में फोन करके हमें स्थिति से अवगत करा देंगे। इतना कुछ करने के बाद हमें ठीक से धन्यवाद भी दे पाने का अवकाश न देकर वे अपनी ड्यूटी पर लौट गए।

सारी स्फूर्ति खोकर थके मन से हम तोबा पहुंचे, तो शाम काफी नीचे उतर चुकी थी। सामान सीढ़ियों पर से ऊपर ले जा रहे थे कि देखा ऊपर एक सज्जन उत्तेजित से, हाथ हिला-हिलाकर नीचे किसी से कुछ कह रहे हैं। अचानक समझ आया कि वे हम ही से कुछ कहना चाह रहे हैं। सारी बात में बस एक ही शब्द पल्ले पड़ रहा था- 'कामेरा, कामेरा'... आशा की चमकीली कौंध मन में दौड़ गई। उसके बाद...आज तक यह सोचकर आश्चर्य होता है कि समझने की तीव्र इच्छा किस तरह मनुष्य को भाषा की सीमा से ऊपर उठा ले जाती है। वे अंग्रेजी या हिंदी बिल्कुल नहीं जानते थे और हम जापानी का एक अक्षर नहीं समझते थे, लेकिन उन्होंने बखूबी यह हमारे जेहन में उतरवा ही दिया कि तोबा से फोन आया है कि वे इस गाड़ी से आने वाले भारतीय दंपत्ति को बता दें कि उनका कैमरा-बैग मिल गया है। यह अगली गाड़ी से भेजा जा रहा है। बैग आ जाने पर ये सज्जन जो स्टेशन मास्टर हैं, उसे ऑफिस लॉकर में सुरक्षित रख देंगे। हमें होटल फोन कर देंगे, ताकि हम उसे आकर ले जाएं।

हमारी खुशी और अचरज का ठिकाना न था। बारंबार धन्यवाद और अनुग्रह में झुकते हुए हम टैक्सी पकड़कर होटल पहुंचे। तब तक स्टेशन मास्टर महोदय होटल फोन करके सारा किस्सा बता चुके थे। सो जाते ही होटल के मैनेजर ने अत्यंत मृदुता से हमें बताया कि हम निश्चिंत रहें। वे हमारा सामान स्वयं होटल की कार भेजकर मंगा लेंगे और हमारे कमरे में पहुंचा देंगे। उसके बाद वे उसी मृदुता, तत्परता और सहजता से हमारी दूसरी समस्या सुलझाने में लग गए।

दूसरी बार फिर हमने कैमरा और उसके तमाम उपकरणों का बैग खो दिया। इस बार यह नगर सप्पोरो से चितोसे हवाई अड्डे आते हुए बस में फिर से ऊपर सामान-रैक पर रखा छूट गया। हमें अपनी भूल का इल्म तब हुआ, जब हवाई जहाज तोक्यो के हानेदा हवाई अड्डे से 10 मिनट की दूरी पर रह गया। फिर वही भागदौड़, दौड़-धूप हमारी और इस बार हवाई परिवहन कर्मचारियों की। फोन-पर-फोन, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। हानेदा से ही हमने अपने मित्र श्री शिनोमिया को सप्पोरो फोन करके अपनी मूर्खता बता दी थी। रात के दस बज चुके थे- तमाम दफ्तर बंद हो चुके थे। अगले दिन रविवार था, लेकिन शिनोमिया जी ने भरसक कोशिश करके हमें फोन करने का आश्वासन दिया।

रविवार को हमारी प्रतीक्षा जितनी आतुर थी, फोन की चुप्पी उतनी ही स्थिर थी। सप्पोरो, हानेदा, चितोसे- सब चुप थे। चुओ बस सर्विस से भी कोई संदेश नहीं था। मेरे पति का कहना था कि इस बार कैमरा न मिलना ही 'पोएटिक जस्टिस' होगा। कुछ देर बाद बोले- 'बच्चा भी एक बार गल्ती करता है, तो माफ कर दिया जाता है, लेकिन दूसरी बार वही भूल करता है, तो उसकी पिटाई बनती है।...' फिर- 'बस अब कैमरा नहीं मिलता, तो जिंदगीभर दूसरा नहीं खरीदूंगा। तुम्हारे जैसी कैमरे से ही काम चलाऊंगा।' कुछ देर बाद फिर- 'इतना बढ़िया कैमरा! शायद मैं उसके योग्य ही नहीं था...' सारी बातें उनकी हताशा और छटपटाहट को ध्वनित कर रही थीं।

आखिर उनसे नहीं रहा गया। चितोसे के दो-तीन नंबरों को फोन, हानेदा में कम-से-कम छह-सात फोन- 'एक बैग जिस पर 'बीटल्स' का चित्र है। उसमें एक निकॉन एफ. ई. कैमरा, मूवी कैमरा, एक वाइड लेंस, एक टेली लेंस, फर की टोपी और दस्ताने, एक भूरी-नीली ऊन की जर्सी...' और हर बार एक ही उत्तर- 'यहां ऐसा कोई बैग नहीं है। हमने नोट कर लिया है।...फोन करेंगे।

शाम को फोन अपने आप बजा। शिनोमिया जी थे। 'मुझे बहुत दुख है...' उन्होंने बात शुरू की और एम एम का बैठा दिल लेट गया। 'मैं इतनी देर में फोन कर रहा हूं। बस के ड्राइवर ने अपनी कंपनी के हेड ऑफिस में आपका कैमरा और सामान जमा करा दिया था...' आगे तो, राहत की हरहराहट में उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दिया। फोन को हथेली से ढक चमकती आंखों, खनकती आवाज में मुझे सूचना दी- 'सुनो कैमरा मिल गया...' जी हां! बीटल्स बैग सही-सलामत हमारे मित्र के घर में आराम फरमा रहा था।

(साभार: 'बीसवीं सदी का हिंदी महिला लेखन (खंड-3)', संपादक: ममता कालिया, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली से संपादित अंश)

छोटी कविता ही महत्वपूर्ण: अज्ञेय

प्रयोगवाद और नई कविता एक ही विकासक्रम में होते हुए भी अलग-अलग अस्तित्व रखते हैं। प्रयोगवाद में संप्रेषण और नई कविता में नए प्रतिमानों को रचा गया है। इन्हीं संदर्भों में प्रयोगवाद और नई कविता के काव्य-सिद्धांतों पर विहंगम दृष्टि डालती है, हाल में आई पुस्तक 'प्रयोगवाद और नई कविता के काव्य-सिद्धांत।' प्रस्तुत है इस पुस्तक से एक संपादित अंश...

पुस्तक अंश

कविता के आकार के संबंध में अज्ञेय का मत है कि छोटी कविता ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भावना प्रधान कविता छोटी ही हो सकती है, नहीं तो अपने भावों का पैराफ्रेज होने लगता है। सर्जना के क्षण लंबे नहीं हो सकते। उनके मत से लंबी कविताएं भी अच्छी हो सकती हैं, किंतु उसमें कलात्मक गठन देने की वस्तु दूसरी ही हो सकती है, भाव की संहति और तीव्रता नहीं।

आधुनिक कविता पर मनोविज्ञान के प्रभाव के कारण व्यक्ति और परिस्थिति में सामंजस्य नहीं है। इस विरोध के कारण व्यक्ति के मन पर दबाव है, जिससे कवि सीधे-सीधे व्यक्त नहीं कर पाता केवल ध्वनित करता है, संकेत देता है, जिसे हम दृष्टिगत कर सकें। सौंदर्य के तीन स्तर होते हैं- एक बाहरी, दूसरा आंतरिक और तीसरा बाहर से आंतरिक आलोक में अंतर्भूत होता हुआ, जिसे कवि अपनी संवेदना के माध्यम से मूर्त कर लेता है। इसमें मानसिक तनाव, अंतर्जीवन की स्वर से संयत तीखी चेतना और जीवन की विविधता का बोध होता है। आज की कविता का सौंदर्य तीसरी कोटि का ही है।

काव्य का विषय और उसकी वस्तु अलग-अलग चीजें हैं। किसी भी कृति की वस्तु अनिवार्यतः मानवीय वस्तु होती है, क्योंकि विषय के साथ वह कवि के रागात्मक संबंध का ही प्रतिबिंब होती है- एक संवेदना या चेतना की अपने से इतर के साथ परस्पर प्रतिक्रिया से उद्भूत वस्तु। वस्तु की परीक्षा करते समय कृतिकार के मानस की परीक्षा भी आवश्यक होती है। विषय मानवेतर होते हैं, हो सकते हैं। अतएव काव्य-विवेचन में विषय से अधिक वस्तु का ही महत्व है, वह मानवीय होती है। उसके माध्यम से कृतिकार के मन तक पहुंचा जा सकता है। कृतिकार कैसे वस्तु तक पहुंचा, कैसे उसे उसकी संवेदना ने ग्रहण किया और बहुजन संवेद्य या प्रेषणीय बनाया।

काव्य विधा के संबंध में अज्ञेय का मत है कि साहित्य में वस्तु और वस्तु रूप अलग-अलग नहीं होते। कृति की वस्तु जिस रूप में व्यक्त हो, उसी में वह व्यक्त हो सकती है। उसे किसी विशेष विधा में व्यक्त करने का कोई विकल्प कलाकार के पास नहीं है।

काव्य में अज्ञेय के मत से मूल प्रश्न नए प्रतिमानों का है, क्योंकि काव्य के व्यंजना साधनों में नए संदर्भ की आवश्यकता होती है। काव्य तत्वों का अन्वेषण आधुनिक कवि सभी स्थानों से करने का प्रयत्न करता है, किंतु वह कविता और सामाजिक के बीच से हट जाता है, जिससे सामाजिक कविता की प्रतिमा अपने अनुरूप गढ़ सके। काव्य की अद्वितीय अनुभूति के संप्रेषण के साथ ही जीवन की अनुभूति का भी महत्व है, जिसमें अनिवार्य रूप से संवेदना का अंतर्भाव रहता है। वस्तुतः अपने से अलग होकर अपने को देख सकना ही कलाकार को काव्य की रचना की प्रक्रिया में अंतर्भुक्त करता है।

काव्य में स्थूल जीवन की वास्तविकता नहीं होती, उसका कल्पना से अनिवार्य संबंध होता है। अज्ञेय के मत से कविता का वास्तविकता से घनिष्ठ संबंध है। कल्पना, प्रातिभ ज्ञान, पर्यवेक्षण सभी से कविता वास्तविकता को स्वायत्त, आत्मसात करती है।

प्रयोगवाद और नई कविता के काव्य-सिद्धांत
(समालोचना)

लेखक: डॉ. राजेन्द्र मिश्र
प्रकाशक: हिंदी साहित्य निकेतन, बिजनौर
मूल्य: ₹800

पुस्तकें आई हैं

मैं एक फेरीवाला
(कविता-संग्रह)
लेखक: राही मासूम रजा
प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
मूल्य: ₹199

'क्यों मेरी मुहब्बत को पत्थर ये समझते हैं, क्यों इतने परेशां हैं शीशे के मकांवाले।' -उदासी, बेचैनी, अकेलेपन और तन्हाई को अपने लफ्जों में पिरोने वाले मशहूर शायर राही मासूम रजा की कविताओं का संग्रह 'मैं एक फेरीवाला' ऊपर कही गई बात की तसदीक करता है। रूमानियत से भरपूर इन गीतों और कविताओं में एक सामान्य आदमी की लाचारी और इसरते खुलकर सांस लेती हुई नजर आती है।

व्यंग्य के सात कोण
(आलोचना)
संपादक: सुनील जैन 'राही'
प्रकाशक: बोधि प्रकाशन, जयपुर
मूल्य: ₹399

इधर-उधर ताक-झांक करने वाले और फिर उस पर चुटकी लेने वालों को विद्वान लोग व्यंग्यकार कहते हैं। बात जब व्यंग्य की हो, तो हरिशंकर परसाई का नाम खुद-ब-खुद जेहन और जुबान पर आ जाता है। फिर पीछे-पीछे कई नाम जैसे शरद जोशी, रवींद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, ज्ञान चतुर्वेदी, प्रेम जनमेजय और सुभाष चंदर आ जाते हैं। 'व्यंग्य के सात कोण' में ये सात व्यंग्य-महारथी शामिल हैं।

हां, मैं हूं
(उपन्यास)
लेखक: महेन्द्र भीष्म
प्रकाशक: अद्विक पब्लिकेशन, दिल्ली
मूल्य: ₹350

अपने आसपास किसी इंसान के समलैंगिक होने का पता चलते ही अक्सर लोगों के चेहरे पर अजीब से भाव आ जाते हैं। भले ही मेडिकल साइंस इसे सामान्य मानता हो और कानून भी आज इनके पक्ष में दिखाई देता हो, तब भी सामाजिक स्तर पर स्थितियां बदल कर भी बहुत नहीं बदली हैं। ऐसे में हाल ही में समलैंगिकों पर केंद्रित उपन्यास 'हां, मैं हूं', इनकी दुनिया के बारे में प्रभावी ढंग से बात करता हुआ दिखाई देता है।

कुछ यूं रचती है हमें किताब
(सृजनात्मक शिक्षा)
लेखक: आर. डी. सैनी
प्रकाशक: राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत
मूल्य: ₹155

'कुछ यूं रचती है हमें किताब' के नायक 'रामजी' का स्कूल जीवन अध्यापकों के कारण किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन एक किताब उसके जीवन को बदल देती है। स्कूल और किताब से दूर भागने वाला रामजी न केवल कक्षा का अव्वल छात्र बनता है, बल्कि विद्यार्थी जीवन में ही कथाकार और लेखक भी बन जाता है। लेखक ने पुस्तक में अपनी आपबीती के जरिये शैक्षिक विमर्श को संजीदगी से उठाया है।

हिंदी साहित्य में कट्टम-कट्टा

तिरछी नजर

सुधीश पचौरी हिंदी साहित्यकार

इस गली गया, तो 'कम्यूनल' हुआ, उस गली गया, तो 'सेक्युलर' हुआ। एक में गया, तो दूसरे से गया; दूसरे में गया, तो पहले से गया। सच कहूं, हमारे जैसे तटस्थ साहित्यकार की आजकल बड़ी समस्या है। कुछ लोग अपने हाथों में ठप्पे लिए बैठे हैं कि जरा भी कोई दुश्मन की गली में दिखा, तो छाप दिया कि दुश्मन है! अब तो यारों ने बचे-खुचे तटों पर भी अपने-अपने बुलडोजर चला दिए हैं, तब बताइए कोई तटस्थ कैसे रहे?

ऐसा तो कभी न था। साहित्यकारों के झगड़े पहले भी होते थे। मतभेद होते थे, लेकिन मनभेद नहीं। साहित्य तब 'प्राइवेट लिमिटेड' था, आज की तरह 'पर्सनल अनलिमिटेड' नहीं। सोशल मीडिया की कृपा से आज हर कोई साहित्यकार है, लेखक है, कवि है, कथाकार है, विचारक है, फोटोकार व वीडियोकार है। तब साहित्य की अवधारणा उदारवादी थी। साहित्य सबका था- *सुरसरि सम सब कहं हित होई* था। उसके लिए कोई अछूत, वर्जित और बहिष्कृत नहीं था।

यूं तो तब भी साहित्य में लेफ्ट-राइट हुआ करता था, पर ऐसा कट्टम-कट्टा और लट्ठम-लट्ठा नहीं था, जैसा आज है। तब कोई नहीं कहता था कि उसे बुलाया, तो हम न आएंगे। असहमतियां होतीं, लेकिन ऐसी 'हेट' न होती कि किसी असहमत को देखते ही भौंहें टेढ़ी हो जाएं।

पिछली सदी के पचास और साठ के दशक में 'परिमल' की गोष्ठियों के 'मिनट्स' के रजिस्टर व कॉपियां इस लेखक ने देखी हैं, जो बताती हैं कि इलाहाबाद में परिमल वाले गोष्ठी करते, तो प्रगतिशील आते; प्रगतिशील गोष्ठी करते, तो परिमलिए आते थे। रचना पाठ होते, बहसें होतीं, सहमतियां-असहमतियां होतीं, नोक-झोंक होती, पर साहित्य की बेहतरी के लिए होतीं। साहित्यकारों में एक-दूसरे के प्रति निजी किस्म की जिघांसा, खुंदक न होती।

यह दूसरे महायुद्ध के खत्म होते ही शुरू हुए शीतयुद्ध का जमाना था। दुनिया दो खेमों में बंटी थी। एक ओर पूंजीवादी अमेरिका-यूरोप के देश थे, दूसरी ओर समाजवादी सोवियत संघ था। एक ओर 'फ्री कल्चर' का नारा था, दूसरी ओर 'समाजवादी कल्चर' का। एक ओर लेखक की आजादी पर जोर रहा, तो दूसरी ओर उसके क्रांति का कल-पुर्जा (प्रचारक) बनने पर जोर रहा।

यह शीतयुद्ध खूब पढ़े-लिखे बुद्धिजीवियों के दिमाग को जीतने की वैचारिक-सांस्कृतिक लड़ाई थी, जो 1990 तक चलती रही और जैसे ही सोवियत संघ गिरा, वैसे ही खत्म हो गई। तब फ्री वर्ल्ड बरक्स समाजवाद था, अब सेक्युलर बरक्स कम्यूनल है। सेक्युलर गली में कम्यूनल नहीं जाते, कम्यूनल गली में सेक्युलर नहीं जाते। सेक्युलर के कई नाम हैं। जैसे, लुटियन्स गैंग, खान मार्केट गैंग, लॉबी वाले, इको सिस्टम वाले, तो कम्यूनल के भी कई नाम हैं- हिंदुत्ववादी, हिंदू धर्मवादी, सनातनवादी, परंपरावादी।

आज का सोशल मीडिया और इसमें भी कमबख्त यू-ट्यूब इन अलग-अलग गलियों की गोष्ठियों के अक्सर दर्शन कराता रहता है, जिनमें एक वैचारिक अखाड़े के सूरमा दूसरे के वीरों को और दूसरे के वीर पहले वाले के सूरमाओं को कोसते-धिक्कारते दिखते हैं। सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के जरिये साहित्य का इतिहास आज रोज लिखा जाता है। ऐसी गोष्ठियों में देर तक 'दुश्मन राग' बजता रहता है।

सेक्युलरों के 'लकड़ परदादा' मार्क्स का कहना है, 'सब आलोचना की पूर्व-शर्त धर्म की आलोचना है।' इस नजर से और सेक्युलर आलोचना पर विचार करने वाले एडवर्ड सईद की नजर से देखें, तो हिंदी का एक भी सेक्युलर, सच्चा सेक्युलर नहीं। कोई बताए कि इनमें से किसने एक धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म की आलोचना की? ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको उनसे डर लगता है। ऐसे आलोचक छद्म सेक्युलर हैं। कई बार ऐसे सेक्युलर सबसे बुरे कम्यूनल साबित होते हैं।

सोचता हूं कि दोनों को धता बताकर गाने लगूं- *तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद।*

गीतामें विचार अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता

गीतामें विश्व दर्शनकी समस्त अनुभूतियां हैं। गीताने विश्वको प्रभावित किया। इसका प्रभाव चीन और जापानतक पड़ा। गीता रहस्यमें प्रवृत्तिमार्गी दृष्टि है। गीता रहस्यको बहुत प्रतिष्ठित ग्रंथ माना जाता है। गीताका आनंद किसी भी पृष्ठसे लिया जा सकता है। कर्मसे संपन्नता आती है। कर्मसे यश मिलता है। कर्मसे युद्ध है। युद्ध कर्मसे विजय मिलती है।

❐ हृदयनारायण दीक्षित

गीता एक बार फिरसे अंतरराष्ट्रीय चर्चामें है। इसी माह आगे पीछे एक साथ दो घटनाएं हुईं। एक बार फिर गीताकी चर्चा अंतरराष्ट्रीय स्तरपर हो रही है। गीता भारतीय दर्शनका प्रतिनिधि दर्शन है। प्रधान मंत्रीने रूसके राष्ट्रपतिको गीता भेंट की है। पुतिन यहां भारत यात्रापर आये हुए थे। मोदी इसके पहले चीन, अमेरिका, जापान आदिके राष्ट्र प्रमुखोंको गीताकी प्रति भेंट कर चुके थे। इधर एक मजेदार घटना हुई। कोलकातामें गीताको लेकर विशाल सम्मेलन हुआ। कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्रकी संस्था यूनेस्कोने गीताको प्रतिष्ठित ग्रंथ घोषित किया था। गीता कर्म प्रेरणाका ग्रंथ है। गीता विशालकाय महाभारतका हिस्सा है। लेकिन महाभारतके भीष्मपर्वके मूल कथानकसे इसकी पर्याप्त संगति है। ऋग्वेदके रचनाकालके समयसे लेकर आजतक समयका बड़ा फासला है। गीतामें ऋग्वेदका दर्शन और अनुभूतियां हैं। अथर्ववेदका कालसूक्त गीतामें भयानक काल होकर प्रकट हुआ है। अर्जुनने श्रीकृष्णसे पूछा कि हे भगवान, आप उग्र रूप वाले कौन हैं। कृष्णने उत्तर दिया, कालोअस्मि लोकोक्षय प्रवृत्ते-मैं काल हूं और लोकोंको समाप्त करनेके लिए, प्राण लेनेके लिए प्रवृत्त हूं।

गीतामें विश्व दर्शनकी लगभग सारी अनुभूतियां हैं। महात्मा गांधी गीतापर मोहित थे। उन्होंने अपने अखबार यंग इंडियामें लिखा था, जब निराशा मेरे सामने आ खड़ी होती है और जब बिल्कुल एकाकी मुझको प्रकाशकी कोई किरण नहीं दिखाई देती, तब मैं गीताकी शरण लेता हूं। कोई न कोई श्लोक मुझे ऐसा दिखाई पड़ जाता है कि मैं विषम विपत्तियोंमें भी मुस्कुराने लगता हूं। मेरा जीवन विपत्तियोंसे भरा रहा और यदि वे मुझपर अपना कोई दृश्यमान अमिट चिह्न नहीं छोड़ सके तो इसका श्रेय भगवद्गीताकी शिक्षाओंको ही है। गांधी जीकी बात भावनात्मक है, लेकिन तथ्य भी यही है कि गीता प्रभावित करती है और सुख-दखमें समान भावकी दृष्टिका विकास करती है।

प्रसिद्ध यूरोपीय विद्वान एडविन अर्नाल्डने गीतापर ग्रंथ लिखा था सैलेशियल सॉन्ग। उसने गीताकी व्याख्या करने वाले अनेक पूर्ववर्ती विद्वानोंकी प्रशंसा की और लिखा कि इस ग्रंथके अभावमें अंग्रेजी साहित्य अधूरा रह जाता है। बंगालमें सन् १७८४ में एशियाटिक सोसाइटीकी स्थापना हुई। सोसाइटीकी प्रेरणासे चार्ल्स विलकिंसने गीताका अनुवाद किया। ईस्ट इंडिया कम्पनीकी मददसे यह अनुवाद लंदनमें छपा। तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगने इस कृतिकी लिखित प्रशंसा की थी। भारतके राष्ट्रपति रहे प्रख्यात दर्शनशास्त्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उन्होंने लिखा, भगवद्गीता एक दर्शन ग्रंथ है और एक प्राचीन धर्म ग्रंथ भी है। उन्होंने गीताका भाष्य किया। गीताने सारी दुनियाको प्रभावित किया। इसका प्रभाव चीन और जापानतक पड़ा। जर्मन धर्मके अधिकृत भाष्यकार जे. डब्लू. होवरने लिखा, यह सब कालोंमें सब प्रकारके धार्मिक जीवनके लिए प्रमाणिक है। इसमें इंडो जर्मन धार्मिक इतिहासके महत्वपूर्ण दौरका प्रमाणिक निरूपण है। लोकमान्य तिलकने भी गीताकी व्याख्या की और गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा। गीता रहस्यमें प्रवृत्तिमार्गी दृष्टि है। गीता रहस्यको बहुत प्रतिष्ठित ग्रंथ माना जाता है।

गीताका आनन्द किसी भी पृष्ठसे लिया जा सकता है। विश्वरूपको ही देखिये, संजयने धृतराष्ट्रको बताया, रोमांचित विस्मृत अर्जुनने श्रीकृष्णको प्रणाम किया और कहा मैं आपके शरीरमें सभी देवताओं और तमाम जीवोंको देख रहा हूं। मैं कमलासीन ब्रह्मा, शिव और सभी ऋषियोंको एवं सर्पोंको देख रहा हूं। आपके अनेक हाथ हैं, अनेक मुख हैं और अनेक आंखें हैं। एक ही केन्द्रपर समूचे ब्रह्माण्डको देखना बड़ी बात है। श्रीकृष्ण द्वारा दिखाये गये दिव्यरूप ऋग्वेदके पुरुषसे मिलते हैं।

ऋग्वेदका पुरुष भी सहस्त्रशीर्षा, सहस्त्र पैरों वाला है। गीतामें अर्जुन द्वारा देखे गये विश्वरूपका वर्णन है। अर्जुन इस रूपको देखकर कांप उठा और बोला अनेक मुखों, आंखों, भुजाओं, पैरों, पेटों, बड़े-बड़े दांत वाले इस भयानक रूपको देखकर सब डर गये हैं। अर्जुनने पूछा, आप कौन हैं। भयानक उग्र रूप वाला तू कौन है। आपको नमस्कार है। मैं जानना चाहता हूं कि तू आदिदेव कौन है। श्रीकृष्णने कहा, मैं लोकोंका क्षय करने वाला काल हूं। काल अपना काम करता है। इस मान्यताको नियतिवाद कहते हैं। कर्मसे संपन्नता आती है। कर्मसे यश मिलता है। कर्मसे युद्ध है। युद्ध कर्मसे विजय मिलती है। राज्यके सुख मिलते हैं। यह पुरुषार्थवाद कहलाया। पुरुषार्थवादी कर्मपर भरोसा करते हैं और नियतिवादसे इनकार करते हैं। गीतामें दोनों हैं। कर्मयोग गीताका केन्द्रीय विचार है। वैदिक काल भी कर्म प्रधान था। ऋग्वेदके एक मंत्रमें कहते हैं कि देवता परिश्रम करने वालेके मित्र बन जाते हैं। आलसी और अकर्मण्य लोगोंकी सहायता देवता नहीं करते। यही विश्वास भारतीय दर्शनमें एवं उपनिषद् आदि ग्रंथोंमें उपस्थित है। भारतके दर्शनका आकर्षण सारी दुनियामें है।

रूसके राष्ट्रपति पुतिनके लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि उन्हें सत्कार देने वाला व्यक्ति भारतका प्रधान मंत्री है। गीताकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीनके नेता वारिस पठानने कहा है कि यदि मोदीने गीताकी जगह कुरान भेंट की होती तो ज्यादा बेहतर होता। एआईएमआईएमका कुरान भेंट करनेका बयान निन्दनीय है। कुरान और गीताकी तुलना नहीं की जानी चाहिए थी। सत्यनिष्ठ तुलनामें मृदु शब्द ही नहीं निकलते। ऐसे बयान देशको कमजोर करते हैं। दुर्भाग्यसे इस्लामी राजनीतिमें कट्टरपंथ है। उनके यहां कोई कृष्ण नहीं हुआ। इस राजनीतिमें अलगाववाद है। इस्लामी राजनीतिक चिन्तनमें दुर्भाग्यसे कोई दार्शनिक नहीं हुआ। इसीलिए इस्लामपर बहस नहीं हो सकती। गीताका जन्म ही कुरुक्षेत्रमें दो सेनाओंके मध्य खड़े अर्जुनके विषादसे हुआ। श्रीकृष्णने अर्जुनको ज्ञान, कर्म और भक्तिकी धाराएं समझायीं। जीवनको कर्म प्रधान बताया। सब बतानेके बाद श्रीकृष्णने प्रश्न किया कि सब सुननेके बाद आपका मन कैसा है। अर्जुनने उत्तर दिया, आपकी कृपासे हमारा मोह नष्ट हो गया-नष्टो मोहा। स्मृति लौट आयी-स्मृति लब्धा। हिन्दुओंपर बहुदेवपूजक होनेके आरोप लगाते हैं।

हिन्दू बहुदेववादी नहीं एकेश्वरवादी और बहुत देव उपासक हैं। इस आलेखकी अंतिम बात, पूरी गीता पढ़ते समय बार-बार ऐसा प्रतीत होता है कि बस अब हो गया, लेकिन गीताके अंतिम अंशमें विचार अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रताका उल्लेख है। दुनियाका कोई भी पंथ, मजहब, रिलिजन ऐसे उपदेश नहीं देता। श्रीकृष्ण कहते हैं, मैंने सभी रहस्योंसे बड़े रहस्य वाला ज्ञान बताया है। इसपर गहन विचार करो और जैसी इच्छा हो वैसा करो-यथेच्छसि तथा कुरु। भारतीय चिंतन और ज्ञान परम्परामें कहीं भी असहमतको पीड़ित करने या मार देनेकी बात नहीं है। सहमत और असहमत दोनों विकल्प यहां व्यवहारिक रूपमें भी सुस्पष्ट हैं। बड़ी बात है कि युद्धसे अलग होनेकी घोषणा करने वाले अर्जुनसे कृष्ण कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु-जो इच्छा हो सो करो।

नए साल में नया वर्ल्ड आर्डर दिखेगा...

भू-राजनीतिक परिस्थितियों के लिहाज से साल 2025, दुनिया के साथ-साथ भारत के लिए भी उथल-पुथल भरा रहा। पुराने रिश्तों में दरार पड़ी, वहीं जिनसे बरसों से दूरी थी, वह पास आ गए। दिसंबर के पहले सप्ताह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के बाद नए वर्ल्ड आर्डर के बदलने को लेकर चर्चा और तेज हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत की स्थिति की व्याख्या करते हुए पूर्व राजनयिक और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे पंकज सरन दावा करते हैं कि नए साल में नया वर्ल्ड आर्डर (नई विश्व व्यवस्था) दिखेगा। यूक्रेन 2026 में अपनी ओर से युद्ध जारी नहीं रख पाएगा और शक्ति संतुलन की नई तस्वीर साफ हो जाएगी। भारत के लिए इसे संक्रमण काल ठहराते हुए वह कहते हैं कि हमें संभलकर आगे बढ़ना होगा। सरन रूस में भारतीय राजदूत रह चुके हैं। 2015 में जब वह बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त थे, उस समय ऐतिहासिक भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते को संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था। विदेश मंत्रालय में नेपाल और भूटान से संबंधित उत्तरी प्रभाग के प्रमुख के रूप में भी पदस्थ रहे। वर्ष 2018 से 2021 तक उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अधीन रणनीतिक मामलों के लिए उप राष्ट्रीय

सप्ताह का साक्षात्कार

सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने समुद्री सुरक्षा, पड़ोस नीति और प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक सुरक्षा सहित क्षेत्रीय और वैश्विक रणनीति निर्माण का कार्यभार संभाला। वर्तमान में वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। दैनिक जागरण की समाचार संपादक रुमनी घोष ने उनसे बदलती परिस्थितियों में भारत की विदेश नीति और सुरक्षा नीति दोनों पर विस्तार से चर्चा की। प्रस्तुत हैं बातचीत के मुख्य अंश :

• क्या वर्ल्ड आर्डर बदल रहा है?

– यह सही है कि नया वर्ल्ड आर्डर (नई विश्व व्यवस्था) बन रहा है। नए साल में यानी वर्ष 2026 में यूक्रेन युद्ध जारी नहीं रख पाएगा। बीते चार सालों में अब रूस भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन, रूस के सैन्य ताकत को संभाल नहीं पा रहा है। युद्ध थमते ही वर्ल्ड आर्डर की नई तस्वीर साफ होने लगेगी।

• क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से वर्ल्ड आर्डर बदलने का कोई संबंध है? क्या यह ट्रिगर प्वाइंट था?

– राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर हुआ है। दुनिया की नजरें इस दौरे पर टिकी हुई थीं। आने वाले समय में यह बहुत सी नीतियों पर असर भी डालेगा, लेकिन इस दौरे से वर्ल्ड आर्डर बदलने की शुरुआत हुई है या फिर यह दौरा वर्ल्ड आर्डर बदल देगा, यह कहना सटीक नहीं होगा। इस मामले में हमें यथार्थवादी (रियलिस्टिक) होना होगा। यह सही है कि भारत और रूस दो शक्तियां हैं, लेकिन हमारी सीमाएं हैं। वर्ल्ड आर्डर बदलने में भारत की फिलहाल कोई सीधी भूमिका नहीं है। जहां तक भारत और रूस के बीच रिश्ते की बात करें तो बीते 25 साल से दोनों देशों के बीच सालाना समिट होता आ रहा है। इस बार का दौरा भी उसी क्रम में रहा। वर्तमान परिस्थितियों में यह अति महत्वपूर्ण इसलिए रहा कि राष्ट्रपति पुतिन चार साल बाद भारत आए। भारत ने उनके दौरे को स्टेट विजिट का सम्मान दिया। यह वर्किंग विजिट नहीं थी।

• स्टेट विजिट और वर्किंग विजिट में क्या अंतर है? इस दौरे से विश्व को क्या संदेश गया है?

– स्टेट विजिट खास मेहमानों को दी जाती है। इसका कूटनीतिक अर्थ यह होता है कि हमने संबंधित देश के शीर्ष प्रतिनिधि के साथ-साथ उस देश को भी सम्मान दिया है। इसमें राष्ट्रपति संबंधित देश के प्रतिनिधि के लिए विशेष राजभोज देते हैं। अन्य प्रोटोकाल का भी पालन किया जाता है। जैसा राष्ट्रपति पुतिन के दौरे के समय हमने देखा। वर्किंग विजिट में ऐसा नहीं होता है। इसके जरिये हमने दुनिया को संकेत दिया कि भारत-रूस के बीच रिश्ते कितने प्रगाढ़ हैं और आगे भी रहेंगे।

• क्या यह मान लिया जाए कि वर्ल्ड आर्डर के शीर्ष स्थान से अमेरिका फिसल रहा है और रूस-चीन और भारत गठजोड़ उभर रहा है?

– नहीं, इसे इस तरह से सीधे देखना सही नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत सहित दुनियाभर के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, यानी भू-राजनीतिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2026 की पहली तिमाही या छमाही तक यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा। यूक्रेन अपने दम पर इस युद्ध को आगे नहीं खींच पाएगा। अब यूक्रेन युद्ध का वर्ल्ड आर्डर से क्या संबंध है, यह जानने के लिए आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर गौर करना होगा, जिसमें वह बार-बार कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू ही नहीं होना चाहिए था। वह इस युद्ध के पक्ष में नहीं हैं और आगे युद्ध के लिए यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे। युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप और पुतिन के बीच समय-समय पर संवाद हो रहे हैं। अलास्का में हुई दोनों की मुलाकात इसका अहम पड़ाव था। उधर, यूरोप अभी भी यूक्रेन के पक्ष में खड़ा है। इसकी वजह से अमेरिका और यूरोप के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। इससे ट्रांस-अटलांटिक अलायंस टूटने की कगार पर है। यह अलायंस 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक पटल पर उभरा था। ट्रांस अटलांटिक अलायंस अमेरिका और यूरोप के बीच के राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संबंधों को संदर्भित करता है। इसका आधार नाटो है। यानी आसान भाषा में कहें तो इस अलायंस के जरिये मुख्य रूप से यूरोपीय देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका पर है। अब ट्रंप ने यूरोप को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाने के संकेत दे दिए हैं। इसके लिए उन्होंने यूरोप को रक्षा बजट में बढ़ोतरी करने की सलाह देते हुए इसे पांच प्रतिशत करने की सलाह दी है।

• एक आम धारणा है कि डोनाल्ड ट्रंप तो अपना रुख समय-समय पर बदलते रहते हैं। फिर उनके इस बयान को इतनी गंभीरता से क्यों लिया जा रहा है? इसे बदलाव की मुख्य वजह क्यों माना जा रहा है?

– अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रिपोर्ट (अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति) जारी किया जाता है। हाल ही में यह रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें ट्रंप की नीतियों और बीते नौ महीने में घटी घटनाओं का उल्लेख है। रिपोर्ट में रूस-यूक्रेन युद्ध, अमेरिका के साथ यूरोप के बदलते कूटनीतिक रिश्ते सहित अन्य मामलों का विस्तार से उल्लेख है। एक तरह से यह नीतियों का वह दस्तावेज है, जिसके आधार पर ट्रंप अमेरिका को आगे ले जाना चाहते हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा) मुहिम चलाकर सत्ता में आए राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि अमेरिका को अनावश्यक खर्च कम करना चाहिए। दूसरे देशों का बोझ उठाने के बजाय खुद की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। इस वजह से ही अमेरिका-यूरोप के बीच पुराना गठजोड़ टूटने की कगार तक पहुंच गया है और यही वर्ल्ड आर्डर को बदलने में सहायक होगा।

• पाकिस्तान और चीन के साथ पहले ही तनाव, बांग्लादेश से बिगड़ते रिश्ते, मालदीव में भारत विरोधी भावना और नेपाल व श्रीलंका में अस्थिरता। स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए?

–जो कुछ हो रहा है, वह हमारे नियंत्रण से बाहर है। यदि पहलगाम नहीं होता तो आपरेशन सिंदूर नहीं होता। आपरेशन सिंदूर नहीं होता तो अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्ते नहीं गहराते। प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्तापलट नहीं होता तो बांग्लादेश से रिश्ते नहीं बिगड़ते। बाकी देशों में अंदरूनी असंतोष है। चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि हमेशा ही सभी से बेहतर रिश्ते रहेंगे, इसलिए हर देश के हर राजनीतिक दलों से तालमेल बनाकर नए सिरे से मेल बनाने की कोशिश है।

• क्या इससे अमेरिका की हेजेमनी (नायकत्व या वर्चस्व) खत्म नहीं हो जाएगी? यदि ऐसा होता है इसका फायदा किसे मिलेगा?

– अमेरिका में विपक्ष यही मुद्दा तो उठा रहा है। उनका कहना है ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिका एक तरह से अपनी वैश्विक छवि को खो रहा है। अपनी भूमिका से पीछे हट रहा है। विशेषज्ञ और विपक्ष दोनों यह चिंता जता रहे हैं कि इसका फायदा चीन को मिलेगा। हालांकि ट्रंप की नीति और उनके समर्थक दोनों ही इससे सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि अमेरिका को नायकत्व की पदवी के लिए दूसरों का बोझ उठाने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने पर ध्यान देना चाहिए। अनावश्यक खर्च को बंद करना चाहिए। इससे ही अमेरिका अपनी ऊंचाई पा सकेगा।

• तो नया वर्ल्ड आर्डर किस तरह का होगा? दुनिया के किस हिस्से में बदलाव नजर आएगा?

– यह दो तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है। एक अमेरिका-रूस और दूसरा, अमेरिका-चीन। हालांकि तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं है कि दोनों में से कौन सा गठजोड़ उभरकर सामने आएगा। पिछले कुछ महीनों से चले आ रहे ट्रेंड को देखेंगे तो अमेरिका और रूस के बीच दुश्मनी कम होती नजर आ रही है। दोस्ती या यूं कहें कि पार्टनरशिप पनप रही है। दूसरी और अमेरिका, चीन से भी अपने संबंध सुधार रहा है। पिछले हफ्ते ही ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात हुई। यह दोनों ही स्ट्रैटेजिक एनिमी यानी रणनीतिक दुश्मन हैं और अमेरिका दोनों से ही रिश्ते सुधारने में लगा हुआ है। अगर यह प्रयोग सफल होता है तो दुनिया में जबरदस्त जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा। इसका असर दुनियाभर के देशों के आपसी रिश्तों पर भी पड़ेगा। भारत भी इसमें शामिल है।

• कूटनीतिक और सुरक्षा दोनों की दृष्टि से भारत के लिए यह स्थिति कैसी है? भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए?

– चुनौतीपूर्ण...! खासतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। भारत को बहुत सतर्कता के साथ सारी स्थितियों का विश्लेषण करना होगा। हर देश के साथ अलग नीति बनाकर संतुलन स्थापित करना होगा। इस पर भारत को बहुत सतर्क और पैनी नजर रखनी होगी।

• नए वर्ल्ड आर्डर में रूस-चीन-भारत गठबंधन की संभावना क्यों नहीं है? यदि ऐसा होता है तो क्या इससे दुनियाभर में एशिया का वर्चस्व बढ़ेगा?

– यह सही है कि तीनों देशों के शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की। तीनों के बीच व्यापार सहित कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी हुई, लेकिन इस रिश्ते को आगे बढ़ाकर कहां तक ले जाना है, इसको लेकर भारत में तो अभी तक पूर्ण सहमति नहीं है। दरअसल, चीन के साथ हमारे संबंध खराब रहे हैं। हमारे बीच युद्ध हुए हैं। कई हिस्सों में सीमा विवाद अभी भी अनसुलझे हुए हैं। चीन की विस्तारवादी नीतियों की पीड़ा भारत ने झेली है। पुराने अनुभवों की वजह से हमारे लिए चीन पर भरोसा कर पाना मुश्किल है।

• एक अवधारणा यह भी बनाई जा रही है, जिसमें सभी देश अपने-अपने हिस्से में वर्चस्व कायम करें। दुनिया पर किसी एक देश या किसी एक गठजोड़ का वर्चस्व नहीं होगा?

– थ्योरिटिकल (सैद्धांतिक) अवधारणा है... यह व्यावहारिक नहीं।

• आप वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर परिस्थितियां कितनी विषम हैं?

– भौगोलिक स्थिति की वजह से हमें पाकिस्तान और चीन दोनों से ही हमेशा सचेत रहने की जरूरत है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं और हमें उस मोर्चे पर भी जूझना पड़ रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान की बढ़ती उपस्थिति हमारे लिए चिंता बढ़ाने वाली है। हालांकि सरकार और एजेंसियां इसको लेकर पहले से ही बहुत सतर्क हैं। म्यांमार और नेपाल की स्थिति पर भी नजर रखने की जरूरत है।

Dainik Jagaran Page No-13

प्राचीन स्टोइक दर्शन की नई चमक

आज का समय जितना गतिशील है, उतना ही थकाने वाला भी। हर तरफ शोर है- सूचनाओं का, महत्वाकांक्षाओं का, इच्छाओं और आशंकाओं का। दुनिया जितनी अधिक उन्नत, जुड़ी हुई और सुविधासंपन्न होती जा रही है, मन उतना ही बिखरा, व्याकुल और दिशाहीन। तकनीकी ने हमें बहुत कुछ दिया, पर स्वयं से मिलने का एकांत छीन लिया। चिंता और बेचैनी का बोझ मनुष्य आज भी उतना ही ढोता है, जितना 2000 वर्ष पहले ढोता था। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है, क्या चार ईसा-पूर्व में कार्डोबा (स्पेन) में जन्मे लुसियस अन्नायस सेनेका, जो यीशु के समकालीन भी थे, आज की इस थकाने वाली मानसिक उथल-पुथल में कोई राह दिखा सकते हैं? यहीं से 'स्टे काम विद सेनेका' की प्रासंगिकता खुलती है। जना कैप्री और चरन डियाज ने सेनेका की रचनाओं से चुने गए महत्वपूर्ण उद्धरणों और प्राचीन शिक्षाओं को आधार बनाकर 69 विचारोत्तेजक

यतीन्द्र मिश्र

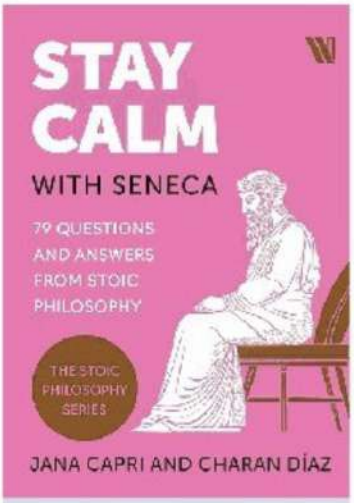

पुस्तक : स्टे काम विद सेनेका
लेखक : जना कैप्री, चरन डियाज
प्रकाशक : वेस्टलैंड बुक्स, चेन्नई
मूल्य : 499 रुपये

प्रश्नों की एक ऐसी शृंखला तैयार की है, जो जीवन की सामान्य, लेकिन निर्णायक सार्वभौमिक चिंताओं को छूती है। यहां नैतिकता, भय, अनिश्चितता, प्रेम, मृत्यु, स्वतंत्रता, थकान, विश्राम, आदर्शों, सीमाओं और जीवन को सरल बनाने की कला है। एक सच्चे रोमन स्टोइक दार्शनिक के रूप में सेनेका ने जीवन भर इस बात पर मनन किया कि मनुष्य अपने मानसिक दुखों से कैसे मुक्त हो सकता है। शायद यही कारण है कि उनके विचार आज के समय में भी उपयोगी और उपचारक प्रतीत होते हैं।

पुस्तक की संरचना तीन सहज हिस्सों में है, पहले जीवन-प्रश्नों से जूझते 'सीकर' की जिज्ञासा, फिर सेनेका का उत्तर और अंत में एक मनोवैज्ञानिक चिंतन। सेनेका प्रकृति-तुल्य उदाहरण देकर समझाते हैं कि पशु केवल वास्तविक खतरे पर ही डरते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। मनुष्य ही न घटित हुए अतीत और न दिखाई देने वाले भविष्य की कल्पनाओं से अनावश्यक पीड़ा पाता रहता है।

कुल मिलाकर सार यह है कि तुलना, लालसा और भ्रम से निकलकर कृतज्ञता, आत्म-परिचय, उद्देश्य और आत्मानुशासन ही भीतर की शांति के वास्तविक स्तंभ हैं। लगता है जैसे प्राचीन दार्शनिक ने आज की भाषा, आज की समस्याओं को ध्यान में रखकर सीधे बातचीत की हो। आधुनिक जीवन के उतार-चढ़ावों में एक विचारशील और संतुलित पुस्तक।

Dainik Jagaran Page No-9

राष्ट्र-निर्माण की सतत प्रक्रिया

कन्हैया झा

राष्ट्र-निर्माण कोई आकस्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह गहन विचारों, कर्तव्यों, समर्पण और सतत प्रयासों का प्रतिफलन है। भारतवर्ष की इस यात्रा के अहम पड़ाव पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सौ वर्षों का अहर्निश योगदान अमूल्य है, जो समाज के भीतर एक चेतना उत्पन्न कर भारत को आत्मनिर्भर, संगठित और सशक्त राष्ट्र बनाते हुए परमवैभव की ओर पथारूढ़ कर रहा है। वहीं, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति को प्रायः राष्ट्रीय विकास के प्रमुख स्तंभों के रूप में देखा जाता है, परंतु गहराई से विचार करें तो इनके प्रभाव की एक सीमा होती है।

यह पुस्तक स्मरण कराती है कि संघ दशकों से जो कार्य करता आया है, वे सभी कार्य आज कैसे विकसित भारत का केंद्रीय विमर्श बनकर संपूर्ण राष्ट्र के लिए अत्यंत प्रासंगिक हो गए हैं। इस पुस्तक में पांच मुख्य आयामों पर प्रकाश डाला गया है- आत्मनिर्भरता, नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता और कुटुंब प्रबोधन। ये आयाम संघ के विचारों और कार्यों के मूल में विद्यमान हैं। संघ ने प्रारंभ से ही इन मूल्यों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस पुस्तक में सरसंघचालकों के विचार और वक्तव्यों सहित संघ परिवार पर भी प्रकाश डाला गया है, जो इन पंच परिवर्तनों की आवश्यकता और उनकी प्रक्रिया को समझने में सहायक हैं।

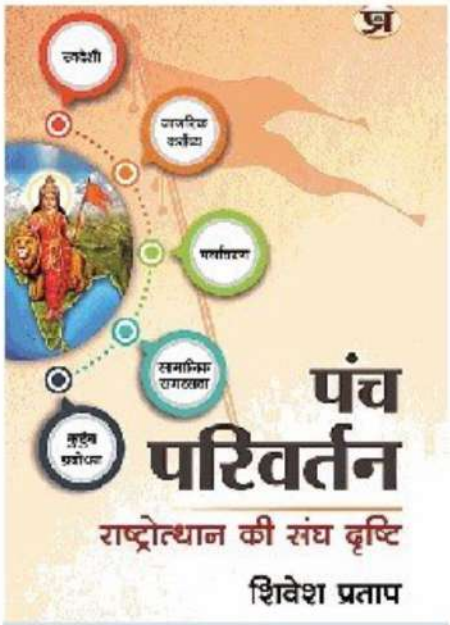

पुस्तक : पंच परिवर्तन : राष्ट्रोत्थान की संघ दृष्टि
लेखक : शिवेश प्रताप
प्रकाशक : प्रभात प्रकाशन
मूल्य : 500 रुपये

इस वर्ष संघ के सौ वर्षों की यात्रा पूर्ण हुई है। यह यात्रा केवल संगठन निर्माण की यात्रा नहीं है, यह भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के चेतना जागरण की यात्रा भी है। पुस्तक में इन विचारों के आधार पर यह प्रस्तुत किया गया है कि कैसे पंच परिवर्तन संघ के प्रयासों और समाज के सहयोग से उभरते हुए भारत की आंतरिक, वैश्विक चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करते हुए 'विकसित भारत' के लक्ष्य को पूर्णता प्रदान करते हैं।

Dainik Jagaran Page No-9

कथक की कहानी, गुरुओं की जुबानी

यह पुस्तक कथक के अनेक घरानों के शीर्षस्थ नृत्य-कलाकारों के जीवन व व्यक्तित्व तथा कथक के अनेक अनछुए आयामों एवं पहलुओं को प्रस्तुत करती है। सत्य कल्पना से भी सुंदर होता है- ऐसा इस पुस्तक को पढ़कर प्रतीत होता है

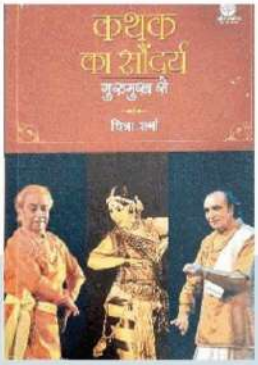

पुस्तक : कथक का सौंदर्य गुरुमुख से
लेखिका : चित्रा शर्मा
प्रकाशक : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास
मूल्य : 280 रुपये

ब्रजबिहारी

साहित्य की कथात्मक विधाओं की समीक्षा करते-करते साक्षात्कार आधारित किसी पुस्तक को पढ़ना ताजा हवा के झोंके की तरह लगता है। पाठक के तौर पर एक सुखद अनुभूति होती है, क्योंकि इस विधा में वास्तविक जीवन के पात्रों और उनके विचारों की प्रामाणिकता अधिक होती है। इसमें पारदर्शिता होती है और साक्षात्कारकर्ता एवं विषय के बीच सीधा संवाद होता है। इसका मूल उद्देश्य सूचना, विचार और व्यक्तित्व को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करना है। इस दृष्टि से कला मर्मज्ञ चित्रा शर्मा की पुस्तक 'कथक का सौंदर्य गुरुमुख से' उल्लेखनीय है।

निस्संदेह कथक एक ऐसा विषय है, जिसे आम पाठक की रुचि नहीं हो सकती है, लेकिन जब इस नृत्य शैली से आपका परिचय पंडित बिरजू महाराज और सितारा देवी सरीखी महान विभूतियों के अनुभव के निचोड़ के रूप में हो तो कोई भी पाठ अरुचिकर नहीं लग सकता है। इस पुस्तक में कथक के इन दो शीर्ष हस्ताक्षरों से लेकर आज के सक्रिय समकालीन अनेक पुरुष एवं स्त्री कथक नृत्यकारों तथा कला समीक्षा के समकालीन व्यक्तित्व तक से की गई बातचीत को साक्षात्कार के रूप में सम्मिलित किया गया है। इस क्रम में कथक नृत्य के अनेक घरानों यथा- लखनऊ, जयपुर, बनारस, रायगढ़ आदि के शीर्षस्थ नृत्यकारों के जीवन और व्यक्तित्व के अतिरिक्त कथक के अनेक अनछुए आयामों एवं पहलुओं को जानने और समझने का अवसर प्राप्त होता है।

मंदिरों में जन्म लेने और राजाओं-नवाबों के दरबार में आश्रय पाकर फलने-फूलने से लेकर शास्त्रीय कला के रूप में स्थापित होने तक कथक ने लंबी यात्रा की है। कथक गुरुओं और समीक्षकों के साक्षात्कार के माध्यम से लेखिका ने इस यात्रा को समेटने का प्रयास किया है। पुस्तक उस तथ्य को भी पुनर्स्थापित करती है कि सभी कलाएं लोक से ही निकली हैं। लिहाजा कथक की बारीकियों को नहीं समझने वाले व्यक्ति भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं।

यह पुस्तक कथक में पौराणिक कथानकों के अस्वीकरण और शृंगारिकता के प्रवेश पर भी प्रकाश डालती है। यह सब मुस्लिम शासकों के प्रभाव में हुआ। बकौल सितारा देवी, 'मुस्लिम नवाब पौराणिक कथानकों को तो स्वीकार कर नहीं सकते थे, इसलिए कथानकों की जगह शृंगारिकता ने ले ली। इसी कारण अदाएं, नखरे और नजाकत कथक में शामिल हुए और कथक दरबारों की शोभा बनकर रह गया।'

इस पुस्तक को पढ़ते हुए कथक नृत्यकारों के व्यक्तित्व और कृतित्व के साथ ही उनके अपने समय की अनुगूंज भी सुनाई देती है। पंडित बिरजू महाराज बदलते हुए समाज में इलेक्ट्रानिक्स गैजेट पर बढ़ती निर्भरता पर जब यह कहते हैं, 'निर्भर न होना मेरी प्रकृति है। निर्भर हो जाना नए बच्चों की प्रकृति है। देखें, यह जो नए युग की निर्भरता है, इसमें सुकून नहीं। बेचैनियां हैं, शोर है, उग्रता है और भागमभाग। इनकी अतियों से जीवन में अशांति बढ़ रही है।' तो ऐसा लगता है जैसे वह हर अभिभावक की भावनाओं को शब्द दे रहे हैं।

इसी तरह प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना शोभना नारायण ने अपने साक्षात्कार में इस नृत्य शैली के विभिन्न घरानों में प्रतिस्पर्धा को लेकर जो टिप्पणी की है, वह सिर्फ कला और कलाकार ही नहीं, बल्कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में उच्चतर लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। वह कहती हैं, 'अपने काम को लेकर निश्चिंत हैं, तब राजनीतिक ताकत मायने नहीं रखती, क्योंकि अपनी सुरक्षा पर आपका विश्वास है। जो मैं कर रही हूं, दिल से कर रही हूं।' उनका यह आत्मविश्वास पाठक को गहरे तक प्रभावित करता है।

Dainik Jagaran Page No-9

आजकल

अनंत विजय

anant@nda.jagran.com

संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव का खेल

हाल में दो ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं, जिन्हें विश्लेषित करने पर यह पता चलता है कि विपक्ष फिर से संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने की राजनीति कर रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र में चर्चा के क्रम में विपक्ष ने चुनाव आयोग के बहाने सरकार को घेरने का प्रयास किया। वहीं, मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जीआर स्वामीनाथन पर महाभियोग चलाने की मांग भी विपक्षी दलों ने की है। उनका आरोप है कि जीआर स्वामीनाथन निष्पक्ष रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में, महाभियोग के समय को लेकर भी सवाल पैदा हो रहे हैं

ज्ञानेश कुमार। पाइल

जीआर स्वामीनाथन। पाइल

संसद के शीतकालीन सत्र में चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हुई। यह चर्चा चुनाव सुधार पर कम, मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) पर केंद्रित हो गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर अपने हमले को सदन में भी जारी रखा। वोट चोरी के आरोप दोहराए। अपनी पिछली प्रेस कांफ्रेंस में कही गई बातों को दोहराते हुए चुनाव आयुक्त की आलोचना की। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने तो एसआइआर कराने के चुनाव आयोग के अधिकार पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया। सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी अपनी बात रखी। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में चर्चा का उत्तर देते हुए विपक्ष के सभी आरोपों को न केवल खारिज किया, बल्कि कांग्रेस को ही कठघरे में खड़ा कर दिया। इस चर्चा से भ्रम भी दूर हुआ। कांग्रेसी इकोसिस्टम निरंतर ये नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही थी कि मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया में बदलाव किया। समिति से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कानून बनाकर बाहर कर दिया। कानून बनाकर चुनाव आयुक्तों को जीवनभर के लिए केस मुकदमे से बचने के लिए कानूनी कवच दे दिया। तीसरा कानून बनाकर वोटिंग के दौरान के सीसीटीवी फुटेज को 45 दिनों तक ही रखने का नियम बना दिया। गृह मंत्री शाह ने तीनों आरोपों की धज्जियां उड़ा दीं।

वर्ष 2023 में पहली बार चुनाव आयुक्तों के चयन को एक समिति से कराने का कानून पास हुआ। उसी समय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बताया था कि मुख्य न्यायाधीश को हटाने की बात गलत है। दरअसल 2023 के पहले प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती थी। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद अंतरिम व्यवस्था बनी थी। मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति का सदस्य बनाया गया था। सरकार ने जब कानून बनाया तो अंतरिम व्यवस्था समाप्त हो गई। इसको ही कांग्रेसी इकोसिस्टम जोर-शोर से प्रचारित कर रहा था, अर्धसत्य के साथ। मतदान के दौरान की सीसीटीवी फुटेज को सहेजने को लेकर भी भ्रम फैलाया गया था। चुनाव से संबंधित विवाद पर बाद दायर करने की अवधि को 45 दिनों तक है तो सीसीटीवी फुटेज को वर्षों तक सहेजने का क्या औचित्य। चुनाव विवाद पर यदि कोई बाद दायर होता है तो कोर्ट के आदेश पर फुटेज को सहेजा जा सकता है। चुनाव आयोग ने कोई नया नियम नहीं बनाया है। लोकसभा में शाह ने स्थिति साफ की, लेकिन इकोसिस्टम अब भी अर्धसत्य फैलाने में लगा हुआ है।

इस दौरान ही एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जी. आर. स्वामीनाथन पर विपक्षी दलों ने महाभियोग चलाने का मांग पत्र लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संसद अखिलेश यादव, कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की संसद कनिमोई समेत सौ से अधिक सांसदों ने जस्टिस स्वामीनाथन पर महाभियोग के प्रस्ताव पत्र पर हस्ताक्षर किए। विपक्षी दलों के इन सांसदों ने मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन पर आरोप लगाया है कि वह निष्पक्ष होकर अपने न्यायिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे। उन पर एक वकील का पक्ष लेने का आरोप भी लगाया गया है। विपक्ष को महाभियोग का अधिकार है, लेकिन महाभियोग की टाइमिंग को लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं।

दरअसल तमिलनाडु के मदुरै में थिरुपनकुंद्रम पहाड़ियों पर स्थित मंदिर में दीपक जलाने से जुड़ा मामला है। पहाड़ी पर स्थित मंदिर के पास दीपथून में दीप जलाने की मान्यता है। दीप जलाने को लेकर पास के दरगाह से जुड़े लोगों ने आपत्ति की थी। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने दीपस्थान पर दीप जलाने की अनुमति दे दी। इसके विरोध में कुछ लोग हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट में जस्टिस स्वामीनाथन ने दीप जलाने की अनुमति दी। ये भी आदेश दिया गया कि केवल 10 लोग दीप जलाने के समय दीपस्थान पर उपस्थित रहें। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस प्रशासन ने दीप जलाने की अनुमति नहीं दी। हाई कोर्ट के दीप जलाने के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है। लेकिन राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन दीप नहीं जलाने देने पर अड़ी है। सुप्रीम कोर्ट से इस मसले पर कोई फैसला आने के पहले ही तमिलनाडु की डीएमके ने आइएनडीआइए के अपने सहियों के साथ मिलकर लोकसभा अध्यक्ष को दीप जलाने का आदेश देने वाले जस्टिस के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव दे दिया।

दरअसल मदुरै की पहाड़ी पर स्थित मंदिर के पास एक दरगाह है। मंदिर दूसरी शताब्दी का बताय जाता है और दरगाह बहुत बाद में बना। दरगाह के बनने के बाद से ही पहाड़ी की जमीन को लेकर विवाद आरंभ हो गया था। वर्ष 1920 में पहली बार मामला कोर्ट पहुंचा था। मंदिर और दरगाह के बीच की जमीन को लेकर एक प्रकार की सहमति बनी हुई है। वर्ष 1994 में क्षतिग्रस्त दीपक के समय मंदिर में दीप जलाने की मांग की गई, क्योंकि पहाड़ी पर दीप जलाने की मान्यता रही है। वर्ष 1996 में कोर्ट ने पारंपरिक स्थान पर दीपक जलाने की अनुमति दी। वर्ष 2014 में दीपाथून पर दीप जलाने पर रोक लग गई और तब से रह-रहकर यह विवाद उठता रहता है। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और उनके मंत्रियों के सनातन को लेकर बयान आते रहते हैं। इस कारण सनातन मान्यताओं और परंपराओं पर राज्य सरकार के रुख पर कुछ कहना व्यर्थ है। इस आलेख का उद्देश्य इस विवाद पर लिखना नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग और न्यायपालिका पर विपक्ष के दबाव को रेखांकित करना है। अनेक अवसरों पर संविधान का गुटका संस्करण लहराने वाले विपक्ष के नेता और उनकी पार्टी के सांसद देश के संवैधानिक संस्थानों पर अनावश्यक दबाव बनने की चेष्टा करते हुए नजर आते हैं। उपरोक्त दो मामले इसके सटीक उदाहरण हैं। चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त को लेकर विपक्षी नेताओं ने कई बार अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को तो सरकार में आने पर जेल भेज देने तक की धमकी भी दे गई। कहा गया कि अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में आ गई तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा।

देश में संवैधानिक संस्थाओं को दबाव में लेने की विपक्ष की ये जुगत खतरनाक है और एक गलत परंपरा की नींव डाल रही है। अगर आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो दलों को मंथन करने की आवश्यकता है। अपने पार्टी संगठन को कसने की जरूरत है। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने वाले कार्यक्रम आरंभ करने की आवश्यकता है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराना न तो संविधान सम्मत है और न ही राजनीतिक रूप से ठीक है। विपक्षी दलों के नेताओं को इस बारे में विचार करना चाहिए। अगर इसी तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव डाला जाता रहा तो संभव है कि इन संस्थाओं से कोई गलत कदम उठ जाए। यह न तो विपक्ष के हित में होगा और न ही लोकतंत्र के हित में।

Dainik Jagaran Page No-9

आशा का दीया जीवन का अंधकार मिटाता है

उच्च शिक्षा में सुधार

शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी बनाने की योजना पर जो काम कर रहा है, वह सही तो है, लेकिन केवल इतने भर से बात बनने वाली नहीं है। उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ ही उनकी शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर भी बढ़ना चाहिए। यह ठीक है कि नई शिक्षा नीति के तहत इस दिशा में कई प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन एक तो उन पर अमल की गति बहुत धीमी है और दूसरे चुनिंदा शिक्षा संस्थानों में ही सुधार हो पा रहा है। उच्च शिक्षा के समक्ष जैसी चुनौतियां हैं और विशेष रूप से देश को जैसे सक्षम युवाओं की आवश्यकता है, उसे देखते हुए कुछ नए और ठोस उपायों पर शीघ्रता से काम किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा संस्थानों से ऐसे युवा निकलने चाहिए, जो उद्योग-व्यापार जगत की आवश्यकता पूरी करने में सक्षम हों। यह ठीक नहीं कि उच्च शिक्षा संस्थानों से निकले तमाम छात्र केवल शिक्षित बेरोजगारों की भीड़ बढ़ाएं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि देश में सरकारी के साथ निजी स्तर पर भी उच्च शिक्षा के तमाम संस्थान खुलते चले जा रहे हैं, क्योंकि यह देखने में आ रहा है कि छात्रों को आज की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम नहीं उपलब्ध कराया जा पा रहा है। निःसंदेह इसके चलते भी बड़ी संख्या में हमारे छात्र विदेश पढ़ने चले जाते हैं। उनमें से कम ही देश लौटते हैं।

एक समस्या यह भी देखने को मिल रही है कि शिक्षा संस्थानों में योग्य शिक्षकों का अभाव व्याप्त हो रहा है। उच्च शिक्षा के कई शिक्षण संस्थान ऐसे भी हैं, जिनमें पर्याप्त संख्या में शिक्षक ही नहीं हैं। दुर्भाग्य से सरकारी शिक्षण संस्थानों में भी यह स्थिति देखने को मिल रही है। यह सामान्य बात नहीं कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों तक में शिक्षकों के पद खाली हैं। राज्य स्तर के विश्वविद्यालयों की स्थिति भी अच्छी नहीं। इसी तरह व्यावसायिक शिक्षा के संस्थानों में भी शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। आखिर ऐसे कैसे काम चलेगा? पिछले कुछ समय से विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने केंद्र खोल रहे हैं। हो सकता है कि इसके चलते भारत के छात्रों के विदेश पढ़ने जाने का सिलसिला कुछ थमे, लेकिन आखिर हमारे अपने शिक्षा संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? एक प्रश्न यह भी है कि जो प्रतिष्ठित और बड़े शिक्षण संस्थान हैं, वे अन्य शिक्षण संस्थाओं में पठन-पाठन की गुणवत्ता सुधारने में कोई सहयोग क्यों नहीं दे सकते? यदि देश भर के छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना पसंद करते हैं तो इसका मतलब है कि सभी राज्यों में उच्च शिक्षा के अच्छे संस्थान नहीं हैं।

Dainik Jagaran Page No-8

पृथ्वी के मौसम में ग्रहों की भूमिका

मुकुल व्यास

पृथ्वी की जलवायु ने शुरू से ही बड़े उतार-चढ़ाव देखे हैं। कभी हिम युग आए तो कभी गर्म मौसम के दौर चले। विज्ञानी काफी समय से यह जानने की चेष्टा कर रहे हैं कि पृथ्वी की जलवायु में बदलाव किस वजह से हुए। अब नए अध्ययन में विज्ञानियों ने बताया है कि जलवायु में परिवर्तन हमारे ग्रह की कक्षा और धुरी के झुकाव में छोटे बदलावों की वजह से होता है। ये बदलाव मिलनकोविच साइकिल के नाम से जाने जाते हैं। पृथ्वी की धुरी का झुकाव लगभग 23.4 या 23.5 डिग्री है। इसी झुकाव की वजह से पृथ्वी तरह-तरह के मौसम का अनुभव करती है। ज्यादा झुकाव होने से मौसम ज्यादा चरम होते हैं, जबकि कम झुकाव से मौसम मध्यम होते हैं। ये बदलाव इसलिए होते हैं, क्योंकि धरती अकेले सूरज का चक्कर नहीं लगाती है। दूसरे ग्रहों का गुरुत्वीय खिंचाव लगातार धरती को खींचता रहता है, जिससे धीरे-धीरे उसका कक्षीय मार्ग, उसकी धुरी का झुकाव और उसके ध्रुव की दिशा बदल जाती है।

मंगल ग्रह भी विशाल गैसीय पिंडों से बहुत छोटा होने के बावजूद धरती के जलवायु चक्र पर बहुत ज्यादा असर डालता है

खगोल विज्ञानी जानते हैं कि बृहस्पति और शुक्र इन चक्रों में अहम भूमिका निभाते हैं। अब नए विश्लेषण से पता चलता है कि मंगल भी धरती के जलवायु चक्र पर असर डालता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के खगोल विज्ञानी स्टीफन केन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने कंप्यूटर पर मिलनकोविच चक्रों का अनुकरण किया, जिसमें मंगल के द्रव्यमान को शून्य से दस गुना तक उसके वर्तमान मूल्य में बदला गया। नतीजों से पता चलता है कि पृथ्वी पर मौसम के निर्धारण मंगल की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें जब मंगल का द्रव्यमान शून्य के करीब पहुंचता है, तो एक आवश्यक जलवायु पैटर्न पूरी तरह से गायब हो जाता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि 24 लाख वर्ष का विराट चक्र, जो लंबे समय तक जलवायु में उतार-चढ़ाव का कारण बनता है, सिर्फ इसलिए मौजूद है, क्योंकि मंगल ग्रह में सही गुरुत्वीय तारतम्य बैठाने के लिए काफी द्रव्यमान है। यह चक्र पृथ्वी और मंगल ग्रह की कक्षाओं के धीमे रोटेशन से जुड़ा है और इस बात पर असर डालता है कि लाखों वर्षों में पृथ्वी को कितनी धूप मिलती है।

यह नई खोज हमें किसी सिस्टम में दूसरे ग्रहों के असर को समझकर पृथ्वी जैसे बाहरी ग्रहों की आवास योग्यता का अनुमान लगाने में भी मदद करती है। ग्रहों के सही समीकरण में एक बड़े पड़ोसी ग्रह वाले स्थलीय ग्रह पर जलवायु में ऐसे बदलाव हो सकते हैं, जो बेकाबू ठंड को रोकते हैं या उसके मौसम को जीवन के लिए ज्यादा अच्छा बनाते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि पृथ्वी के मिलनकोविच चक्र सिर्फ पृथ्वी और सूरज के बारे में नहीं हैं। वे हमारे पड़ोस में समस्त ग्रहों के बीच चल रही अंतरक्रियाओं के परिणाम हैं, जिसमें मंगल हमारी जलवायु को आकार देने में एक बड़ी सहायक भूमिका निभाता है।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

Dainik Jagaran Page No-8

ध्वस्त हुए हवाई यात्रा के अरमान

हास्य-व्यंग्य

'तारे जमीं पर' और 'सितारे जमीं पर' फिल्मों की काफी धूम रही अपने देश में। और अभी धूम है 'हवाई यात्री जमीं' पर की। हालांकि यह कोई फिल्म नहीं, बल्कि हकीकत है। अभी तक विमान से यात्रा करने वाले खुद को कुछ अलग ही समझते थे। सिर्फ ट्रेन, बस से सफर करने वालों की तुलना में ही वे खुद को भाग्यशाली नहीं समझते थे, बल्कि एयरपोर्ट पर अपने बगल में प्रतीक्षा लाउंज में बैठे, महंगी दुकानों में सामान खरीदते या कैफे में भक्षण करते या अपने ही विमान में अपने ही बगल में बैठे विमान यात्री से भी खुद को भाग्यशाली समझते थे। न वे एक दूसरे से बातें करते थे, न एक दूसरे की ओर देखते थे। पता नहीं ऐसा क्यों था। हो सकता है एक दूसरे के बारे में सोचता होगा कि बगल वाला तो आफिस की ओर से कभी-कभार मिलने वाले टीए से जा रहा है, जबकि वह अपने पैसे से जा रहा है। हो सकता है दूसरा भी पहले के बारे में यही सोचता होगा या फिर आफिस के खर्च से जाने वाले खुद को इस कारण से श्रेष्ठ समझते होंगे कि वे तो सरकार या कंपनी के पैसे से हवाई यात्रा कर रहे हैं, जबकि उनके बगल में बैठा व्यक्ति अपने बटुए का पैसा डुबा रहा होगा। या इसी प्रकार के कुछ कारण रहे होंगे।

लगता है कि सबसे बड़ी विमान सेवा प्रदाता को विमान यात्रियों का यह दंभ-युक्त व्यवहार ठीक नहीं लगा। उसने निश्चय कर लिया कि विमान यात्रियों

विनय कुमार पाठक

> उड़ानों के रद होने से एयरपोर्ट पर जो नजारा दिखा, वह किसी भी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड को मात दे रहा था

को भी संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। उन्हें भी अपने सहयात्री से उसी प्रकार बातें करनी चाहिए जैसे ट्रेन के या बस के यात्रीगण अपने सहयात्री से करते हैं। मतलब भाई साहब आपको कहां जाना है आदि-इत्यादि।

इसमें सरकार का योगदान रहा। यहां एक बात और देखने में आई कि नियम से कोई काम किया जाए तो अव्यवस्था और अराजकता का माहौल हो जाता है। यदि नियम का पालन नहीं किया जाए तो सब कुछ ठीक-ठाक चलता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ट्रैफिक पोस्ट पर पुलिस के होने या ट्रैफिक लाइट के होने से जाम की समस्या काफी विकट हो जाती है। पुलिस या ट्रैफिक लाइट न होने पर यातायात सुचारु रूप से चलता रहता है। विमान सेवा के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए थे, जैसे पायलट के न्यूनतम घंटे का विश्राम या अधिकतम कार्य अवधि आदि। इन नियमों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा विमान यात्रियों को संवेदनशील बनाने में।

इन नियमों के चलते और यात्रियों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से कई फ्लाइट रद हो गईं और फिर एयरपोर्ट पर जो नजारा दिखा, वह किसी भी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के नजारे को मात दे रहा था। कुछ देर तक तो विमान यात्री एक दूसरे से दूरी बनाकर रहे, पर दर्द जब हद से गुजर गया तो फिर बातें करने लगे। अपना दुख बांटने लगे। मुख्य रूप से विमान कंपनी और इसके कर्मचारियों के अवगुणों के बारे में ही चर्चा होती रही। इसके अलावा अन्य बातें भी होने लगीं यात्रियों के बीच और फिर अन्य विमानन सेवा कंपनियों ने मौका देखकर चौका लगाना शुरू कर दिया। दिल्ली से होनुलुलु से अधिक किराया दिल्ली से जयपुर का हो गया। ऐसे में जो मन मसोस कर बटुआ ढीला कर हवाई यात्रा करते थे, उनके हवाई यात्रा का सपना हवा हवाई हो गया। अब तक जो दंभ वे पाले हुए थे, उससे मुक्त हो गए, क्योंकि वे भी जमीन पर आ गए।

response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-8

नियम-कानूनों की घातक अनदेखी

संजय गुप्त

> प्रत्येक बड़ी घटना के बाद कार्रवाई कर संदेश देने की कोशिश होती है कि शासन-प्रशासन सख्त है, पर यह सख्ती आगे हादसों को रोकने में सक्षम नहीं होती

गोवा के एक नाइट क्लब में लगी आग ने एक बार फिर सार्वजनिक एवं निजी इमारतों समेत हर जगह सुरक्षा की अनदेखी की पोल खोलकर रख दी। यह पहली बार नहीं है, जब किसी इमारत में आग लगने से लोगों की जानें गई हों। देश में रह-रह कर ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं और बड़ी संख्या में लोग उनमें मरते भी रहते हैं। ऐसी हर घटना के बाद सुरक्षा संबंधी कमियां बड़े पैमाने पर उजागर होती हैं। गोवा नाइट क्लब के मामले में भी उजागर हो रही हैं। उन्हें गिनाते हुए नाइट क्लब पर बुलडोजर चला दिया गया और उसके संचालकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह की कार्रवाई करते हुए यही संदेश देने की कोशिश की जाती है कि शासन-प्रशासन सख्त है और वह ऐसी कार्रवाई कर रहा है, जो नजीर बनेगी, लेकिन ऐसा कठिनाई से ही होता है, क्योंकि एक तो कार्रवाई एक सीमा तक ही होती है और दूसरे अनदेखी के लिए जिम्मेदार अधिकारी सजा से बच जाते हैं। वे ज्यादा से ज्यादा कुछ समय के लिए निलंबित होते हैं। नतीजा यह होता है कि बार-बार वैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, जैसी गोवा में देखने को मिली और जिसमें 25 लोगों की जान चली गई। इतनी अधिक जानें इसीलिए गईं, क्योंकि नाइट क्लब में आग से बचाव के कोई उपाय नहीं थे।

वैसे तो कोई इमारत ऐसी नहीं हो सकती, जिसमें आग लगने की आशंका न रहे, लेकिन भारत में आमतौर पर भवनों में सुरक्षा के जो जरूरी उपाय होने चाहिए, वे नहीं किए जाते। भवनों का निर्माण करते समय उनमें सुरक्षा और विशेष रूप से आग से बचाव के उपाय न करना एक अपराध ही है, लेकिन देश में ऐसे अपराध हर कहीं हो रहे हैं और उनकी रोकथाम के लिए संबंधित विभाग और सरकारें सक्रिय नहीं होतीं। गोवा के नाइट क्लब के बारे में यह सामने आ रहा है कि वह महीनों से बिना लाइसेंस के चल रहा था और उसमें सुरक्षा के उपाय भी नहीं थे। उसका निर्माण भी नियमों के विपरीत किया गया था। जब इस नाइट क्लब का नियमों का उल्लंघन करके निर्माण हो रहा था, तब संबंधित विभाग निष्क्रिय क्यों थे? ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस निर्माण के बारे में उन्हें कुछ पता न चला हो। तथ्य यह है कि इस नाइट क्लब के निर्माण और संचालन में बरती जा रही लापरवाही को लेकर कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन उन पर अधिकारियों ने भी ध्यान नहीं दिया। आखिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? सब जानते हैं कि अवैध निर्माण नगर निकायों और

अवधेश राजपूत

अन्य विभागों की मिलीभगत से होते हैं। इस तरह के निर्माण में आग से बचाव के उपायों के मामले में तो रिकार्ड कुछ ज्यादा ही खराब है।

गोवा की घटना के बाद ऐसी खबरें आ रही हैं कि देश के अन्य शहरों के तमाम रेस्त्रां और बैंक्वेट हाल, होटल आदि ऐसे हैं जहां सुरक्षा और विशेषकर आग से बचाव के पर्याप्त उपाय नहीं हैं। यदि सुरक्षा उपायों का आडिट किया जाए तो शायद ही कोई निजी या सार्वजनिक इमारत निर्माण और सुरक्षा संबंधी नियम-कानूनों की कसौटी पर खरी पाई जाए। जो भी गैर-कानूनी निर्माण होते हैं, उनके प्रति नगर निकाय के अधिकारीगण आंखें मूंदे रहते हैं। नियम विरुद्ध निर्माण में आर्किटेक्ट और ठेकेदार भी शामिल होते हैं। बहुत कम यह सुनने को मिलता है कि अवैध निर्माण में शामिल रहे किसी आर्किटेक्ट के खिलाफ कार्रवाई हुई हो और उसका लाइसेंस रद किया गया हो। लाइसेंस रद भी किया जाता है, तो कुछ महीने के लिए। ठेकेदारों के खिलाफ भी कभी कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती। समय आ गया है कि उन्हें भी अवैध निर्माण के लिए जवाबदेह बनाया जाए। आर्किटेक्ट या ठेकेदार अवैध निर्माण में भागीदार इसीलिए बनते हैं, क्योंकि उन्हें कड़ी कार्रवाई का कोई भय नहीं होता। आखिर उन्हें इसके लिए क्यों नहीं चेताया जाता कि वे अवैध और सुरक्षा उपायों की अनदेखी करने वाला निर्माण न होने दें, अन्यथा दंड के भागीदार बनेंगे।

प्रत्येक बड़ी घटना के बाद हर तरह की कार्रवाई कर यह संदेश देने की कोशिश होती है कि शासन-प्रशासन सख्त है। इससे शासन-प्रशासन की वाहवाही तो हो जाती है, लेकिन आम तौर पर यह सख्ती आगे दुर्घटनाओं को रोकने में सक्षम नहीं होती। यह कहना कठिन है कि गोवा प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, उससे जो लोग गैर-कानूनी निर्माण या सुरक्षा मानकों की अवहेलना कर रहे हैं, वे सचेत हो गए होंगे। अपने देश में हर तरह के नियम-कानून हैं, पर उनका पालन करने के लिए न तो नागरिक सचेत रहते हैं और न ही उन पर अमल सुनिश्चित कराने वाले सरकारी विभाग। शायद ही कोई अवैध निर्माण होता हो, जिसमें नगर निकाय के कर्मचारी और अधिकारी पैसे न खाते हों। नगर निकायों में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते कई बार तो लोगों को सही ढंग से निर्माण कराने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। यह भ्रष्टाचार अवैध निर्माण के साथ सुरक्षा उपायों की अनदेखी को बढ़ावा दे रहा है। यह अनदेखी अक्सर जान-माल के नुकसान का कारण बनती है। जब जान-माल का नुकसान हो जाता है, तब भी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती, जिससे उन्हें सबक मिले और अन्य अधिकारियों में डर बैठे।

यह समझा जाना चाहिए कि निर्माण और सुरक्षा उपायों पर अमल की मौजूदा व्यवस्था में जब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, तब तक भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में गोवा नाइट क्लब जैसी दुर्घटनाएं रोकना संभव नहीं। हर वर्ष तमाम ऐसी घटनाएं घटती हैं, जिनमें निर्दोष नागरिक निर्माण और सुरक्षा संबंधी कमियों के कारण जान गंवाते हैं, लेकिन कोई सही सबक सीखने से इन्कार किया जा रहा है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में भूकंप के खतरों को कम करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए जिस तरह यह कहा कि क्या सबको चांद पर बसा दें, उससे भूकंप रोधी उपायों की अनदेखी होने की आशंका है। यह ठीक है कि भूकंप रोधी उपायों की चिंता करना सरकारों का काम है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वे ऐसे उपायों के पालन पर ध्यान दे रही हैं? वे तो सामान्य सुरक्षा उपायों की भी अनदेखी कर रही हैं।

response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-8

प्रश्न:

"21वीं सदी में उभरता हुआ 'नया वर्ल्ड ऑर्डर' भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, बहुध्रुवीयता और शक्ति-संतुलन में परिवर्तन का परिणाम है।"

इस कथन के आलोक में—

1. नए वर्ल्ड ऑर्डर की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए।
2. भारत के लिए इससे उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
3. भारत को इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने हेतु किन नीतिगत कदमों पर बल देना चाहिए?

(उत्तर: 250 शब्द)